प्रभात

इस अंक में ......

★ *भुमकाल के अमर शहीदों को ...* 6
★ *पीजीए के हमले तेज ...* 9
★ *मुशर्रफ की भारत यात्रा ...* 12
★ *महाराष्ट्र का खून चूसता एनरॉन ...* 14
★ *अनाज के ढेरों की बीच ...* 16
★ *उदारतावाद और मनोगवाद पर माओ ...* 22
★ *टर्की का कम्युनिस्ट आन्दोलन ...* 28
★ *सिएटल से लेकर नाइस तक ...* 35

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्स वार] दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष - 14 | **अंक - 3** | **जुलाई - सितम्बर 2001** | **मूल्य - 10 रुपए**

कुरबानी के बिना बदलाव नहीं आएगा!

सबसे महान तो हमारा लक्ष्य है जो कुरबानी की प्रेरणा देता है!!

- कॉमरेड मासा, केन्द्रीय कमेटी सदस्य

[28 जुलाई से 3अगस्त तक 'शहीद सप्ताह' के मौके दण्डकारण्य के किसी स्थान पर छापामारों द्वारा आयोजित एक शहीद-सभा को भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड मासा ने संबोधित किया । पेश है उनके भाषण का संक्षिप रूपान्तरण

- सम्पादक मण्डल]

कॉमरेडों!

हम हर साल 28 जुलाई को शहीद सप्ताह मनाते हैं । इस सप्ताह में हम उन हजारों-हजार शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने सामंतवादी, साम्राज्यवादी और पूंजीवादी शोषण से भारत को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को मुक्त करने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन सबको याद करने के लिए समूची पार्टी पूरे देश में यह *सप्ताह* मनाती है। खासकर एक साल में जो शहीद हुए हैं, उन सबको एक बार याद करेंगे। पूरे भारत में हमारी पार्टी के शहीदों को ही नहीं, बल्कि बाकी क्रांतिकारी पार्टियों के शहीद साथियों को भी, दूसरे देशों में शहीद हुए कॉमरेडों को भी और राष्ट्रीयताओं के आन्दोलनों में शहीद होने वाले कॉमरेडों को भी लाल सलाम पेश करेंगे।

सिर्फ इस एक साल में ही नहीं, हमारी नवजनवादी क्रांति की शुरूआत से लेकर अभी तक जितने कॉमरेड शहीद हुए हैं, उन सभी को यहां याद करेंगे। कॉमरेडों को नक्सलबाड़ी से लेकर अब तक हमारी पार्टी के 9,000 कॉमरेड शहीद हो गए हैं। 1980 के पहले 6,000 कॉमरेड और 1980 के बाद 3,000 कॉमरेड । इन 9,000 कॉमरेडों ने भारत देश को सामंतवादी, साम्राज्यवादी शोषण से मुक्त करने और विश्व समाजवादी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान कुरबान कर दी । इनके अलावा नेपाल में जो हमारा पडोसी देश है, पिछले साढ़े पांच सालों से जारी जनयुद्ध में 1,700 कॉमरेड शहीद हो गए हैं। और पेरू, फिलिप्पीन्स, टर्की (तुर्की) में जहां जनयुद्ध चल रहा है, हजारों कॉमरेड शहीद हो गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीयता आन्दोलनों में, जैसा कि कुर्दिस्तान, फिलिस्तीन, पूर्वी तिमोर आदि में और चेचेन्या में जो पहले चला था, अनगिनत कॉमरेड शहीद हो गए। और हमारे देश में कश्मीर, नगा, त्रिपुरा, असम आदी प्रदेशों जारी राष्ट्रीयता आन्दोलनों में अनेक कॉमरेडों ने इस फासीवादी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों को

हमारी पीढ़ी का बहाया खून
इन सूखे खेतों में पानी बन गया।
बेटो!
इस धरती पर बहा तुम्हारा खून
अब मैं सोखने नहीं दूंगा।
बिछाया हूं यह गमछा नहीं,
ज़ख्मों से भरा दिल है।
सम्भालकर मैं तुम्हारी कुरबानी को
सौंप दूंगा आने वाली पीढ़ियों को!

न्यौछावर किया। हमारी पार्टी इन सभी को शहीद मानती है। जो शोषण के खिलाफ लड़ेगा और जान न्यौछावर करेगा वो सब शहीद ही हैं। उन सभी को हम याद करते हैं।

इस एक साल के दौरान जो साथी शहीद हो गए उन्हें हम फिर एक बार याद करेंगे। हांलकि मुझसे पहले बोलने वाले साथियों ने भी बताया है, फिर भी मैं संक्षेप में बताऊंगा ।

सबसे पहले कॉ. दिवाकर को याद करेंगे जो हमारी पार्टी में .20-22 सालों से काम कर रहे थे। वह साथी आन्ध्रा के गुन्टूर मेडिकल कालेज के छात्र थे और खासकर क्रांतिकारी सांस्कृतिक आन्दोलन के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया । सांस्कृतिक मंच पर वह अच्छे कलाकार तो थे ही, साथ ही, क्रांतिकारी गीत लिखना, ट्रेइनिंग देना, कक्षाएं लेना, सांस्कृतिक आन्दोलन का मार्गदर्शन करना, सांस्कृतिक आन्दोलन को मजबूती प्रदान करना आदि सभी में उनका बड़ा योगदान रहा है। ऐसे कॉमरेड को खोना हमारे लिए बड़ा नुकसान है। वह कॉमरेड नलगोंडा जिले के सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। कॉ. दिवाकर की मृत्यु से भारत की क्रांति को बडा नुकसान हुआ है।

आप सभी जानते ही हैं, कॉ. दीपक ने 25 साल क्रांतिकारी आन्दोलन में काम किया। वह पिछडे हुए दलित समुदाय से आए थे। उन्होंने एकदम निचले स्तर से शुरू करके राज्य कमेटी के नेता के रूप में उभर कर क्रांतिकारी आन्दोलन का नेतृत्व किया। उत्तरी तेलंगाना के स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य के तौर पर रहकर पार्टी कतारों का हौसला बढ़ाया करते थे। इसके पहले उन्होंने दण्डकारण्य में काम किया था। इसके बावजूद कि उन्हें बीमारी से शारीरिक रूप से कई तकलीफें हुई थीं, उन्होंने संघर्ष-क्षेत्र से दूर कभी नहीं रहा। बाद में उन्होंने महाराष्ट्र का राज्य कमेटी सदस्य बन कर ढाई साल काम किया।

और कॉमरेड सूर्यम 20 साल से आदिलाबाद (उत्तरी तेलंगाना) जिले में काम करते रहे। वह आदिलाबाद जिले के सचिव और उत्तरी तेलंगाना के स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य थे। उनका क्रांतिकारी जीवन दस्ता सदस्य से शुरू हुआ था और उन्होंने दुश्मन के खिलाफ किए गए कई हमलों का सकुशल नेतृत्व किया था।

कर्नाटक के क्रांतिकारी आन्दोलन को कॉ राजेश्वरी (सुमति) की शहादत से बडा धक्का लगा। वह मैसूर में सरकारी नौकरी करते हुए क्रांतिकारी आन्दोलन के सम्पर्क में आई थी । वह पिछले 10-11 सालों से पेशेवर क्रांतिकारी बनकर काम करने लगीं। इस दरमियान पार्टी में कार्यरत एक साथी से उनकी शादी हुई। कर्नाटक पार्टी के प्रकाशन विभाग की वह प्रभारी थीं। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन और कंप्यूटर का काम वह संभालती थीं। ऐसे एक कबिल और वरिष्ठ कॉमरेड की शहादत से न सिर्फ कर्नाटक के आन्दोलन को, बल्कि समूची पार्टी को ही गंभीर नुकसान है।

इनके अलावा हम अन्य दो कॉमरेडों को भी याद करें जिन्होंने बाहर के नागरिक अधिकार आन्दोलन में काम करते हुए अपनी जान कुरबान की। उनमें से एक कॉमरेड पुरुषोत्तम लंबे अरसे से आन्दोलन के समर्थन में दृढता से डटे हुए थे। उन्होंने पहले रैडिकल छात्र संगठन में काम किया था। बाद में वकील बने और नागरिक अधिकार आन्दोलन में सक्रिय नेता बने । पुलिस ने उन पर चार बार कातिलाना हमला किए, इसके बावजूद वह टस से मस नही हुए। वह और उनकी जीवन साथी, जो अब महिला चेतना संघ में काम कर रहीं हैं, क्रांति के अच्छे समर्थक थे। पुलिस और गुण्डों ने कॉमरेड पुरुषोत्तम को तलवारों और बन्दूकों से मार दिया। कॉमरेड आज़म अली नलगोंडा जिले के नागरिक अधिकार संगठन के प्रमुख थे। वह भी 15-20 साल से इस आन्दोलन से जुड़े थे। यह जानकर भी कि बाहर काम करने वाले कलाकारों, साहित्याकारों और नागरिक आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को कभी भी पुलिस के छिपे या खुले हमले का शिकार होना पड़ सकता है, उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन का बढ़िया साथ दिया। लेकिन इस बर्बरतापूर्ण राज्य ने उनकी हत्या कर दी । इन दोनों कॉमरेडों के मृत्यु से पार्टी ने अपने दो अच्छे साथी खो दिए।

इनके अलावा एमसीसी के हमलों में बिहार के कुछ कॉमरेड शहीद हो गए हैं। उत्तरी तेलंगाना में प्लाटून कमाण्डर कॉ. महेश भी पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड के दौरान शहीद हो गए। कॉ. महेश पहले निजामाबाद जिले में काम करते थे और बाद में लंबे समय तक पार्टी के तकनिकी विभाग में काम किया था । हाल ही में वह आदिलाबाद जिले में प्लाटून कमाण्डर बनकर गए थे। उनकी मृत्यु से पार्टी ने एक जांबाज़ सेनानी खोया है।

एक साल में और कई कॉमरेड भी शहीद हो गए हैं, लेकिन उनके नाम याद नहीं है। करीबन 200 साथी शहीद हो गए जिनमें किसान-मजदूर संगठन के सदस्यों से लेकर क्रांतिकारियों को भोजन देने वाले आम लोग तक शामिल हैं।

शहीदों को जनता कभी नही भूलेगी। अगर एक गांव में पुलिस एक व्यक्ति को पकड़कर मारती है तो आसपास के गांवों में जनता उस पर गीत लिखकर गाती है और उसको याद करती है। मिसाल के तौर पर नक्सलबाड़ी के समय शहीद हुए शहीदों पर अब तक कई हजारों गीत लिखे गए। श्रीकाकुलम संघर्ष के शहीदों पर भी कई गीत अभी भी गाए जाते हैं। चारु मजुमदार, सरोज दत्ता, पंचादि कृष्णमूर्ति, पंचादि निर्मला, स्नेहलता जैसे नेताओं को ही नहीं कोरन्ना, मंगन्ना जैसे किसानों को भी आज भी याद किया जाता है। 40 साल पहले शहीद हुए कॉमरेडों का नाम आज भी लिया जाता है। हमारी पार्टी के बाहर के शहीदों, जैसे कि भगतसिंह को अभी 70 साल बाद भी पूरा देश याद करता है। उनसे भी पहले के अल्लूरि सीताराम राजू (मन्यम), कोमरम भीम (आदिलाबाद), बिरसा मुण्डा (बिहार) और गुण्डाधुर (बस्तर) को भी, जो अब से कोई 100 साल पहले शहीद थे, आज भी याद किया जाता है। उन पर कई किताबें छपी हैं, कई गीत आए हैं। आम जनता उन्हें देवता मानती है। हजार साल पहले

स्पार्टकस ने विद्रोह किया था उन्हें आज भी याद किया जाता है। हम उन लोगों को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए लड़ाई की थी।

मौत तो मामूली चीज़ है। मानवजाति के इतिहास में देखें तो अभी तक करोड़ों लोग मर गए हैं। कितने करोड़ मरे होंगे हम बता नही सकते। सिर्फ 20वीं सदी की ही बात की जाए, तो इन 100 सालों में सिर्फ युद्धों में 10 करोड़ लोग मारे गए। दो विश्व युद्धों में 4-5 करोड मारे गए। इनसे कई गुना ज्यादा लोग भूख से मर गए। पिछले 100 सालों में युद्धों और दूसरे हमलों में मारे गए लोगों की संख्या से ज्यादा पिछले 15 सालों में भूख और अकाल से मारे गए लोगों की होगी। इसके अलावा हमारे देश में ही टी.बी., मलेरिया, जांडिस आंत्रशोथ जैसी बीमारियों के कारण हर साल अनगिनत लोग मर रहे हैं। लेकिन उन्हें कोई नहीं याद करता। युद्धों में मरने वाले सैनिकों को कोई याद नहीं करता। क्योंकि वे शोषण से मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि शोषण को जारी रखने के लिए सत्ताधारी वर्गों के हुक्मों का पालन करते हुए मरते हैं। लेकिन स्पार्टकस से लेकर कल-परसों की मीराबाई (राजनांदगांव जिले में हाल ही इनकी शहदत हुई) तक के ये जो लोग हैं, इन्हें हजारों साल बाद भी जनता याद करेगी। क्योंकि इन लोगों ने एक मकसद की खातिर, जनता को और देश को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी जानें दीं। इनकी मौत, जैसा कि माओ ने बताया, एवरेस्ट की चोटी से भी भारी है। हमें आज के दिन यह संकल्प लेना है कि शहीदों के मकसद को दृढतापूर्वक पूरा करेंगे।

अब सरकार का हमला जो हम पर हो रहा है, यह आने वाला दिनों में कई गुना बढ़ेगा । हालात आज के जैसे नही रहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी ने आधार-क्षेत्रों का निर्माण करने का कार्यभार तय किया है। देश को साम्राज्यवादी एवं सामंतवादी शोषण से आज़ाद करने लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं। आज हम पुलिस और सीआरपी के साथ लड़ रहे हैं, कल हमें भारतीय सेना के साथ लड़ना होगा। और जरूरत पड़ने पर अमेरिका की सेना (अगर वह आए तो) के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। इसके लिए एक ही रास्ता है - जनता को गोलबंद करना और जनता पर निर्भर रहना। हरेक विषय में जनता के साथ चर्चा करके उनकी राय लेकर उस पर अमल करना। अगर हम जनता से दूर हो जाएंगे तो हमारी हार निश्चित है। जनता के साथ रहेंगे तो कोई भी सेना हमें नहीं हरा सकेगी, चाहे वह कितनी शक्तिशाली सेना भी क्यों न हो।

अभी हमारी ताकत बहुत कम है। हमारी पीजीए भी फिलहाल दुश्मन के मुकाबले में बहुत कमजोर है। हमारी सेना को बढ़ाना है। हम लाखों लोगों को हमारी सेना में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए लोगों की समस्याओं को लेकर उन्हें गोलबंद करना होगा। उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, उन्हें हमारी राजनीति से अवगत कराना चाहिए। उन्हें अपने संगठनों में गोलबंद करके लाखों लोगों को सेना में ला सकेगें। हम समुचित प्रयास करेगें तो यह काम बहुत जल्दी ही कर सकते हैं। तब आधार-क्षेत्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी से युद्ध के लिए बड़ी तेजी से तैयारियां करनी होंगी। जनता को भी तैयार करना होगा। इसके लिए आवश्यक राजनीतिक, सांगठनिक व फौजी तैयारियां भी करनी होंगी।

आने वाले दिनों में सरकारी दमन बढेगा। लेकिन हम इन तैयारियों के साथ उसका मुकाबला निश्चित रूप से कर सकेंगे। इस सिलसिले में कुछ लोग भाग सकते हैं। यहां का स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य करण भाग गया था। उत्तरी तेलंगाना में भी कुछ लोग भाग गए। कल और भी ज्यादा दमन होगा तो कुछ और लोग भाग सकते हैं। निचले स्तर के लोग भी भाग सकते हैं और नेतृत्वकारी लोग भी भाग सकते हैं। मगर ऐसे लोगों को जनता ठुकराती है; नकारती है। जो शहीद हुए हैं वे ही जनता के दिलों में सालों तक रहेंगे।

जो भाग रहे हैं, बाहर उनकी जिन्दगी बहुत ही खराब है। कोई भी आदमी बाहर की जिन्दगी को ठुकराकर कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों आता है? क्रांति करने के लिए क्यों आता है? क्योकि बाहर के जिन्दगी में कुछ है ही नहीं, सिवाए शोषण और झूठे मूल्यों के हर एक व्यक्ति दूसरे को छलना चाहता है। सब नाटकबाजी करते हैं। आप लोग भी रेडियो,पेपर में पढ़-सुन रहे होंगे। हर आदमी दूसरे को नीचे गिराकर ऊपर आना चाहता है। एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। बाहर की जिन्दगी में बहुत गंदगी है। कुछ साथी जिस गंदगी को छोड़कर आए थे, फिर से उसी गंदगी में जा रहे हैं। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हांलकि दमन में कुछ लोग जा सकते हैं। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा लोग पार्टी में, पीजीए में आएंगे। और कॉमरेडों को अच्छा प्रशिक्षिण देने से, उनकी समस्याओं पर ध्यान देने से भागने वालों की संख्या घट जाएगी।

कॉमरेडों!

कुरबानी के बिना समाज में आज तक कोई भी बदलाव संभव नहीं हुआ। मैं सिर्फ सामाजिक क्रांतियों की बात नही कर रहा हूं। दुनिया में नए-नए अविष्कार भी कुरबानी की कीमत पर ही किए जा चुके हैं। गेलीलियो की बात ही ले लें। इसलिए समाज को बदलने के लिए कुरबानी बहुत आवश्यक होती है। रूस और चीन की क्रांतियों में लाखों लोगों ने शहादत दी। हमारी नवजनवादी क्रांति में भी लाखों लोगों को शहादत देनी पडेगी। **यह सच है कि कुरबानी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन सबसे महान तो हमारा लक्ष्य है जो हमें कुरबानी की प्रेरणा देता है।** इसलिए मैं फिर एक बार हमारे प्यारे शहीद साथियों को श्रद्धांजली पेश करते हुए, उनके महान लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए समाप्त करता हूं ।

★ *अमर शहीदों को लाल सलाम !*

★ *शहीदों के मकसद को पूरा करेंगे !*

★ *कॉमरेड चारु मजुमदार अमर रहें !* ❑

श्रद्धांजलि

बीमारी से शहीद हुए कॉमरेड पुन्नेम बुधू को लाल सलाम!

कॉमरेड पुन्नम बुधू का जन्म दक्षिण बस्तर डिवीजन के बासागूडेम रेन्ज के गांव गुण्डम में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह पार्टी के सम्पर्क में रहे और बाल संगठन का सदस्य बनकर काम करते हुए धीरे-धीरे पार्टी सदस्य के तौर पर उभरे। पार्टी द्वारा दी गई हरेक जिम्मेदारी को वह बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा किया करते थे और जनता का कुशल नेतृत्व किया करते थे। जन संगठन के नेता के रूप में उन्होंने जनता के लिए उल्लेखनीय काम किया।

1998 में बासागूडेम इलाके में दुश्मन ने जन जागरण अभियान के नाम पर फिर एक बार भारी दमनचक्र चलाया था। लोगों को गिरफ्तार करना, जेलों में बंद करना, यातनाएं देना, आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करना आदि का दौर चला था। इसके बावजूद बुधू ने हिम्मत न हारी और गांव के मुखियाओं की धमकियों की परवाह न करते हुए संघर्ष में दृढ़ता से खड़े रहे। उन्होंने जनता को भी आत्मसमर्पण न करने को कहते हुए हौसला आफजाई की। जब-जब उसका पार्टी के साथ सम्पर्क टूट जाता था, तब वह बहुत बेचैन हुआ करता था, पार्टी के साथ सम्पर्क कायम करने के लिए हर संभव कोशिश किया करता था। एक पार्टी सदस्य के नाते, सर्वहारा के प्रतिनिधि के नाते वह गांव में लोगों का कुशल नेतृत्व किया करता था। वह बैठकों में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बताता था और अपने साथियों की गलतियों की सटीक आलोचना किया करता था। आदिवासी रिवाजों में मौजूद गलत प्रथाओं के खिलाफ उन्होंने आखिर तक संघर्ष जारी रखा। वह गांव के ग्राम सुरक्षा दस्ते का कमाण्डर चुन लिए गए थे। इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। पार्टी पर, जनता पर उनका विश्वास अटल था। अपने ही गांव के कॉमरेड राकेश दस्ते में भर्ती होकर शहीद हो जाने से भी उन्होंने अपने रास्ते से पीछे मुड़कर नहीं देखा, उस शहीद का मकसद पूरा करने के दौरान ही बीमारी के चलते कॉमरेड बुधू की शहादत हुई। कॉमरेड बुधू को *'स्पेशल जोनल कमेटी'* श्रद्धांजली पेश करती है और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेती है। ❑

समूचे दण्डकारण्य में 'शहीद-सप्ताह' क्रांतिकारी स्फूर्ति के साथ मना!

(28 जुलाई से 3 अगस्त तक "शहीद सप्ताह" के दौरान सभी डिवीजनों में सभाएं, जुलूस, स्मारकों का अनावरण आदि की खबरें आ रही हैं। लेकिन प्रस्तुत अंक की तैयारी के समय तक इनकी सभी रिपोर्टें नहीं पहुंचीं। इसलिए हम सिर्फ माड़ डिवीजन के इंद्रावती इलाके से आई रिपोर्ट ही प्रकाशित कर रहे हैं जो इस अंक की तैयारी के समय तक पहुंची।

सम्पादकमण्डल)

माड़ डिवीजन के इंद्रावती इलाके में जनता ने इस वर्ष शहीद सप्ताह क्रांतिकारी स्फूर्ति के साथ मनाया। 28 जुलाई से पहले ही डीएकेएमएस और केएएमएस के स्त्री-पुरुष कार्यकर्ताओं ने इलाके के कई गांवों में प्रचार अभियान चलाया। भारत की नव जनवादी क्रांति के दौरान शहीद हुए तमाम लोगों को श्रद्धांजली अर्पित करके, शहीदों का मकसद पूरा करने के लिए संघर्ष को दृढ़ता से आगे ले जाने का संकल्प लेते हुए कई गांवों में लोगों ने सभा-जुलूस आदि का आयोजन किया। 28 जुलाई के पहले ही गांवों में पहले से निर्मित शहीदों के स्मारकों को लाल रंग से पुताई की गई। जहां स्मारक नहीं है उन गांवों में पत्थरों या सिमेन्ट से स्मारकों का निर्माण भी किया गया। इस इलाके में कुल 5 स्थानों पर बड़ी शहीद सभाएं आयोजित की गईं। इनमें से कुछ सभाओं में स्थानीय छापामार दस्ता भी उपस्थित था, और कुछ सभाओं का आयोजन डीएकेएमएस और केएएमएस के नेतृत्व में किया गया। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय छापामार दस्ते के अलावा, क्रांतिकारी जन संगठन की सभी इकाइयों, ग्राम सुरक्षा दस्तों और पार्टी संगठनों ने साझा प्रयास किया।

ग्राम नीरुम में आयोजित शहीद-सभा में 500 लोगों ने भाग लिया। किसकल गांव में 1,500, रेखावाया में 650, ताकिलोड में 850 और कोडेम में 650 लोगों ने भाग लिया। इन सभी जगहों में सभा के पहले लोगों ने जुलूस निकाले। जुलूस के दौरान तमाम शहीद साथियों के नाम पर गगनभेदी नारे लगाए गए। बाद में इन जुलूसों ने आमसभा का रूप लिया। सभाओं की शुरूआत शहीदों की याद में मनाई दो मिनट की खामोशी के साथ हुई। और स्थानीय पार्टी नेताओं और जन संगठन नेताओं ने इन सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं में संकल्प लिया गया कि क्रांति को सफल बनाने के प्रयास में शहीद हुए साथियों के अधूरे मकसद को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया जाएगा और हमारे शहीद साथियों की हत्या करने वाली इस व्यवस्था का सफाया करने के लिए संघर्ष को दृढ़ता से जारी रखा जाएगा।

हालांकि शहीद-सप्ताह को विफल करने के लिए पुलिस वालों ने गश्त बढ़ाई और खोजबीन अभियान तेज किए, फिर भी पीजीए की चौकसी ने पुलिस की योजनाओं को नाकाम कर दिया। जिन-जिन गांवों में शहीदों की याद में सभाएं हुईं, उन गांवों में स्थानीय मिलिशिया ने सुरक्षा के सारे प्रबंध अपने कंधों पर लिए। कई गांवों और कस्बों में शहीद-सप्ताह के पहले दिन बन्द का पालन करने का समाचार भी मिला है। ❑

आंध्र के फासीवादी शासक चन्द्रबाबू द्वारा मारे गए नागरिक अधिकार संगठन के नेता

कॉ. पुरुषोत्तम और कॉ. आज़म अली को लाल सलाम!

आन्ध्र के फासीवादी शासक कसाई चंद्रबाबू के हाथ फिर एक बार जन-नेताओं के खून से रंगे हैं। 23 नवंबर 2000 को, हैद्राबाद शहर में दिन-दहाड़े पुलिस द्वारा नियुक्त भाड़े के हत्यारों ने नागरिक अधिकार संगठन के सहायक सचिव, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के वकील कॉ. पुरुषोत्तम की तलवारों और चाकुओं से निर्मम हत्या कर दी। हत्यारे टाटा सुमो गाड़ी में आए थे और कॉ. पुरुषोत्तम जब अपने घर से बाहर निकलकर दुकान से समान खरीद रहे थे तब पीछे से उन पर वार करके उनकी जान ली गई। हमेशा की तरह पुलिस और सरकार ने इस हत्या में अपने हाथ होने से इनकार कर जनता को गुमराह करने नाकाम कोशिश की।

कॉमरेड आज़म अली

कॉ. पुरुषोत्तम 1980 के दशक में अपनी पढ़ाई के दौरान रैडिकल छात्र संगठन के नेता रहे थे। बाद में उन्होंने वकालत पूरी की। वे हमेशा जनता के पक्षधर रहे। जनता के सच्चे दोस्त रहे। वे जहां कहीं भी रहते, जनता के जनवादी अधिकारों के हनन को बर्दाशत नहीं करते थे। जहां कहीं भी झूठी मुठभेड़ होती तो वे सत्यान्वेषक दल के साथ जाते थे और रिपोर्ट तैयार करते थे और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर करते थे। इनके प्रयासों के चलते कई बार अदालत ने लाशों के दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया। उन्होंने न सिर्फ आंध्र में, बल्कि असम, कश्मीर आदि देश के अनेक हिस्सों का दौरा करके मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई घटनाओं को जनता के सामने उजागर किया। इसी वजह से वे शासक वर्गों के लिए आंख का कांटा बने थे। अभी तक सरकार ने उनकी हत्या का कई बार प्रयास किया। एक बार तो सादे कपड़ों में आई पुलिस ने उन्हें बुरी तरह घायल करके मरा समझकर छोड़ दिया था। उससे ठीक होने में उन्हें काफी दिन लगे थे। लेकिन इन तमाम हमलों और धमकियों के बावजूद कॉ. पुरुषोत्तम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिर तक वे एक अदम्य योद्धा की तरह अपने मोर्चो पर डटे रहे। आइए, इस सच्चे जन सेवक की शहादत को लाल सलाम पेश करें और उनके अधूरे सपनों को साकार बनाने का बीड़ा उठाएं।

कॉ. पुरुषोत्तम की हत्या के बाद उठे विरोध की गूंज थमी ही नहीं, फासीवादी चंद्रबाबू ने एक और नागरिक अधिकार संगठन नेता को अपना शिकार बनाया। नलगोंडा जिले के नागरिक अधिकार संघठन नेता कॉ. आजम अली को चन्द्रबाबू द्वारा नियुक्त भाड़े के हत्यारों ने दिन दहाड़े मार डाला। हमेशा की तरह पुलिस ने हत्यारों की धरपकड़ की कोशिश शुरू करने की दिखावे की घोषणा की। कॉमरेड आज़म अली पिछले 15-20 सालों से नागरिक अधिकारों के मार्चे पर काम कर रहे थे। वे अच्छे कवि भी थे। उन्होंने कई अच्छी-अच्छी कविताएं लिखीं। नलगोण्डा जिला एक समय महान तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष का गढ़ था। एक लंबे अन्तराल के बात, खासकर 1990 के दशक की शुरूआत से फिर एक बार क्रांतिकारी आन्दोलन मजबूती से उभरा। उससे पहले नलगोण्डा जिले में संशोधनवादियों का बोलबाला रहा। यहां के किसानों ने कई वीरतापूर्ण संघर्ष किए। अब इस जिले में जनयुद्ध प्रति-क्रांतिकारी ताकतों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहा है। कॉ. आज़म को इन संघर्षों से काफी प्रेरणा मिली और उनकी दृढ़दीक्षा से जिले की क्रांतिकारी जनता को काफी प्रेरणा मिली। जनता पर पुलिसिया दमन का उन्होंने हर समय विरोध किया, इस तरह जिले के किसानों के दिलों में उनकी जगह पक्की हो गई।

नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले नेताओं की हत्या देश में कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में जलील अंद्रबी, असम में परागदास, इस तरह के अनेक लोगों को गिना जा सकता है जिन्हें सरकार मार डाला। आंध्र की पुलिस का नागरिक अधिकार संगठन के नेताओं की हत्या का काफी लंबा रिकार्ड है। 1983 में गोपि राजन्ना नामक वकील को, 1985 में बच्चों के डॉक्टर रामनाथम को, 1988 में जापा लक्ष्मारेड्डी को और वरंगल में ही 1990 के दशक में कॉ. नर्रा प्रभाकर रेड्डी को पुलिस ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मार डाला।

आखिर चंद्रबाबू इनकी हत्या करने पर क्यों तुल गया? विश्व बैंक का पालतू कुत्ता चंद्रबाबू *(शेष पृष्ठ 34 पर ....)*

बस्तर का मुक्ति-संग्राम

भुमकाल के अमर शहीदों को लाल सलाम !

दण्डकारण के गोण्डों की संघर्षमय परम्परा रही है। दण्डकारण गोण्डों की जन्मभूमि है। इतिहास के पुराने ग्रन्थों में बस्तर, चांदा और कोरापुट के जंगलों को दण्डकारण कहा गया है, जबकि आधुनिक इतिहासकार बस्तर और कोरापुट (जयपुर) के जंगलों को दण्डकारण कह रहें हैं। सीमाएं चाहे जो भी कही गईं हों,पर यह कहना बिलकुल सही होगा कि यह पूरा इलाका आदिवासियों का है। वर्तमान संघर्ष की जरूरतों के मद्देनजर हम दण्डकारण में बस्तर, गढचिरोली, भण्डारा, बालाघाट, राजनांदगांव और मलकनगिरी जिलों का जिक्र कर रहे हैं।

मौर्यवंशी साम्राज्य के विस्तारक और युद्धोन्मादी अशोक द्वारा किए गए भीषण युद्ध में एक लाख जनता मारी गई थी, जबकि डेढ़ लाख लोग आहत हुए थे, इतिहास इस बात का साक्षी है। अशोक का युद्ध कलिंगापट्टनम तक चलकर रुक गया। यह कहा जाता है कि नालों की तरह बहते खून को और लाशों को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। लेकिन इतिहास में इस सचाई को समुचित जगह नहीं दी गई है कि बेरोकटोक चल रहे अशोक के युद्ध-रथ के चक्कों को रोकने वाले और कोई नहीं थे, बल्कि दण्डक वनों के 'असभ्य' आदिवासी ही थे। इसका प्रमाण अभी भी इतिहास के आधार के रूप में मौजूद शिला- शासनों से मिलता है जिससे दण्डक वनों के आदिवासियों की ताकत और क्षमताओं का परिचय मिलता है। खरवेल (ई. पू. 186-72) के समय के शिला-शासनों में उन्हें 'अपराजेय' के रूप में चित्रित किया गया था, जबकि उससे पहले ई. पू. 261 के शासनों में उन्हें अविजित पडोसी का नाम दिया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यहां के आदिवासियों को 'आटविक योद्धा' कहा गया है। दण्डकारण्य की जनता के इतिहास का अध्ययन करने पर और कई जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इन लोंगो के संघर्षों को और उनकी जिन्दगियों को जनता के दृष्टिकोण से इतिहास-लेखन में स्थान दिया हो। यह जिम्मेदारी आज क्रांतिकारी आन्दोलन पर ही है।

समय की धारा में कई बदलाव आए है। पुरोगामी समाज के अनुरूप यहां भी प्रशासनिक अंग निर्मित किए गए। एक शब्द में कहा जाए, तो यहां पर सहज विकासक्रम ही चल रहा था, और अंग्रेजों के आगमन से इसने गलत दिशा ली। इतिहासकारों का यह मत है कि दण्डकारण का प्रमुख हिस्सा बस्तर में ई. पू. 600 से 1324 ई. तक आदिवासी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली चला करती थी । इस बात का ठोस प्रमाण मिलते हैं कि यह प्रणाली नलों (ई.पू. 350 से 760) और नागों (ई. पू. 760 से 1324 ई.) तक चली। यह भी कहा जाता है कि नलों से पहले बस्तर के आदिवासी गणतंत्र पर बौद्धों और जैनों का प्रभाव रहा था। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चूंकी शूरू से ही ये आदिवासी लोग छापामार लड़ाई के जानकार थे, इसलिए वे बिना किसी फौज के ही अपनी बस्तर की धरती का बचाव कर सके। लेकिन 1324 में वरंगल के राजा प्रतापरुद्र के छोटे भाई अन्नमदेव ने बस्तर पर आक्रमण करके स्थानीय गोण्ड राजा हरिश्चन्द्रदेव को खत्म करके चक्रकोट के शासन पर कब्जा किया। तबसे लेकर 1774 तक काकतीयों (चालुक्यों) का राज कई घुमाव लेते हुए चलता गया। सदियों से जारी गोण्डों का परम्परागत राज-शासन छिन्न-भिन्न हो गया। समय के साथ-साथ 1369-1534 के बीच तेलंगाना के रेड्डी राजाओं और छत्तीसगढ़ी कालचूरों; 1602-25 के बीच दक्षिणी कुतुबशाही; और 1721- 1731 के बीच रीवा के चंदेलों के हमलों से बस्तर चकनाचूर किया गया था। उसके बाद 1777 में मराठा राजा भोंसले की हुकूमत कायम हो गई। 1853 तक भोंसले राजाओं ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, तो बस्तर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बस्तर का संघर्षमय इतिहास बताता है कि चाहे किसी भी समय किसी भी राजा का बस्तर पर कब्जा हुआ हो, पर वे अपने नीतियों पर नहीं चल सके। इस बात को और भी स्पष्ट रूप से कहना है तो अंग्रेजों ने भोंसले राजाओं को मदद देते हुए जबसे बस्तर पर कब्जा किया, तब से 1947 तक बस्तर की धरती पर कई विद्रोह हुए -

1.	**हलबा विद्रोह**	**1774-74**
2.	**भूपालपट्टनम लडाई**	**1795**
3.	**परालकोट विद्रोह**	**1825**
4.	**तारापुर विद्रोह**	**1842-54**
5.	**मेरिया विद्रोह**	**1842-63**
6.	**महान मुक्ति संग्राम**	**1856-57**
7.	**कोया विद्रोह**	**1859**

'प्रभात' में भूमकाल के बारे में प्रकाशित लेख पढ़कर कई पाठक पत्र लिख रहे हैं। कई गांवों में लोग भुमकाल विद्रोह में शहीद हुए माटी-पुत्रों की यादों को अपने दिलों में अभी भी संजोए हुए हैं और हमें उनके बारे में लिख भेज रहें हैं। हम उन सभी लोगों को अपना अभार व्यक्त करते हैं। हम पाठकों से अपील करते हैं कि भुमकाल विद्रोह के बारे में, उसमें शहीद हुए लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां इकट्ठी करके हमें भेजें।

-सम्पादक मण्डल

8.	**मुरिया विद्रोह**	**1876**
9.	**रानी विद्रोह**	**1878-82**
10.	**महान भुमकाल**	**1910**

विशाल बस्तर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले लोगों ने राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ जब-जब विद्रोह किया, इन विद्रोहों को उनके समुदाय के नाम मिले हैं। इन्हें ये नाम इस ऐतिहासिक परिणाम के फलस्वरूप भी मिले हैं कि समय की धारा में विशाल बस्तर की जनता अलग-अलग कबीलों में बंट चुकी है। दरअसल ये सभी लोग गोण्ड ही हैं। और पाठकों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि इन विद्रोहों के हमें अब जो ब्यौरे मिल रहे हैं, उनका विदेशी इतिहासकारों ने ही संग्रहण किया है। इसलिए यह बहुत संभव है कि विदेशी इतिहासकारों द्वारा संग्रहित जन संघर्षों के इतिहास की कई सीमाएं होती हैं। उनका मूल शासक वर्ग के होने के अलावा, उनकी इस माटी की पैदाइश भी नहीं है। चूकि उन्हें स्थानीय जनता पर और उसकी संस्कृति से कोई वास्ता नहीं रहा और उन्होंने इसे द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से जनता का पक्षधर बनकर जनवादी तरीके से नहीं लिखा है, इसलिए यह जिम्मेदारी अध्ययनशील पाठकों पर रहती है। अपनी सीमाओं के बावजूद इस इतिहास से जनता द्वारा सामना की हुई समस्याओं और उस पर चलाए गए दमनचक्र और अत्याचारों को समझा जा सकता है।

उपरोक्त सभी लड़ाइयां साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाइयां ही थीं। यह कहना कि भारत में अंग्रेजों की नींद हराम करने वाले आदिवासियों में दण्डकारण्य के आदिवासी ही अव्वल रहे थे, वास्तविक इतिहास की व्याख्या ही होगा। लेकिन किसी भी इतिहासकार ने इनके संघर्षों को महत्व देते हुए कभी नहीं लिखा। 'आजादी' के पहले के शासक वर्गों ने लोगों पर गोली बरसाने में बर्बरता बरती है, तो देश के वर्तमान शासकों ने भी कम नहीं किया। बस्तर, गड़चिरोली प्रान्त के जन योद्धाओं ने अंग्रेजी चोर-लुटेरों के खिलाफ जंग का ऐलान करके, पराजय का सामना करके विदेशी गद्दारों द्वारा फांसी की सजाएं भी मुस्कुराते हुए भुगतीं, तो इस देश की सरकार ने उन वीरों को शहीद भी घोषित नहीं किया, इसके बावजूद भी कि इस देश में आजादी की 50वीं सालगिरह और गणतंत्र की 50वीं सालगिरह बदस्तूर मनाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कमीनेपन में भारत के शासक अंग्रेजी शासकों से पीछे नहीं हैं। दिन के उजाले को देखने में असमर्थ हैं ये शासक। उन जन विद्रोहों की रोशनी में ही जारी वर्तमान क्रांतिकारी आन्दोलन शासकों की सत्ता पर ताबडतोड प्रहार करते हुए जब सामंतवाद और साम्राज्यवाद को स्थाई तौर पर नहीं दफनाता है, तब तक उत्पीडित जनता के संघर्षों को और उनके नेताओं को इतिहास में समुचित स्थान नही मिलेगा। हमारे दण्डकारण्य में ये सिलसिला पिछले 20 सालों से जारी है। यह और भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। हमारी इस मार्क्सवादी समझ के मुताबिक कि भारत की आजादी की तमन्ना से साम्राज्यवाद के खिलाफ किए गए तमाम विद्रोह जनवादी क्रांति का हिस्सा ही थे, इन संघर्षों के दौरान धराशायी हुए तमाम जनयोद्धाओं को हम इस अवसर पर श्रद्धांजली पेश करेगें। 1825 के परलकोट विद्रोह में अंग्रेजों का मुकाबला करने वाले आदिवासी नेता गेंदसिह फांसी पर चढ़कर इस प्रांत से सबसे पहले साम्रज्यवाद विरोधी जनयोद्धा के रूप में अंकित हो गए। उसके बाद 1856 में धुर्वाराव 1857 में वीर बाबुराव सडिमेक (गढचिरोली), 1858 में यादवराव, वेंकटराव आदि नेता प्रमुख थे जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था। इनके अलावा कई अन्य अज्ञात योद्धाओं ने भी विदेशी सेनाओं का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। प्रमुख रूप से 1910 के फरवरी माह में 'माडिया राज' की घोषणा करते हुए लोकप्रिय आदिवासी नेता गुण्डाधुर के नेतृत्व में चले महान भुमकाल में कई स्थानीय आदिवासी जनयोद्धाओं ने अपनी जान की कुरबानी दी। कुछ लोगों का मानना है कि हजारों लोंगो ने अपनी जान कुरबान कर दी, जबकि बहुतेरे लोग यह लिख रहे हैं कि सैकडों लोग धराशायी हुए थे। सचाई जो भी हो, पर यह बात स्पष्ट है कि आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ परम्परागत हथियारों से छापामार युद्ध लडते हुए कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए। लेकिन इन विद्रोहों के दौरान शहीद होने वाले चंद जन नेताओं के नाम ही अब उपलब्ध हैं। अंग्रेजी सरकार ने मुट्ठी भर लोगों के मरने की सूचना ही दस्तावेजों में दर्ज करके अपने जन विरोधी चरित्र को साबित किया। हम यह तो जानते ही हैं कि आज भी अंग्रेजों के नक्शेकदम पर चल रही

एक पाठक का पत्र

1910 के भुमकाल में वीरगति को प्राप्त करने वाले बोडकाल के बारे में ....

बोडकाल की शहादत भी उन तथ्यों में से एक है जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह न मिली। माड़ अंचल के काननार गांव का निवासी बोडकाल घर-जमाई बनकर गांव नेलनार गया हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे भुमकाल योद्धाओं के साथ मिलकर वह भी अपना परम्परागत हथियार (फरसा) लेकर संघर्ष में कूद पड़ा था। कोर्रामि-दुरवेडा और परपाकुमारी के निकट हुई लड़ाई में बोड़काल ने एक अंग्रेजी सैनिक को मार गिराकर अमरता को प्राप्त किया। इस शहीद के परिवार जनों ने ये जानकारियां दी। भुमकाल के एक और वीरयोद्धा बोडकाल को श्रद्धांजली पेश करेंगे।

- 'माड़'

भारत सरकार का रवैया भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। इस लडाई में जान गंवाने वाले तमाम योद्धाओं के नाम पर क्रांतिकारी ***'जोहार'*** अर्पित करेंगे। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को सफल बना कर उनके सपनों को साकार बनाएंगे।

1910 की लड़ाई में शहीद हुए जनयोद्धा

(सरकारी आंकड़ों में दर्ज 16-02-1910 की लड़ाई में शहीद हुए लोग)

1) अयतू, 2) एडका, 3) कापा, 4) कोहला, 5) मासा, 6) रेखा, 7) विज्जा, 8) भीमा, 9) हुंगा और 10) वोडी

इनके अलावा सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन रायपुर जेल के दस्तावेजों में सिर्फ 78 लोगों के ही नाम हैं। रायपुर जेल में मरने वाले कैदियों की सूची में कहा गया है कि जेल के दूभर हालत के चलते 27 लोगों की मौत हुई थी। इस सूची पर 07-11-1910 की तारीख दर्ज थी।

1)आंसु, 2) किंदरिया, 3) कोरली, 4) कोला, 5) चंदू, 6) जोगी, 7) तिहरु, 8) डोडा पेद्दा, 9) दलाम, 10) धनिया, 11) नरसिंग, 12) पाण्डू, 13) बलबा, 14) बुदरु, 15) बुधू पेन, 16) भदरु, 17) भागा, 18) बैरा, 19) मंगतू, 20) मुण्डी, 21) मुसमी हडमा, 22) मुलिया, 23) मेस्सा, 24) रुडा, पेद्दा, 25) रूपदर, 26) सोसा और 27) हडमा।

जेल की सजा भुगते लोगों की सूची

उम्र कैद	5
11 साल	1
8 साल	2
7 साल	8
6½ साल	1
5 साल	1
4 साल	2
3 साल	5
2 साल	9
साल भर	17

यह तो किसी को नहीं मालूम कि जेल की सजा भुगतने वालों में कितने लोग शहीद हो गए होंगे। अंग्रेजों के जमाने में इसकी कोई गारन्टी नहीं रहती थी कि जेल भोगने वाले लोगों के जिन्दगी में फिर से बहार आ जाए। इस तरह अंग्रेजों के जुल्मों और अत्याचारों का शिकार होकर गोण्डी जनता के लिए लड़ते हुए बस्तर की धरती पर अपना खून बहा चुके सैकडों नौजवान योद्धाओं को वर्तमान दण्डकारण्य की संघर्षरत जनता विनम्रता से सर झुकाकर श्रद्धांजली पेश करती है। ❑

(.... पृष्ठ 19 का शेष)

इनका असर न के बराबर है।

दरअसल हमारी पार्टी, भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] ने ही ऐसी स्थिति को बदलने के लिए तात्कालिक और दूरगामी समाधान प्रस्तुत किए हैं। इस तथ्य से यह साफ हो जाता है कि जबकि देश के सभी इलाकों में रहने वाले आदिवासी मौजूदा आर्थिक नीतियों के चलते बुरी तरह तबाह किए जा रहे हैं, हमारी पार्टी के प्रभाव वाले इलाकों में वे अपने भाग्य को काफी हद तक बेहतर बना रहे हैं। आज देश के विशाल आदिवासी इलाकों में हजारों आदिवासी भुखमरी, कुपोषण, बीमारी और मौत का सामना कर रहे हैं, लेकिन बस्तर, आदिलाबाद, रायलासीमा, गड़चिरोली आदि इलाकों में नहीं, जहां हमारी पार्टी सक्रिय है।

हमारी पार्टी ने 1997 में बस्तर में और पिछले साल रायलासीमा में यह दिखा दिया कि फौरी तौर पर सूखे और अकाल से कैसे निपटा जा सकता है। वहां सरकारी गोदामों और जमाखोरों पर अकाल हमले किए गए; अमीर लोगों से नकद पैसे और अनाज इकट्ठे किए गए। अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए कई योजनाएं तैयार की गईं।

दूरगामी नजरिए से, बस्तर और अन्य इलाकों में, जहां सरकारी अधिकारियों और मुखियाओं की लूट-खसोट खत्म हो गई, सूदखोरों, सेठ-साहुकारों, डॉक्टरों और दूसरे लोगों का लूटना बंद हुआ, आदिवासियों की सहन शक्ति साफ तौर पर बढ़ गई। क्योंकि वहां पर गांव के भीतर ही स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी कर दी गई है; और प्राथमिक स्वरूप में सहकारी खेती की शुरूआत हो चुकी है। हलांकि वहां पर भी गरीबी है, लेकिन जीवन-स्तर में गिरावट की बात नहीं है, बल्कि असल में सिलसिलेवार सुधार हो रहा है।

इसलिए, आज वे इस आधार के फलस्वरूप उतना कमजोर नहीं हैं जितना दूसरे इलाकों में उनके समकक्ष हैं। साथ ही, चूंकि इन इलाकों में हमारी पार्टी ने पारिस्थितिक दृष्टि से टिक सकने वाली पानी की परियोजनाएं बनाई हैं, इसलिए ये इलाके आसानी से सूखे से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए, जबकि इस वर्ष छत्तीसगढ़ सूखे की चपेट में आया है, लेकिन बस्तर क्षेत्र में इसका प्रभाव कम है। यहां 100 से ज्यादा बांधों का निर्माण किया गया। हमारी पार्टी और जनता जंगल के बचाव पर ध्यान दे रही हैं। किसी भी आपदा से निपटने के लिए यहां के लोग सामूहिक प्रयास करेंगे। इसीलिए जबकि छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों के मुकाबले में यहां से बहुत कम लोगों ने पलायन किया है।

हालांकि हमारी पार्टी ने जो कुछ हासिल किया वह मात्र शुरूआत ही है, फिर भी वह भारत की ग्रामीण आबादी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। वह न सिर्फ सूखे और अकाल का सामना करने का रास्ता दिखाता है, बल्कि उनकी पुनरावृत्ति को कम करने का रास्ता भी दिखाता है। वह यह दिखाता है कि स्थिति का बिगड़ना अवश्यंभावी नहीं है। वह भविष्य की ओर रास्ता दिखाता है - कृषि क्रांति का रास्ता। ❑

आन्ध्र, उत्तरी तेलंगाना, आन्ध्र-उड़ीसा सीमांत इलाका और दण्डकारण्य में

जनयुद्ध को आगे बढ़ाते हुए पीजीए के हमले तेज!

"जनयुद्ध को तेज करो–आधार क्षेत्र कायम करने के लिए कदम बढ़ाओ " यह था हाल ही मे संपन्न पार्टी की 9वीं कांग्रेस का प्रमुख नारा। कांग्रेस द्वारा उठाए कार्यभारों और किए प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए पीजीए ने पूरे जोशोखरोश के साथ प्रयास शुरू कर दिए। आन्ध्र, उत्तरी तेलंगाना, आंध्र-उड़ीसा सीमांत इलाका, दण्डकारण्य और बिहार के जंगे मैदानों से लगातार पीजीए की हथियारबंद कार्यवाहियों की खबरें मिल रही हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा साझे तौर पर छेड़े गए प्रथम देशव्यापी आक्रामण हमले को मात देने के कांग्रेस के फैसले पर अमल करते हुए पीजीए के छापामारों ने अपनी जान की बाजी लगाकर सरकार के पुलिस बलों को, उसके दलालों को और लुटेरे राजनेताओं को धूल चटाने का सिलसिला शुरू किया। हम प्रस्तुत अंक में कुछ कार्यवाहियों का ब्यौरा ही पेश कर पा रहे हैं क्योकि हमें अभी विस्तृत रिपोर्टों का इंताजार है।

पुलिसिया 'कोवर्टवार' का मुंहतोड़ जवाब

उत्तरी तेलंगाना में पीजीए ने दुश्मन के 10 दलालों का सफाया करके शासक वर्गों के दिलों में आतंक भर दिया

पिछले तीन दशकों से बिना रुके जारी उत्तरी तेलंगाना आन्दोलन को कुचलने के लिए शासक वर्गों ने अभी तक कई बार क्रूरतम दमन अभियान और षड़यंत्रपूर्ण चालें अपनाई। लेकिन उत्तरी तेलंगाना की जनता और उसका नेतृत्व कर रही हमारी पार्टी ने इन सभी कोशिशों का पलटकर जवाब दिया और जनयुद्ध को दृढ़ता से आगे बढ़ाया। झूठी मुठभेड़ों में सैकड़ों युवाओ की हत्या, सामूहिक गिफ्तारियां, संपत्तियों का नाश, बलात्कार, यातनाएं–इस तरह की दमनात्मक कार्यवाहियां जनता को संघर्ष-पथ से अलग नहीं कर सकीं। साम्राज्यवादी और उनके गुप्तचर संगठन खासकर आन्ध्रप्रदेश में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं।

इसके अंतर्गत, पुलिस पिछले एक दशक से 'कोवर्टवार' नामक (अपनी उंगली से अपनी आंख फोड़ने वाली) एक घिनौनी नीति लागू करती आ रही है। 1993 मे कत्तुला सम्मय्या नामक एक दस्ता सदस्य को पुलिस ने अपना दलाल बना लिया था जिसने रात के अंधेरे में दस्ता कमांडर कॉ. भूपति और अन्य साथियों की हत्या कर दी। इस घटना के साथ ही आंध्रप्रदेश में क्रांतिकारी आन्दोलन के खिलाफ जारी पुलिसिया दमन के इतिहास में एक काला अध्याय शुरू हो गया। उसके बाद घटी चंद दूसरी घटनाओं में पार्टी को, जनयुद्ध को काफी नुकसान हुआ। 1999 में गोविंद रेड्डी नामक कोवर्ट (गद्दार) के जरिए कॉ. श्याम, कॉ. मुरली और कॉ. महेश की हत्या की घटना इस तरह की सभी घटनाओं में से सबसे दुखद थी। इसके बाद दण्डकारण्य में भी खासकर गढ़चिरोली डिविजन में पुलिस कोवर्ट की कई कोशिशें की। लेकिन जनता की सतर्क निगाहों और छापामार दस्तों की सावधानी से ऐसी कोशिशें बुरी तरह विफल हुई। माड़ डिविजन में हमें कॉ. राकेश की शहादत के रूप में कीमत चुकानी पड़ी। बाद में पार्टी ने इसकी समीक्षा करके सही निर्देश तैयार करके छापामार दस्तों को भेजे। खासतौर पर जनता पर निर्भर रहते हुए दुश्मनों का पता लगाना, भर्ती के लिए तयशुदा नियमों का कड़ाई से पालन आदि कदम उठाए गए। इसके बावजूद जब भी नियमों का पालन करने में जहां कहीं भी ढील बरती जाती है तो दस्तों मे दुश्मन के दलाल घुस जाते हैं। जनयुद्ध को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे दलाल पार्टी में, दस्तों में, जन संगठनों में नहीं घुस सकें, इसके लिए सभी आवश्यक राजनीतिक व फौजी कार्यवाहियां तेज करनी होंगी।

बहरहाल, पीजीए ने उत्तरी तेलंगाना के निजामाबाद जिले के दस्तों और जन संगठनों में मौजूद दुश्मन के कुछ कोवर्टों का पता लगाकर उन्हें कड़ी सजा दी। 16 जून को पीजीए ने एक साथ ऐसे दस गद्दारों का सफाया करके शासकों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा कर दी। पीजीए के एक प्लाटून सदस्य अजय उर्फ बोज्जन्ना की गतिविधियों पर जिम्मेवार कॉमरेडों ने कुछ दिनों से नजर रखे हुए थे। उसे करीमनगर जिले के प्लाटून में पिछले साल तबादला कर दिया गया था। अजय को गिरफ्तार करके पूछताछ करने पर उसने 24 अन्य लोगों के नाम बताए। इनमें से कुछ लोग दस्तों में सदस्य के तौर पर थे। और बाकी गांवों में रहकर मुखबिरी करने वाले थे। पुलिस ने पहले ही इन्हें प्रशिक्षण देकर लाखों रूपए का प्रलोभन देकर, सेल फोन आदि मुहैया करवाकर जन संगठनों और दस्तों में भर्ती करवाया। दस्तों में रहकर पार्टी के नेताओं, पीजीए के कमांडरों की हत्या करना और समय-समय पर पुलिस को दस्तों के ठिकानों की सूचना देना, ताकि मुठभेड़ हो जाए, इनका काम था। ये लोग उत्तरी तेलंगाना के पार्टी नेता कॉ. आजाद और कुछ जिला कमेटी नेताओं की हत्या करने की ताक में थे। इनकी गद्दारी के चलते ही पिछले साल सितंबर माह में पुलिस ने पार्टी के अधिवेशन पर हमला करके कॉ.विनोद (दीपक) सहित कुछ अन्य योद्धाओं की हत्या की थी।

अजय की सूचना पर पीजीए के योद्धाओं ने दस्तों से गांवों में छापा मारकर 16 गद्दारों की गिरफ्तारी की। इनकी पिटाई करने से सभी ने अपने अपराधों को कबूल किया। बाद में कॉ. आजाद

ने छापामारों के एक अस्थाई शिविर में पत्रकार सम्मेलन बुलाया और इस वाकिए के बारे में पत्रकारों को पूरा ब्यौरा दिया। खुद इन गद्दारों ने भी पत्रकारों को बता दिया कि वे क्या करना चाहते थे और पुलिस ने उन्हें क्या-क्या दिया।

इनमें से ऐसे छह लोगों को जिनके अपराध हल्के थे, को मामूली पिटाई करके छोड़ दिया गया और 10 को गोली मार दी गई। इस घटना से जहां क्रांतिकारी पांतों ने राहत की सांस ली क्योंकि इन गद्दारों का पर्दाफाश होने से आन्दोलन को हो सकने वाला एक जबर्दस्त नुकसान टल गया, वहीं पुलिस पागलों की तरह बौखला गई क्योंकि उसके इतने सारे दलालों का एक साथ सफाया हो गया। साथ ही इस घटना से हमें यह चेतावनी भी मिलती है कि गद्दारों के प्रति सावधानी बरतने में कोई ढिलाई न बरती जाए। ★

वरंगल जिले के एटूरनागारम पुलिस थाने पर पीजीए का हमला

तीन पुलिस वाले मरे और कई घायल

जुलाई के आखरी सप्ताह में पीजीए के छापामारों ने एटूरनागारम थाने पर भारी हमला किया। इस थाने मे स्थानीय पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कोई 70 जवान तैनात हैं। संघर्ष इलाके के बीचोंबीच स्थित इस थाने में सुरक्षा का भारी बंदोबस्त रहता है। दर्जनों छापामारों ने दो ट्रक्टरों में विस्फोटक भरकर थाने के नजदीक तक पहुंचाया। पुलिस वाले कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि दोनों तरफ से छापामारों ने बमों का विस्फोट किया। उसके तुरंत बाद सभी तरफ से थाने पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 3 पुलिस वाले, जिनमें सीआरपीएफ के दो जवान शामिल थे, मौके पर ही मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। छापामारों की ओर से किसी के हताहत होने का कोई समाचार नहीं मिला। संख्या और सुरक्षा की दृष्टि से इस मजबूत थाने पर किए हमले में हालांकि पीजीए को आंशिक सफलता मिली है, लेकिन इससे *पीपुल्सवार शक्तिविहीन हो चुकी है* कहकर बकवास कर रहे शासकों और उनके भाड़े के टट्टू पुलिस अफसरों के मुंह पर जैसे चपत लग गई। ★

उड़ीसा के कलिमेला और मोटु थानों पर पीजीए के सफल हमले!

दो साहसी जन-नायक कॉमरेड क्रांति रणदेव (प्रकाश) और कॉमरेड परमेश्वर (विश्वनाथ) की शहादत की कीमत पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा पीजीए के कब्जे में

8 अगस्त, 2001 को रात के 8-15 बजे पीजीए के छापामारों की दो अलग-अलग टुकड़ियों ने उड़ीसा राज्य के कलिमेला और मोटु (जिला मलकनगिरी) पुलिस थानों पर हमला किया। दर्जनों छापामारों ने इन थानों को चारों तरफ से घेरकर बमों और गोलियों से हमला शुरू किया। क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा छेड़े गए देशव्यापी आक्रामक हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए जनयुद्ध को तेज करने के लक्ष्य के तहत किए गए इन हमलों के पीछे हथियार जब्त करना भी पीजीए का इरादा रहा। कलिमेला थाने पर किए गए हमले में थानेदार, एक हवलदार और एक पुलिस जवान की मृत्यु हुई जबकि 10 पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। छापामारों ने बिजली सी तेजी से, असीम पराक्रम का परिचय देते हुए कुछ ही घण्टों में सभी पुलिस वालों को निष्क्रिय बना दिया। कुछ देर तक मुकाबला करने के बाद बचे हुए पुलिस वालों ने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण किया। पीजीए के योद्धाओं ने आत्मसमर्पण करने वाले पुलिस वालों को कोई हानि नहीं पहुंचाने की हमारी पार्टी की नीति का पालन करते हुए सभी को जनयुद्ध की राजनीति समझाकर छोड़ दिया। कलिमेला थाने से जब्त किए गए हथियारों का ब्यौरा इस प्रकार है -

एके-47 :	*4*
एसएलआर :	*4*
स्टेनगन :	*4*
.303 रायफलें :	*22*
दो इंच मोर्टार :	*1*
एलएमजी:	*1*
और गोलियां :	*4,000*

एक साथ दोनों थानों पर हमला करने की योजना के तहत मोटु पर किए गए हमले में पीजीए को आंशिक सफलता मिली है। छापामारों ने इस थाने के सहायक थानेदार और एक जवान का सफाया कर दिया। मोटु से लगे छत्तीसगढ़ राज्य के कोंटा में तैनात पुलिस वालों ने थाने से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की, पागलों की तरह रात भर बेकार फायरिंग करते रहे। मोटु थाने में तैनात पुलिस वालों पर काबू करने के प्रयास में **पीजीए के योद्धा कॉमरेड क्रांति रणदेव (प्रकाश) और कॉमरेड परमेश्वर (विश्वनाथ) की मृत्यु हुई**। इसके बाद छापामारों ने हमले को राका और पीछे हट गए। जनयुद्ध को आगे बढ़ाकर देश को सामंती और साम्राज्यवादी शोषण से मुक्त कर नव जनवादी व्यवस्था स्थापित करने के महान लक्ष्य को सफल बनाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लुटेरे शासकों के भाड़े के टट्टुओं से जूझते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले इन जानबाज योद्धाओं को 'दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी' नम्रतापूर्वक श्रद्धांजली पेश करती है। साथ ही, इन हमलों में भाग लेकर दुश्मन को धूल चटाकर, भारी मात्रा में हथियार जब्त करने में साहस व पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले पीजीए के कमाण्डरों और सैनिकों का तथा इन हमलों के लिए अपना सहयोग देने वाली क्षेत्र की उत्पीड़ित जनता का हम क्रांतिकारी अभिनन्दन करते हैं। ★ *(शेष पृष्ठ 27 पर....)*

झूठी आजादी का पर्दाफाश करो !
असली आजादी के लिए संघर्ष करो !!

15 अगस्त 1947 के बाद भारत में अंग्रेजों की सीधी हुकूमत ही खत्म हुई थी। वास्तव में अंग्रेजी शोषण यथापूर्व जारी है। 1947 से पहले भारत को अंग्रेजी ही अपने मन माफिक लूटा करते थे। लेकिन 1947 के बाद से सभी प्रमुख साम्राज्यवादी देशों ने हमारे देश को लूटने के लिए होड़ सी लगाई है। इसलिए यह झूठी आजादी है। इस झूठी आजादी से भारत को कोई फायदा तो नहीं हुआ, उलटा उसे अब एक ब्रिटेन की जगह कई साम्राज्यवादियों द्वारा शोषण शिकार होना पड़ा है।

इसलिए अंग्रेजों द्वारा भारत को छोड़कर पांच दशक बीत जाने के बावजूद यह अभी भी एक पिछड़ा हुआ देश ही है। लेकिन भारत के दलाल शासक पिछले पांच दशकों से ज्यादा समय से जनता को आजादी के बारे में झूठ बताते आ रहे हैं। साम्राज्यवादी देशों को अपनी सेवाओं के बारे में और भारत को उन्हें बेच डालने के बारे में छुपाते आ रहे हैं। लेकिन यह छुपाए न छुपने वाली सचाई है। आजादी को लेकर भले ही ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन कर्ज, पिछड़ापन, भूखमरी, आत्महत्या, घोटाला, बेरोजगारी, गरीबी, साम्राज्यवादियों की सत्ता आदि बार-बार याद दिलाते हैं कि भारत को अभी आजादी नहीं मिली है।

साम्राज्यवाद के गहराते संकट की पृष्टभूमि में, 1990 के दशक से शुरू हुए आर्थिक सुधारों ने साम्राज्यवादी देशों को भारत को लूटने में बचे अवरोधों को भी हटा दिया है। खुल्लम-खुल्ला लूटखसोट के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए। इसके बाद देशवासियों की जिन्दगी और भी दूभर हो गई। कई उद्योगों में ताले लग गए। और लाखों मजदूर बेघर हो गए। सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण करके लाखों मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। जनता को सीमित मात्रा में ही सही राहत पहुंचाने वाली सब्सिडियों पर सरकार ने भारी कटौती की। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जैसे साम्राज्यवादी संस्थानों के इशारे पर चलते हुए सभी पार्टियों की केन्द्र सरकारों ने इन नीतियों पर बराबर अमल किया। जहां 1980-81 में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सब्सिडियां कुल खर्च का 9.2 प्रतिशत रहीं, वहीं 1999-2000 तक 8.4 प्रतिशत तक घट गईं।

पिछले चार पांच वर्षों से देश के कई हिस्सों में किसानों की आत्महत्याओं का दौर शुरू हुआ जोकि आर्थिक सुधारों का सबसे बुरा नतीजा है। कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश ने किसानों पर कहर बरपा है। नकली बीजों, नकली कीटनाशक दवाओं, कृषि में बड़ी पूंजी, आकाल या कम वर्षा के चलते पैदावार में गिरावट, फसलों की खरीद न होना, वाजिब दाम न मिलना, कर्जों का बोझ आदि कारणों से किसान आत्महत्या की शरण ले रहें हैं। कृषि उत्पादनों की विकास-दर ने भी उलटी दिशा पकड़ी।

आजादी के बाद इन 54 सालों में बेरोजगारी लगातार बढ़ती रही है। वर्ष 2000 के आकड़ों के मुताबिक सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत ही खर्च कर रही है, जबकि इससे तीन गुना ज्यादा राशि सेना पर खर्च करती है। स्वास्थ्य सुविधा के मामले में भारत का स्थान पूरे विश्व में 112वां है। भीषण गृहयुद्ध झेल रहे श्रीलंका, फ़िजी, कज़ाकिस्तान जैसे पिछड़तम देशों से भी काफी नीचे।

इन सब का कारण यह है कि साम्राज्यवादी भारत के दलाल शासकों को सामने रखकर देश को मनमानी लूट रहे हैं। लेकिन हैरान की बात यह है कि देश के दलाल शासक आर्थिक सुधारों पर सही अमल न होने के कारण ही देश का विकास अवरुद्ध हो गया कहकर झुठला रहे हैं। उससे भी हैरान की बात तो यह है कि वे कह रहे हैं कि देश को मौजूदा तीव्र आर्थिक संकट से उबारने के लिए दूसरी पीढ़ी के सुधारों पर तत्काल अमल किया जाए। साम्राज्यवादी शोषण को छुपाते हुए बेसिर पैर के तर्क पेश कर रहे हैं।

1990 दशक की शुरूआत से शुरू किए गए सुधारों के बारे में यह प्रचार किया गया था कि भारत में मौजूद सभी बीमारियों के लिए वही राम-बाण जैसी दवा है। लेकिन सच तो यह है कि इन 10 सालों में देश ने किसी एक भी क्षेत्र में तरक्की नहीं की। कृषि एवं उद्योग का दिवालिया निकल चुका है। आर्थिक मंदी छाई हुई है। जिस सेवा क्षेत्र के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था वह अब पूरी तरह चौपट हो गया।

सूचना प्रौद्योगिकी को भी आसमान पर चढ़ाया गया था लेकिन यूटीआइ के ताजे घोटाले ने उसकी हवा निकाल दी और छोटे निवेशकों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। 1947 के पहले भारत का विदेशी ऋण शून्य था लेकिन आज 5 लाख करोड़ रूपए तक हो गया। घरेलू और विदेशी कर्जों को मिलाने पर 67 लाख करोड़ रूपए होंगे। इन 10 सालों में व्यापार घाटा लगातार बढ़ता रहा। फिर भी इसके सही कारण न बताते हुए दलाल शासक सुधारों पर अमल में धीमी गति को और दूसरी पीढ़ी के सुधारों पर अमल में देरी को कारण बता रहे हैं।

साम्राज्यवादी शोषण, खासकर अमरीकी साम्राज्यवादी शोषण और उनके दलाल नौकरशाही पूंजीपति और जमींदारों के द्वारा जारी लूट-खसोट ही देश में व्याप्त बदहाली की असली जड़ हैं। इसलिए भारत के दलाल पूंजीपति और जमींदार शासक वर्गों तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए इनकी साजिशों को नकाम करने से ही भारत में एक सच्चा नव जनतंत्र कायम हो सकता है। तभी भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। ❑

मुशर्रफ भारत क्यों आया?

कश्मीर की जनता कश्मीर की आज़ादी के लिए दिनोंदिन ज्यादा जुझारू संघर्ष कर रही है। केंद्र सरकार की तमाम कत्लेआमों और दमन की नीतियां विफल हो चुकी हैं। लाखों संख्या की भारतीय सेना कश्मीर के संघर्षों को नहीं रोक सक रही है। कश्मरी जनता के संघर्षों ने न सिर्फ भारत के सैन्य बलों पर कड़े प्रहार किए, बल्कि कश्मीर में युद्ध पर सरकारी खर्च को कई गुना बढ़ाया। सरकार के लिए कश्मीर में जारी युद्ध से न सिर्फ सैनिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही, देश के विभिन्न इलाकों में, कई उतार-चढ़ावों के बावजूद विभिन्न हथियारबंद लड़ाइयां बढ़ रही हैं। सरकार को यह एहसास हो गया कि एक तो कश्मीर में फौजें थक गई हैं और दूसरा, इन सभी संघर्षों का एक साथ मुकाबला करना भी मुमकिन नहीं होगा। इसी पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने यह योजना तैयार की है कि उनमें से जहां तक संभव है कुछ को तटस्थ बनाकर, एक के बाद एक संघर्ष को कुचल दिया जाए। इसके अंतर्गत ही 19 नवंबर 2000 को सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की। कश्मीर में संघर्षरत तमाम दलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया।

यानी भारत सरकार एक ओर सैनिक लड़ाई के जरिए जनता के संघर्ष को कुचलने की कोशिश करते हुए ही, साथ-साथ संघर्ष विराम और बातचीत की कार्यनीति अपनाई ताकि कश्मीरी जनता को गुमराह किया जा सके और संघर्षरत दलों में फूट डाली जा सके। शुरूआत में ऐसा लगा भी था कि कश्मीर की आजादी की लड़ाई में फूट डालने में सरकार को कुछ सफलता मिली है। लेकिन भले ही संघर्षरत गुटों के बीच मतभेद और फूट के कुछ आसार नजर आए हों, लेकिन कुल मिलाकर कश्मीरी जनता ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित झूठे संघर्ष विराम का मुंहतोड़ जवाब दिया। संघर्ष को बिना रुके जारी रखकर जनता ने केंद्र सरकार के अनुमानों और सपनों को चकनाचूर कर दिया।

झूठे संघर्ष विराम का दांव पिट जाने के बाद से सरकार ने फिर एक नाटक शुरू कर दिया। जहां एक ओर उसने 23 मई 2001 को कथित संघर्ष विराम को वापस लेकर सेना को कश्मीरी जनता के खिलाफ और भी क्रूरता से उकसाया, वहीं दूसरी ओर उसने पाकिस्तान के शासक जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बातचीत की पेशकश करते हुए एक के बाद एक कई आमंत्रण भेजे। इस चाल के पीछे सरकार की असली मंशा यह थी कि एक ओर कश्मीरी जनता पर दमन जारी रखते हुए ही दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से मिल रहे नैतिक और पादार्थिक समर्थन को रोक सकने का मौका ढूंढ़ा जाए। दक्षिण एशिया के सभी बाजारों में अपनी धाक जमाने की ताक में बैठे भारत के दलाल पूंजीपति शासक वर्गों को पाकिस्तान के बाजार में घुसने का मौका मिल सके, यह भी इस चाल के पीछे एक खास वजह थी। भारतीय शासक वर्गों की यह दीर्घकालीन योजनाएं भी हैं कि पाकिस्तान के बाजार में घुसकर, उस पर अपना सिक्का जमाकर, यानी व्यापार की लेन-देनों और आर्थिक समझौतों की लौह मुट्ठी में पाकिस्तान के शासक वर्गों को दबोचकर कश्मीर की जनता को मिल रही सहायता को समाप्त किया जाए। (इसीलिए मुशर्रफ की यात्रा के मौके पर भारतीय शासक वर्गों ने इसी मुद्दे का प्रचार किया और इसे ही ज्यादा महत्व दिया।) इसके अलावा वाजपेयी की अपनी मजबूरियां भी इसकी अन्य वजहें हैं। मसलन, विधानसभाओं के चुनावों में राजग का खराब प्रदर्शन और तहलका कांड से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की चूलें हिलना आदि।

मुशर्रफ देशीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कई समस्याओं से जूझ रहा था। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता की समस्या थी। अमरीका समेत विश्व समुदाय उनकी जमकर निंदा कर रहा था कि उसने अपने देश में लोकतंत्र का गला घोंट डाला है। इसी पृष्ठभूमि में, भारतीय शासक वर्गों ने सोचा कि मुशर्रफ को मान्यता दी जाए, तो उसे अपने अनुकूल मनवाने के अवसर मिल सकेंगे। साथी ही, पाकिस्तान के बाजार में पैठ भी बनाई जा सकती है। इसीलिए तत्काल ही वाजपेयी ने, जो एक समय यह उलटा सवाल पूछा था कि ***'असल में पाकिस्तान में जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही कहां है जिसके साथ बातचीत की जाए?'***, अपने अंदाज में हॉटलाइन पर मुशर्रफ को भारत आने का निमंत्रण देते हुए **'प्रेसिडेन्ट साहब'** कहकर बुलाया जिससे खुद मुशर्रफ भी आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि वह तब तक राष्ट्रपति नहीं बना था।

भारत के निमंत्रण से मानो जनरल मुशर्रफ की किस्मत का ताला ही खुल गया। देश में कायदे से चुनी गई सरकार को बरखास्त करने के तुरन्त बाद जनता ने बड़े पैमाने पर विरोध नहीं किया था। क्योंकि तब तक नवाज़ शरीफ के शासन में आर्थिक-राजनीतिक संकट बढ़ गया था जिससे जनता काफी नाराज़ थी। सेना द्वारा सत्ता पलट दी जाने के बावजूद जनता को कोई चिंता नहीं हुई, और यह उम्मीद भी जगी थी कि कम से कम फौजी शासन के तहत आर्थिक-राजनीतिक हालत सुधर जाए। लेकिन पाकिस्तानी जनता को यह समझने में कोई देर नहीं लगी कि मुशर्रफ के शासन में भी कोई चमत्कार नहीं होने वाला है और सैनिक शासन के अंत होने के कोई आसार भी नहीं हैं। ऐसी हालत में पाकिस्तान में फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुईं। जनतंत्र की मांग करते हुए लोगों द्वारा आन्दोलन खड़े किए जाने लगे हैं। घरेलू मोर्चे पर वह गहरा राजनीतिक-आर्थिक संकट में फंसा है। देश पर 37 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। बैंकिंग ढांचा ढहने के कगार पर है। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर अनुमानित 4.5 फीसदी की जगह 2.6 फीसदी है। मुद्रास्फीति दो अंकों तक पहुंच जाने से और देश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति की वजह से खासी गरीबी में रह रहे 4 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जीवनयापन बेहद मुश्किल हो गया है। आर्थिक मजबूरियों के मद्देनजर मुशर्रफ को पाकिस्तान के रक्षा बजट में 27.4 फीसदी

की कटौती की घोषणा करनी पड़ी। आर्थिक मुद्दों को लेकर भी जन-आन्दोलन बढ़ गया। समूचे पाकिस्तान में अराजकता सी फैल गई। इस पृष्ठभूमि में मुशर्रफ को भारत का न्यौता डूबते को तिनके का सहारा जैसा मिला। तुरन्त ही मुशर्रफ ने भारत यात्रा स्कीकार की, बिना किसी एजेन्डा के ही।

पाकिस्तान को मालूम है कि भारत की क्या मजबूरियां हैं। भारत को मालूम है कि पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं। दोनों की मजबूरियां क्या हैं अमरीका को मालूम है। इसलिए अमरीका अपने साम्राज्यवादी हितों के मद्देनजर दोनों से बंदर-नाच करवा रहा है। वह कश्मीर की समस्या को लेकर अपनी अन्तरराष्ट्रीय पुलिस की भूमिका अदा करते हुए दोनों देशों पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर रहा है। पूरे दक्षिण एशिया में विकसित हो रहे जनवादी आन्दोलनों और राष्ट्रीयता आन्दोलनों से अमरीका चिंतित है। अमरीका की चिंता इस बात को लेकर भी है कि भारत-पाक की शत्रुता के चलते क्रांतिकारी आन्दोलनों और राष्ट्रीयता आन्दोलनों के लिए अनुकूल हालत बन रही है। अमरीका इससे वाकिफ है कि इन आन्दोलनों का विकास अंततः उसके साम्राज्यवादी हितों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए अमरीका ने भी इन दोनों देशों पर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाए रखा है जोकि खुद मुशर्रफ ने भी स्वीकार किया।

और जैसे ही वाजपेयी ने जनरल मुशर्रफ को निमंत्रण भेजा, भारत के अखबारों, टीवी और रेडियो ने इस खबर को आसमान पर उठाया। कश्मीरी जनता पर जारी कत्लेआमों को इस खबर ने दबाने की कोशिश की। भारत के शासक वर्गों ने सुनियोजित रूप से इस प्रचार को बढ़ावा दिया ताकि देश में बढ़ रहे आर्थिक-राजनीतिक संकट से जनता की दृष्टि को भटका दिया जाए। इसलिए निमंत्रण भेजने के दिन से लेकर मुशर्रफ की यात्रा पूरी होने तक अखबारों और अन्य मीडिया ने लोगों को इसी खबर को रोज-रोज नए-नए रंग चढ़ाकर परोसा। मुशर्रफ की भारत यात्रा को लेकर कश्मीर में संघर्षरत दलों के बीच पनपे विवादों और मतभेदों का भी अखबारों ने तिल को ताड़ बनाकर प्रचार किया।

इस शोरगुल के बीच ही मुशर्रफ ने चुपचाप खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। दुनिया स्तब्ध रह गई। कई देशों ने मुशर्रफ की निंदा की। खुद पाकिस्तानी जनता ने मुशर्रफ की भर्त्सना की। लेकिन अजीबोगरीब व आश्चर्यजनक ढंग से भारत ने जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार किया जोकि तब तक उसे पाकिस्तान की जनता के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने से इनकार करता रहा। भारत सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय का विरोध और पाकिस्तानी जनता की जनवादी आकांक्षाओं को ताक पर रखकर मुशर्रफ को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी। इस तरह मुशर्रफ को रिझाकर कश्मीर के संघर्ष को कुचल डालना भारतीय शासक वर्गों की ख्वाइश थी। भारतीय शासक वर्गों को यह उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि मुशर्रफ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर कई समस्याओं का सामना कर रहा था।

भारतीय शासक वर्गों की इस आशा का तथा कश्मीरी जनता के संघर्ष को कुचलने में उनकी नाकामी का मुशर्रफ ने खूब फायदा उठाया। इसलिए जबसे उसने भारत का निमंत्रण स्वीकार किया तबसे हर दिन तरह-तरह के वक्तव्य देने लगा। आखिरकार उसने इसका भी खुलासा किया कि इस निमंत्रण और बातचीत की पेशकश के पीछे अमरीका का हाथ है। अमरीका की भूमिका को उजागर करके उसने तब तक भारत की पहलकदमी को लेकर बांधे जा रहे प्रशंसा के पुलों को ढहा दिया। एक ओर उसने यह दोहराते हुए ही कि वह पूर्व निश्चित फैसलों और मतों से नहीं बल्कि खुले दिमाग से भारत जा रहा है, कश्मीर को लेकर तथा हुर्रियत की भूमिका को लेकर ऐसे वक्तव्य दिए जो भारतीय शासक वर्गों के गले नहीं उतरे। एक शब्द में कहा जाए तो वह दीवार पर बैठी बिल्ली जैसा बरताव किया। एक साथ उसने ऐसे वक्तव्य दिए जिससे कश्मीर के संघर्ष का समर्थन करने का अर्थ भी आए और खुले दिमाग के नाम से कश्मीर पर कोई दिलचस्पी नहीं रखने का अर्थ भी आए। मुशर्रफ ने ऐसा अभिनय किया ताकि सब उसे यकीन करें। इस तरह वह भारत के द्वारा मान्यता प्राप्त करना, भारत-पाक बातचीत का नाटक खेलकर दुनिया में भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता हासिल करना, साथ ही साथ कश्मीर के संघर्ष का समर्थन करने वाले नायक के रूप में पाकिस्तानी अवाम की मान्यता हासिल करना जिससे वह खुद को राष्ट्रपति के रूप में स्थापित कर सके - ये थे मुशर्रफ के लक्ष्य। जैसा कि पहले भी बताया गया, पाकिस्तान में बढ़ रही आर्थिक-राजनीतिक समस्याओं से पाकिस्तानी जनता की नजरें हटाने के लिए भी मुशर्रफ को यह नाटक जरूरी हो गया। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में वह काफी हद तक सफल भी हो गए। लेकिन सच तो यह है कि आज़ाद कश्मीर के मसले पर मुशर्रफ में ईमानदारी का अभाव है। मौका मिले तो कश्मीर के बाकी हिस्से को भी पाकिस्तान में मिला लेना ही उसका मकसद है।

अजीब सी बात है, चाहे भारत-पाक बातचीत के नाम पर कश्मीर के बारे में या कश्मीर के नाम पर भारत-पाक बातचीत के बारे में भले ही बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार छेड़ा गया हो, असल में इस बातचीत का कोई सही एजेन्डा ही नहीं था। भले ही मुशर्रफ ने कश्मीर के मुद्दे पर बहस करने की ठान लेने का दिखावा किया हो, यह बात कभी नहीं बताई गई है कि असल में आजाद कश्मीर के बारे में मुशर्रफ के क्या विचार हैं। दोनों देशों के शासक वर्गों ने अपनी समस्याओं से उबरने के लिए और अपने-अपने देशों की जनता को मूलभूत समस्याओं से गुमराह करने के लिए बातचीत का यह नाटक खेला। दरअसल ये दोनों देशों के शासक वर्ग आज़ाद कश्मीर की स्थापना के विरोधी हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के शासक वर्गों ने कश्मीरी जनता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बिना ही कश्मीर के मसले पर बातचीत करने की तैयारियां कीं। कश्मीरी जनता की यह आलोचना काफी सही है कि कश्मीरी जनता के प्रतिनिधियों के बिना कश्मीर के मसले पर चाहे कितनी ही बार बातचीत होगी, लेकिन मसले का हल कभी नहीं होगा। ***"दरअसल मशर्रफ और वाजपेयी कौन होते हैं जो कश्मीर के बारे में बातचीत करें? उन्हें*** ***(शेष पृष्ठ 15 पर....)***

महाराष्ट्र का खून चूसता एनरॉन

महाराष्ट्र की भूतपूर्व और वर्तमान सरकारों में बैठे गद्दारों ने जनता के हितों को अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी एनरॉन को बेच डाला है। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी) एनरॉन को 6.80 रु. प्रति यूनिट की दर से भुगतान कर रहा है। एमएसईबी खुद 1.30 रु. प्रति यूनिट की लागत से बिजली पैदा करता है और दूसरे स्त्रोतों से 2.30 रु. प्रति यूनिट के भाव से खरीदता है। इसका मतलब, एमएसईबी एनरॉन को उसकी बिजली खरीदने के लिए 300 प्रतिशत अधिक पैसा दे रहा है। इससे एमएसईबी, जो एक समय अच्छा-खासा मुनाफा कमाता था, का दिवालिया निकल गया। वर्ष 2000 के मई के आखिर तक उसका घाटा 2,000 करोड़ रु. तक जा पहुंचा।

इस तरह की खरीद से महाराष्ट्र की जनता पर कितना बोझ बढ़ेगा, इसका अंदाजा लगाना आसान है। फिलवक्त महाराष्ट्र के घरेलू उपभोक्ता 2 रु. प्रति यूनिट की दर से पैसा दे रहे हैं। किसान (जो एमएसईबी के कुल उपभोक्ताओं का एक-तिहाई भाग हैं) प्रति यूनिट पर 50 पैसा देते हैं। यदि उपभोक्ताओं को एनरॉन की दरों से भुगतान करना पड़े, तो घरेलू उपभोक्ताओं पर तीन गुना और किसानों पर 14 गुना बोझ बढ़ेगा। चूंकि सरकार बिजली के

बिजली का निजीकरण – हर तरफ विफलता ही विफलता!

बिजली के निजी उत्पादकों के साथ तीसरी दुनिया के देशों के अनुभव कड़वे ही रहे हैं। निजी बिजली उत्पादकों के साथ किए गए समझौतों को कई देशों ने रद्द कर दिया। एनरॉन के साथ किए गए इस तरह के समझौते को क्रोएशिया ने निरस्त किया। क्रोएशिया के राष्ट्रपति द्वारा की गई निजी बातचीतों, जिनमें उसने यह कबूल किया था कि उसने एनरॉन के साथ इसलिए समझौता कर लिया क्योंकि इससे उसे वाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिलने वाला था, के व्हीडियो टेपों के उजागर होने के तुरन्त बाद यह समझौता निरस्त किया गया। इंडोनेशिया में सुहार्तो के परिजनों और दोस्तों को निजी बिजली कम्पनियों द्वारा भारी रिश्वत देकर किए गए समझौतों के परिणामस्वरूप वहां की सरकारी बिजली कम्पनी को अपना बिजली उत्पादन रोक देना पड़ा जहां कम खर्च पर बिजली पैदा की जा रही थी। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उसे निजी बिजली उत्पादकों को दी गई गारन्टी पूरी करनी थी। सिर्फ एक साल के अन्दर इन्डोनेशिया की सरकारी बिजली कम्पनी पर दो निजी बिजली कम्पनियों से एक अरब डॉलरों का कर्ज हो गया। इससे उसे पूरे समझौतों की समीक्षा करनी पड़ी। फिलिप्पीन्स भी महाराष्ट्र बिजली बोर्ज जैसी हालत झेल रहा है। 32 बिजली आपूर्ति संस्थाओं से खरीदी जा रही बिजली का बिल भुगतान करने के लिए उसे विदेशों से कर्ज उठाने पड़ रहे हैं। फिलिप्पीन्स सरकार ने साफ तौर पर कहा कि वह निजी कम्पनियों से किए गए समझौतों का नवीनीकरण नहीं करेगा। हंगरी की संसद ने भी सरकार द्वारा निजी बिजली कम्पनी आरडब्ल्यूई के साथ किए गए समझौते को गलत और अवैध ठहराया।

इस तरह तीसरी दुनिया के देशों में ही नहीं, बिजली का निजीकरण या विनियमन हटाने की समस्या ने अमरीका को भी लपेट में लिया। कैलिफोर्निया अमरीका का सबसे धनी राज्य है। इसे धरती का सबसे प्रगतिशील औद्योगिक राज्य का दर्जा मिला हुआ है। दुनिया के सॉफ्टवेर क्षेत्र की चोटी माने जाने वाली सिलिकॉन वैली इसी कैलिफोर्निया में स्थित है। पांच वर्ष पूर्व, यानी 1996 में जब कैलिफोर्निया राज्य ने बिजली उद्योग को विनियमन क्रम से हटाकर इस क्षेत्र में बाजार की ताकतों को प्रवेश दिलवाने का फैसला किया, तब सब ने उसे एक 'ऐतिहासिक' कार्यवाही बताया। जैसा कि दुनिया की बाकी जगहों में भी बताया गया, यहां भी बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया गया कि बिजली के नियमन को हटाने से निजी कम्पनियों के द्वारा बिजली की सुचारू रूप से बचत करने के कदमों से जनता को देय बिलों में 20 प्रतिशत तक कमी हो सकती है। लेकिन नियमन को हटा देने के बाद बिजली की कीमत 30 डॉलर प्रति मेगावाट से अचानक 1,000 डॉलर प्रति मेगावाट तक बढ़ गई। 1996 से कैलिफोर्निया में बिजली की दरों में 379 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोत्तरी हुई। बिजली की दरों की बात छोड़ भी दें, तो जिस 'क्षमता' के बारे में ढिंढोरा पीट-पीटकर निजी कम्पनियों ने प्रवेश किया, उस 'क्षमता' ने कैलिफोर्निया में पिछले पांच सालों में अराजकता ही पैदा की। पूंजीवादी दुनिया द्वारा 'धरती पर उतरा स्वर्ग' कहलाने वाले इस कैलिफोर्निया में अचानक बिजली गुल हो जाना, बिजली आपूर्ति व्यवस्थाओं का ठप्प हो जाना आदि से कैलिफोर्निया के अटार्नी जनरल ने निजी बिजली उत्पादक और आपूर्तिकर्ता एनरॉन के कामकाज के ढंग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की। अनगिनत उपभोक्ताओं ने एनरॉन आदि निजी बिजली कम्पनियों के खिलाफ यह कहते हुए मुकदमे दायर किए कि उन्होंने मुनाफा कमाने वाली बिजली व्यवस्था को उलटकर धोखाधड़ी की। इसका नतीजा यह रहा कि 'जमीन पर उतरा स्वर्ग' कैलिफोर्निया पिछले पांच सालों में 'जमीन पर उतरा नरक' बन गया। सिलिकॉन वैली में बिजली की कटौती इस कदर की जाती है कि वहां की विश्व स्तर पर नामी-गिरामी हाइ-टेक (साफ्टवेयर और हार्डवेयर) कम्पनियों ने कैलिफोर्निया राज्य को ही छोड़कर जाने की कोशिशें शुरू कीं। कैलिफोर्निया में मचे आतंक और अस्तव्यस्तता के लिए इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है?

काश कैलिफोर्निया की बदहाली पर महाराष्ट्र सरकार, चन्द्रबाबू नाइडू और उस किस्म के लोग एक बार नजर डालते ! ❑

निजीकरण पर तुली हुई है, इसलिए बढ़ोत्तरी अवश्यंभावी है। इससे किसानों, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर जबर्दस्त मार पड़ेगी।

मौजूदा हालत उस समझौते का नतीजा है जिस पर खुद को राष्ट्रीयवादी कहने वाली शिवसेना/भाजपा सरकार ने दस्तखत किया। पहले शरद पवार (एक जमाने का कांग्रेसी और अब एनसीपी) को और बाद में बाल ठाकरे को रिश्वत देकर एनरॉन ने इस बेहद अपमानजनक समझौते पर एमएसईबी का दस्तखत करवाया।

इस समझौते के मुताबिक एनरॉन अपनी बिजली की कीमत 'क्षमता' के आधार पर लगाती है, एमएसईबी अगर बिजली नहीं भी खरीदता है तब भी उसे भुगतान करना पड़ेगा। ईंधन की कीमत रूपए की डालर कीमत पर तथा तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत पर आधारित है। इसलिए, यदि एमएसईबी एनरॉन से बिजली नहीं खरीदता है, तब भी 95 करोड़ रु. प्रति माह का असाधारण 'क्षमता चार्ज' भुगतान करना पड़ेगा। सबसे बड़ा अपराध तो यह है कि एमएसईबी के दलाल बिजली की एक कृत्रिम किल्लत पैदा कर रहे हैं ताकि एनरॉन से ऊंचे दाम पर बिजली की खरीद को जायज ठहराया जा सके। यह किल्लत पैदा करने के लिए उसने अपने कुछ संयंत्रों को 'मरम्मत' के नाम पर बंद कर दिया और गैस आधारित 900 मेगावाट की उरान यूनिट को गैस की अनुपलब्धता के बहाने बंद कर दिया। दरअसल, महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन और उपलब्धता का संपूर्ण विश्लेषण करने से यह पता चल जाता है कि दाभोल बिजली संयंत्र (एनरॉन) से बिजली खरीदने की जरूरत कतई नहीं है।

मुक्त व्यापार की पवित्रता का ढिंढ़ोरा पीटने वाले अमरीकी डकैतों ने एनरॉन से बहुत ऊंचे दाम पर–**न कि बाजार के दाम पर**–बिजली खरीदने के लिए एमएसईबी से कई समझौते किए। क्यों एनरॉन मुक्त बाजार में अन्य बिजली उत्पादक कम्पनियों से स्पर्धा नहीं करती?! एमएसईबी एनरॉन से बिजली खरीदने को मजबूर है, वरना उसे प्रति माह जुर्माने के रूप में 95 करोड़ रु. की भारी भरकम राशि देना पड़ेगी। इसके अलावा एनरॉन ने राज्य सरकार से यह गारन्टी हासिल की कि यदि एमएसईबी उसे भुगतान नहीं कर सकेगा तो राज्य सरकार भुगतान करेगा, केन्द्र सरकार से यह प्रति-गारण्टी हासिल की कि यदि राज्य सरकार भुगतान नहीं कर सकेगी तो केन्द्र सरकार करेगी।

कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एनरॉन ने अपनी परियोजना का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारियां कीं (जिससे उसकी उत्पादन क्षमता 1,444 मेगावाट की हो जाती है) और महाराष्ट्र सरकार को समझौते को आगे बढ़ाते हुए दस्तखत करने पर मजबूर किया गया, नहीं तो उसे अपने वादे से मुकरने के लिए 20,000 करोड़ की क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी।

चूंकि इस खुली लूट-खसोट से भी एनरॉन संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए भारत की वित्तीय संस्था औद्योगिक विकास बैंक, जिसने एनरॉन को संयंत्र का निर्माण करने के लिए भारी भरकम राशि कर्ज के रूप में दी थी, ने अब फैसला किया कि अपने द्वारा दिए कर्ज पर ब्याज की दर में 3 प्रतिशत कटौती–17% से 14%–की जाए। दूसरे शब्दों में, सरकार एनरॉन को सालाना 50 से 100 करोड़ रु. का एक और तोहफा देने जा रही है।

सरकार एक ओर ऊंची बिजली दरों से जनता को लूटते हुए, कर्ज और कम ब्याज दरों से खजाने को लुटाते हुए, एमएसईबी का दिवालिया निकालते हुए, दूसरी ओर एनरॉन को भारी मुनाफा दिलवा रही है। इसका बड़ा हिस्सा विदेशों में निवेश किया जा रहा है। यह देश के साथ और देशवासियों के साथ गद्दारी नहीं तो और क्या है?

लेकिन इस तरह की परियोजनाओं में सिर्फ एनरॉन ही नहीं है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दूसरे स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ इस तरह के कई बिजली खरीद के समझौते किए गए हैं। इनमें से अधिकतर इस वर्ष में उत्पादन शुरू करने की संभावना है। आन्ध्रप्रदेश में इसके प्रभाव पहले ही देखे गए हैं, जहां अमरीका के पालतू कुत्ता चन्द्रबाबू नाइडू ने बिजली की दरों को अंधाधुन्ध बढ़ा दिया।

इस तरह के देशद्रोहात्मक समझौतों का जमकर विरोध करना चाहिए। एनरॉन जैसी संस्थाएं भारत के हितों के लिए काफी नुकसानदेह हैं। लेकिन इन समझौतों का अस्तित्व विश्व बैंक द्वारा निर्देशित बिजली क्षेत्र के संपूर्ण निजीकरण से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह नीति इस क्षेत्र में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करती है और साथ ही, इन नए कदमों से अंधाधुन्ध बढ़ाई जाने वाली बिजली की दरों से जनता भी प्रभावित होगी। इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। 2000 के दिसंबर माह में बिजली कर्मचारी एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर चले गए थे। यह केवल शुरूआत भर है, सरकार को अपनी नीतियों को वापस लेने पर मजबूर करने के लिए यह नाकाफी है। कर्मचारियों और जन-समुदायों को एकजुट होकर एक सैलाब की तरह उमड़ना होगा ताकि बिजली क्षेत्र में साम्राज्यवादी साजिश को नाकाम किया जा सके। ❑

(.... पृष्ठ 13 का शेष)

किसने यह अधिकार दिया है कि वे कश्मीर पर बात करें? सबसे पहले भारत और पाकिस्तान अपनी-अपनी सेनाएं वापस ले लें तो हम अपने बारे में खुद ही देख लेंगे" कहकर जेकेएलएफ ने कश्मीरी जनता की आकांक्षाओं को सही अभिव्यक्ति दी।

अब कश्मीरी जनता के सामने हल का एक ही रास्ता है। संघर्ष को आगे बढ़ाना ही वह रास्ता है। किन्हीं दो दूसरे देशों के बीच बातचीत से कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलेगी। कश्मीर की आजादी के लिए खुद कश्मीरी जनता को अपनी खुद की ताकत के बूते संघर्ष को जारी रखना होगा। संघर्ष की शुरूआत में व्याप्त भ्रम और असमंजस की स्थिति संघर्ष के दौरान ही दूर होकर स्पष्टता आएगी। कश्मीरी जनता को अब आजादी की लड़ाई के बारे में ज्यादा स्पष्टता मिल रही है। इसीलिए कश्मीर आज एक आग का गोला जैसा बन गया है। निश्चित रूप से कश्मीर की जनता ही कश्मीर की आजादी हासिल कर लेगी। ❑

अनाज के ढेरों के बीच भुखमरी से लाखों लोगों की मौत

"नारायण लाल 20 वर्षीया छुमेरिदिता को राजस्थान के कोतरा स्थित अस्पताल ले गया जहां उससे 5,000 रु. देने को कहा गया। वह नहीं दे सका। छुमेरिदिता मर गई। कुछ दिन बाद उसका बच्चा भी मर गया। लाल ने कहा सदा पंचायत में हर 3-4 दिनों में 2-3 लोग मर रहे हैं।"

"28 साल के आदिवासी युवक वेरा होना को सरकार के 'राहत-केन्द्रों' में काम नहीं मिला। वह गुजरात गया। लेकिन वहां भी कोई काम नहीं मिला। वह 70 किलोमीटर पैदल चलकर वापस घर आया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने फिर से काम की तलाश में 'राहत-केन्द्रों' का चक्कर लगाया। उसे वापस भेज दिया गया। 11 फरवरी को उसने कीटनाशक दवाई खा ली। उसने अपने पड़ोसियों को पहले ही बताया था कि वह अपने बच्चों को भूख से तड़पकर मरते हुए नहीं देखना चाहता है। उसकी मौत के पहले उसके परिवार के छह सदस्य दो दिन में एक बार बारी-बारी से खाना खाया करते थे..... खाने के नाम पर थोड़ा मकई का पेज, थोड़ा नमक और कुछ मिर्चियां।"

"राजस्थान की मेदी पंचायत के देरी गांव के उप सरपंच शंकर भामाजी ने कहा कि बेरोजगारी और भूख के चलते हो रही मौतें आम हो गईं। उसने कहा कि गिरवा, केरवादा आदि प्रखण्डों में हालत एक जैसी है।"

"समूचे राजस्थान में 'राहत-केन्द्रों' के सामने 500 से 600 लोगों का तांता लग जाता है। बमुश्किल 20 से 40 लोगों को काम में लिया जाता है, वह भी महज 15 दिनों के लिए। महिलाएं बिलखते हुए वापस चली जाती हैं जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता। महीने की 1 और 15 तारीखों को रोती हुई महिलाओं और हताश पुरुषों का दृश्य दिल को चीर देता है। जिन्हें वापस भेजा जाता है उनके लिए 'राहत-केन्द्रों' पर सरकार की मजदूर सीलिंग नियम मानो मृत्युदंड की घोषणा ही है।"

"राहत सचिव राम लुभाया ने जयपुर में भुखमरी की खबरों को ठुकरा दिया।"

पूरे राजस्थान में कुपोषण के चलते मौत, बीमारी और आत्महत्या एक सामान्य बात बन गई। विडंबना देखिए, सबसे धनवान मारवाड़ी समुदाय अपने गृहराज्य को मुरदाघर में तब्दील होता हुआ देख रहा है। उन्हे इसकी परवाह नहीं है। वे भारत के कोने-कोने में पैसा बनाते ही रहते हैं। न तो काग्रेंस शासित राज्य सरकार को और न ही केन्द्र सरकार को इसकी चिंता है। आखिर वहां जो मर रहें हैं वे सब गरीब हैं, उनका एक विशाल भाग आदिवासियों का है।

राजस्थान सबसे सूखे से बुरी तरह प्रभावित राज्य भले ही हो, अन्य राज्यों की स्थिति भी बदतर ही है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश और यहां तक की हिमाचलप्रदेश और उत्तरांचल भी सूखे का सामना कर रहे हैं। हजारों लोग और मवेशी दम तोड़ रहे हैं। इन सभी राज्यो में आदिवासी सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। यहां जनता अमानवीय अस्तित्व की स्थिति तक सिकुड़ गई। मृत लोग जिंदगी की यत्रंणा और वेदना को देखने से बच गए हैं। बच्चों की पूरी पीढ़ी बेहद कुपोषण की हालत में पल रही है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास खतरे में है।

राजस्थान में पूरे 32 जिलों में से 31 के 3.5 करोड़ लोग और 5.4 करोड़ मवेशी सूखे के चपेट में आ गए। पिछले साल के 23,400 प्रभावित गांवो की तुलना में इस बार 30,585 गांव प्रभावित हैं। इस साल *'गोदारा'* (घास से बनाई जाने वाली एक रोटी जो बेहद तंगी के दिनों में आदिवासी खाते हैं) भी नहीं मिल रही है।

महाराष्ट्र में सरकार ने 26 जिलों (पूरे 35 जिलों में से) को अकालग्रस्त घोषित किया। 1992 के बाद यह सबसे बुरा अकाल है। नासिक डिवीजन (नंदुरबार, जलगांव, धुले, अहमदनगर और नासिक जिले) की आदिवासी पट्टी में साल भर में कुपोषण से 8,000 बच्चों की मौत हुई जिनकी उम्र छह साल तक थी। लेकिन नासिक सबसे अकाल ग्रस्त जिला नहीं है। वह तो अमरावती जिला है। मेलघाट क्षेत्र मे पिछले एक दशक से, यहां तक की सामन्य वर्षा की स्थिति में भी सैकड़ों आदिवासी बच्चे कुपोषण के चलते मौत के मुह में समाते जा रहे हैं। वहां की स्थिति इस वर्ष कैसी होगी आसानी से कल्पना की जा सकती है।

आन्ध्रप्रदेश में सरकार ने 8 जिलों के 142 मण्डलों को सूखाग्रस्त घोषित किया। हालांकि सभी जिलों में पीने के पानी की किल्लत है, लेकिन अनन्तपुर, कर्नूल, प्रकाशम, करीमनगर, नलगोण्डा और मेदक जिलों में हालत बहुत ही खराब है।

छत्तीसगढ़ में इस सीज़न में 20 से 25 लाख लोगों ने रोटी की तलाश में पलायन किया।

हर तरफ आपराधिक लापरवाही, जानबूझकर किया जाने वाला विनाश और उच्च स्तर के भ्रष्टाचार की कहानी एक सी है। इस कंगाली के बीच ही डॉक्टर सिर्फ जांच के लिए मरीजों से 100 से 300 रु. वसूलते हैं। दवाई के लिए अलग। 'राहत-केन्द्रों' पर अधिकारी 30 से 35 रु. का भुगतान करते हैं जबकि सरकार द्वारा निर्धारित न्यनतम मजदूरी 60 रु. है। उनकी सूचियों में काल्पित नाम दर्ज किए जाते हैं और सैकड़ों लोगों को वापस लौटाते हैं। सूदखोर (मुख्य रूप से दुकानदार) और गिरवी व्यापारी लोगों की जान खा रहे हैं जबकि अधिकांश ग्रामीण 10,000 रु. से लेकर 40,000 रु. तक के कर्जों में डुबे हुए हैं। कई लोग अपनी जमीन से हाथ धोने के स्थिति में हैं क्योंकि वे भारी ब्याज दरों को नहीं चुका सकेंगे।

लेकिन लाखों ग्रामीण जनता की इस बदहाली सिर्फ सूखे का नतीजा नहीं, बल्कि लापरवाही और भ्रष्टाचार का है। यह उस सचेत नीति का हिस्सा है जहां बाजार में प्रचलित दुराग्रह क्रय शक्ति से लैस व्यक्ति को ही अपने लिए उपयोगी मानता है, बाकी को व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ मानता है और उनका पिंड छुड़ा लेना बेहतर समझता है। इसी सोच का नतीजा यह हास्यास्पद स्थिति है कि जहां एक ओर गोदामों में खद्यान्न के भीमकाय भंडार मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग भूख से तड़प रहे हैं और हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। इस बेतुकी हालत पर नजर डाली जाए।

ढेरों अनाज, लेकिन भूखी जनता के लिए नहीं !

अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अकाल से लाखों लोग मारे गए थे क्योंकि खाने के लिए अहार नहीं था। वर्तमान राज में सूखे से हजारों लोग मर रहे हैं, जबकि लाखों टन खद्यान मौजूद हैं। इसलिए वर्तमान राज कम से कम अंग्रेजी हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा क्रूर है। कल्पना कीजिए, राजस्थान के नोखा, बीकानीर जैसे कई जिलों में खद्यान्न के पहाड़ सूखा पीड़ीत लोगों की आंखों के सामने खड़े हैं।

भारत में एफसीआइ (भारतीय खाद्य निगम) के गोदामों में 4.5 करोड़ टन खाद्यान के भीमकाय भण्डार मौजूद हैं। इनका 30 प्रतिशत 2 से 3 साल पुराना है और सड़ने लग गया है। पिछले साल एफसीआइ ने 10 लाख टन भंडार को नष्ट हुआ बताया। इसके अलावा वर्तमान रबी सीजन में 80 लाख टन गेहूं खरीदा गया। इसे रखने के लिए जगह नहीं है। इस खाद्यान्न को चूहे खाए जा रहे हैं और भारी नुकसान हो रहा है। भण्डारण की कीमतों में भारी उछाल आई है। इसके बावजूद सरकार इस खाद्यान्न को भूख से पीड़ीत लाखों लोगों को वितरित करने को तैयार नहीं है। यह आपराधिक कत्लेआम से कम नहीं है। एक ओर तो सरकार 'काम के बदले अनाज' की योजनाओं के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराती है, दूसरी ओर वह न तो गरीबी रेखा वाले राशन पाने के लिए पात्रता की सीमा को घटाती है न उन्हें देय राशन की कीमतें नीचे लाती है जो जनता की पहुंच से बाहर रह गई। और जहां ये दुकानें मौजूद हैं उनमें समान रूप से सीमित राशन ही उपलब्ध है। अभी तक विभिन्न योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा विमोचित खाद्यान बहुत कम कहा जा सकता है। भूख से तड़पने वालों को आहार देने के बजाए वह यह ढिंढोरा पीटने में ही तेजी दिखा रही है। सबसे बुरी तरह प्रभावित राजस्थान की स्थिति पर नजर डाली जाए।

यहां सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने (अप्रैल 2001 तक) की सीमा निर्धारित की जबकि 350 लाख लोग सूखे के चपेट में आ चुके हैं। स्थानीय लोग अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताते हैं कि पहले के अकालों में रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध किए जाते थे। 1988 के बाद अकाल में जनवरी-मई के दरमियान 17 लाख लोगों को राहत-केन्द्रों में रोजगार मिला था। इस वर्ष का आंकड़ा सिर्फ 6 लाख का हैं। लेकिन इस वर्ष क्रूरतापूर्ण सीलिंग तय की गई, बावजूद इसके कि 'काम के बदले अनाज' की योजनाओं में देने के लिए पहले के सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा खाद्यान्न उपलब्ध हैं। मिसाल के तौर पर उदयपुर जिले में 70,000 लोग सूखे से पीड़ित हैं तो औसतन 800 लोगों को ही काम मिला। देवला गांव में 5,000 लोग रहते हैं, लेकिन 40 लोगों को ही राहत केन्द्रों में काम मिला।

लोगों ने यह शिकायत भी की कि उचित मूल्य दुकानों में उन्हें कभी भी राशन अनाज पूरा नहीं मिलता है। गरीबी रेखा के नीचे गेंहू 4.60 रु. प्रति किलो बिक रहा था और खुले बाजार में मकई 5 रु. प्रति किलो बिक रहा था।

सरकार का प्रचार चाहे जो हो, जमीनी सच्चाइयां तो दूसरी तस्वीर पेश करती हैं। जबकि जनता भूख से मर रही है, गोदामों में खाद्यान्न सड़ रहे हैं।

लेकिन सरकार की अपराधिकता यहीं खत्म नहीं होती। वह इस हद तक बढ़ चुकी है जिसकी कल्पना सिर्फ तानाशाही के राज्यों में ही की जा सकती है। जबकि उसने अकाल और भुखमरी की स्थिति में भी गरीबी रेखा वाले राशन की कीमतें कम करने से इनकार किया, दूसरी ओर व्यापारियों द्वारा गरीबी रेखा से कम दाम पर बड़े पैमाने पर गेंहू निर्यात को स्वीकृति दी। पिछले चंद महीनों में सरकार ने व्यापारियों से 3.90 रूपये प्रति किलो (84 डॉलर प्रति टन) की दर से गेंहू लेकर 17 लाख टन का निर्यात किया और अतिरिक्त 9 टन के लिए करार किया। वास्तव में सरकार ने नवंबर 2000 से मार्च 2001 तक खाद्यान्न के निर्यात पर 664 करोड़ रु. सब्सिडी के तौर पर खर्च किए, जबकि गरीबी रेखा के नीचे की जनता के लिए 498 रूपये ही अंवटित हैं। इसलिए खाद्य सब्सिडियों में कटौती करने के लिए मीडिया द्वारा काफी शोर मचाए जाने के बावजूद, सरकार विदेशी मुद्रा कमाने के लिए निर्यातों पर मोटी सब्सिडियां देने को तत्पर है, पर गरीब और भूखी जनता के लिए सब्सिडी के रूप में एक कौड़ी भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है।

किसी आंशिक रूप से जनवादी व्यवस्था में भी इस तरह की निर्लज्ज जन-विरोधी नीतियों की कल्पना नहीं की जा सकती। फासीवादी राज्य यंत्र के बल बूते यह पाशविक और घमंड राजसत्ता जनता की मौजूदा निष्क्रिय स्थिति का फायदा उठाते हुए जनता की जिन्दगियों को लापरवाह होकर कुचल रही है।

लेकिन वह तेजी से बदल रही है। समूचे राजस्थान में गोदामों के सामने कई विरोध-प्रदर्शन किए गए। एफसीआइ गोदाम के बाहर, जिसकी रक्षा में 100 पुलिस वाले तैनात किए गए थे, आयोजित एक प्रदर्शन में भाग लेने वाले हजारों प्रदर्शनकारियों में से एक युवा प्रदर्शनकारी को यह कहते हुए सुना गया, *"हां हम*

सरकार गोदामों पर कब्जा करेंगे"; दूसरे ने जोड़ा *"और साथ ही साथ, हमें सेठ-साहुकारों पर भी धावा बोलना चाहिए"* यहां तक कि दिल्ली में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले अवैतनिक प्रोफेसर जीन द्रेज़े ने 'दि हिन्दू' में लिखा: *"इस तरह की नाइंसाफी को देखते हुए हरेक व्यक्ति चाहेगा कि भूखी जनता आहार पर अधिकार को अपने हाथ में ले।"*

दुर्भाग्य से राजस्थान के युवा और द्रेज़े को अभी यह मालूम नहीं है कि मध्य भारत के कई हिस्सों में हमारी पार्टी, भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] ने एफसीआइ के गोदोमों और जमाखोरों व सूदखोरो के भंडारों पर कई अकाल हमले किए ताकि जनता की तकलीफें दूर की जा सकें।

जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए वह अस्थाई समाधान जरुर है, पर इनकी जड़ें काफी गहरी हैं। हालांकि पहले भी इससे बदतर सूखे आए थे। लेकिन इतनी व्यथा कभी नहीं रही जितनी आज है। सचाई यह है कि आर्थिक सुधारों के इन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के साथ लगातार बरती जा रही लापरवाही ने पहले से गरीबी में डुबी हुई ग्रामीण जनता को विनाश के कागार पर ला खड़ा किया। उत्पादन में होने वाले छोटे से उतार-चढ़ाव भी उस पर भारी पड़ने लगे। बारिश की थोड़ी सी कमी भी पहले से अमानवीय हालत में अस्तित्व में जी रही जनता को तबाही की ओर ले जाती है। पानी, भोजन और अन्य वस्तुओं की कमी को सूखा और भी तेज बनाता है। लेकिन आज हम जिस तरह की विपदा देख रहे हैं, उसका आधार यह नहीं है। यह नीतियों से बनी विपदा है जिसे हम आज देख रहे हैं।

कृषि संकट : विपदा की असली जड़

यदि भारत की 20 करोड़ टन फसलों को न्यूनतम उष्मांकीय जरूरत (minimum caloric requirement) के आधार पर बांटा जाए, तो अतिरिक्त खाद्यान्न का विशाल भण्डार पूरा गायब हो जाएगा। सरकार और मीडिया यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि फलती-फूलती कृषि के परिणामस्वरूप ही खाद्यान्न भण्डार लगातार बढ़ रहे हैं जो एक झूठ है। हालांकि खाद्यान्न उत्पादन की विकास-दर गिर रही है, फिर भी भण्डार बढ़ रहे हैं। क्योंकि गरीबों की क्रय शक्ति में भारी गिरावट से अतिरिक्त खाद्यान्न बढ़ रहे हैं। जन वितरण प्रणाली को लगभग खत्म किए जाने के चलते इसमें ये दस गुना बढ़ गए। (पिछले साल ग्रामीण जनता द्वारा की जाने वाली कुल खरीद में 25 फीसदी गिरावट आई।) भारत के 'अतिरिक्त' खाद्यान्न उत्पादन का आधार यह है कि हरेक रात करोड़ों लोग भूखे पेट सो जाने को मजबूर हैं।

फिलहाल भारत के ग्रामीण इलाकों में व्याप्त विपदा स्थाई स्वभाव की है जो हर साल ज्यादा तीव्रता से ग्रामीण जनता को अपनी चपेट में ले लेगी और हजारों की भुखमरी का कारण बनेगी। सूखे जनता की मश्किलों में वृद्धि ही करते हैं। सालों से बनाई जा रही गलत योजनाओं और अराजक विकास के चलते पर्यावरण के व्यापक विनाश के परिणामस्वरूप ही सूखे आते हैं। इसका स्वभाव भी स्थाई है। आइए, आर्थिक सुधारों के इन सालों में कृषि-अर्थव्यवस्था की दशा पर नजर डालें जिसने लाखों जनता की जिंदगी को तबाह कर रख दिया।

पिछले दशक में हम कृषि उत्पादन, उत्पादकता, कृषि में पूंजी निवेश, ग्रामीण रोजगार आदि की विकास-दर में भारी गिरावट को देख सकेंगे। इन तमाम कारणों से भारत के ग्रामीण क्षेत्र में खतरनाक स्थिति निर्मित हो गई।

1980 के दशक की तुलना में 1990 के दशक में फसल उत्पादन की विकास-दर लगभग आधी हो गई। वह 1980 में 3.4% से आज 1.8% तक घट गई। वह और भी गिरती जा रही है। नीचे दी गई तालिका से अलग-अलग किस्म के कृषि उत्पादनों की गिरती विकास-दर की तसवीर सामने आती है।

कृषि उत्पादन की वार्षिक विकास-दर

	1980-81से 1991-92	1992-93 से 1999-2000
1. खाद्य अनाज	2.9	2.0
इनमें से सिरियल्स	3.1	2.1
धान	3.7	2.2
गेंहू	3.6	3.6
अपरिष्कृत सिरियल्स	-	(-) 1.6
2. दलहनें	1.4	0.8
3. गैर-खाद्यान्न	4.3	2.4
4. सभी फसलें	3.4	1.8

तिलहनों और दलहनों के उत्पादन में वास्तव में पूरी तरह गिरावट आई है। तिलहनों का उत्पादन 1996-97 में 2.5 करोड़ टर रहा जो 2000-01 में 1.9 करोड़ टन तक घट गया। इसी अवधि में दलहनों का उत्पादन 14 करोड़ टनों से 1.3 करोड़ टनों तक घट गया।

जहां तक खाद्यान्नों की उत्पादकता का सवाल है, हमें पता चलता है कि 1980 के दशक में 3.2 रही वार्षिक विकास-दर 1990 के दशक में 2.3% तक घट गई। लेकिन खाद्यान्नों की पैदावार 1980-81 में 11.4 क्विन्टल (1140 किलो) प्रति हेक्टेयर थी जो 1990-91 में 15.7 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर तक और 1997-98 में 17.7 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ी। (**आधार** : *भारत 2000; भारत सरकार का प्रकाशन*)

इसलिए, आश्चर्य की बात नहीं कि खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1991 में 510 ग्राम रही जो वर्ष 2000 में 446 ग्राम तक घट गई। लेकिन इससे प्रतिदिन के उपभोग की मात्रा की सही तस्वीर सामने नहीं आती जोकि इससे कहीं ज्यादा कम होगी। इस 'उपलब्धता' में गोदामों के विशाल भंडार भी शामिल है जो वास्तव में जनता के लिए 'उपलब्ध' नहीं है क्योंकि खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है।

दूसरा, आज कृषि में पूंजी निवेश 1980 के दशक के मुकाबले में आधा है। नीचे दी गई तालिका से यह पता चलता है कि भारतीय कृषि में दोनों सरकारी और निजी स्त्रोतों द्वारा पूंजी निवेश में किस तरह गिरावट आ रही है।

कृषि में पूंजी निवेश

(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

	सार्वजनिक	निजी	कुल
1990-91	0.6	1.6	2.2
1996-97	0.4	1.1	1.5
1997-98	0.3	1.1	1.4
1998-99	0.3	1.1	1.4

चूंकि केन्द्र एवं राज्य कह रहे हैं कि उनके पास धन का अभाव है, इसलिए सिंचाई, कृषि अनुसंधान, भूमि विकास आदि में सार्वजनिक पूंजी व्यय घट चुका है। जबकि टेलिकॉम उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी में मदद करने के लिए उन्हें बेअन्त संसाधन मिल जाते हैं, लेकिन कृषि के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता।

मिसाल के तौर पर, राजस्थान में कृषि पर विकास खर्च वर्ष 1995-96 और 1997-98 के बीच 20 प्रतिशत घट गया। विकास का नजरअंदाज और संभ्रान्त वर्गवादी योजनाओं के प्रति शासकों के पागलपन की हद तक के मोह का उदाहरण यह है कि गेहलोत सरकार ने अपने 'राहत कार्य' के अंतर्गत प्रत्येक जिले में गोल्फ के मैदानों का निर्माण करने का अव्यावहारिक फैसला लिया! 'राहत कार्य' का इस्तेमाल पानी के भण्डारण की योजनाओं के लिए करने के बजाए, उसने गोल्फ का मैदान बनाने की योजना बनाई जो 9,000 आबादी वाले एक गांव के बराबर का पानी पी जाता है।

महाराष्ट्र सरकार ने भी पिछले साल पानी की 2,600 परियोजनाओं को निरस्त कर दिया क्योंकि उसके पास 'धन अपर्याप्त' है। लेकिन सरकार टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति करने के लिए हर साल 100 करोड़ रूपए खर्च कर सकती है। यह कदम शक्तिशाली टैंकर लॉबी को संतुष्ट करता है जिसके सूत्र अग्रणी राजनीतिकों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र की कुल खेति योग्य जमीन के सिर्फ 15 प्रतिशत को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है जो कि राष्ट्रीय औसत का आधा है। इस जमीन का अधिकांश हिस्सा शक्कर लॉबी का है। इस तरह, एक ऐसे राज्य के पास, जो भारी राजस्व पैदा करने वाले राज्यों में से एक है (मुम्बई-पुणे पट्टी में औद्योगिक और आर्थिक केंद्रीकरण के चलते), सिंचाई सुविधाएं बनाने के लिए पैसा नहीं है!

निजी पूंजी निवेश का जहां तक सवाल है, किसान ज्यादा पूंजी लगाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि ऋण मिलने के अवसर समाप्त हो चुके हैं, चलती पुंजी का तो जिक्र ही नहीं है। 1990 के दशक में संगठित ग्रामीण ऋणव्यवस्था विनाश की स्थिति में आ गई। यह प्रक्रिया दो कारणों से तेज हुई – 1) बैंकों का निजीकरण की ओर बढ़ता रुझान और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र को विशेष ऋण खत्म करने के सरकार के निर्देश, 2) पैदावार में गिरावट के चलते कृषि का संकट।

आखिर में, अगर हम ग्रामीण रोजगार पर नजर डालें, तो 1947 के बाद के इतिहास में 1990 के दशक में इस क्षेत्र में सबसे कम विकास-दर देखी गई। 1977 से 1989 के बीच ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार लगभग दोगुना हुआ। तब से इसमें गिरावट आई। 1990 के दशक के आखिरी सात सालों में यह महज 0.7 प्रतिशत की रही।

इसके अलावा, झींगा मछली पालन जैसी योजनाओं से रोजगार के अवसर घट रहे हैं, जैसा कि आन्ध्रप्रदेश की तटीय पट्टी में हुआ। एक एकड़ में धान की खेती से साल में 150 कार्य दिवस उपलब्ध किए जाते हैं, जबकि झींगा मछली पालन में महज 40-50 कार्य दिवस।

1990 के दशक के दौरान खेतिहर मजदूरों के वास्तविक वेतन स्थिर रहे।

इस तरह, खेती के संकटग्रस्त होने से, ग्रामीण रोजगार घट जाने से, वास्तविक वेतन स्थिर रहने या कम होने से और कृषि में पूंजी निवेश सिकुड़ते जाने से और संगठित साख के विनाश होने से ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनता तबाही के कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसी हालत में, छोटे से उतार-चढ़ाव से भी दुःखद नतीजे हो सकते हैं। यहां तक कि परिवार में किसी के बीमार होने से, या नकदी फसलों की कीमतें गिरने से, या पैदावार में गिरावट आने से, या फिर घर में एक बेटी की शदी होने से भी परिवार के भीतर संकट पैदा हो जाता है। सूखे और कम वर्षा से स्थिति विनाशकारी रूप ले लेती है। साल-दर-साल ग्रामीण आबादी की सहन शक्ति ज्यादा से ज्यादा सिकुड़ती जा रही है। उनकी मजबूरियां बढ़ रही हैं। छोटे से झटके को सहने में भी उनकी क्षमता घट रही है। इसका नतीजा ही था जो हमने हाल की गर्मियों में देखा, और भविष्य में हमें हर साल गर्मियों में इसे इस रूप में या फिर किसी दूसरे रूप में देखना पड़ेगा।

कृषि क्रांति : एक मात्र रास्ता

तो फिर जनता किससे मदद की गुहार लगाए? संशोधनवादी पार्टियों समेत किसी भी संसदीय पार्टी के पास इन समस्याओं के सही समाधान हैं। ज्यादा से ज्यादा वे कुछ सुधारों से आंसू पोंछू काम कर सकते हैं ताकि विद्रोह को टाला जाए। क्या गैर-सरकारी संगठनों के पास इसका समाधान है? ऐसे इलाकों में सैकड़ों गैर-सरकारी संगठन काम कर रहे हैं जिसका असर न के बराबर है। अपवादस्वरूप इने-गिने लोगों को छोड़कर जिन्हें वे गांवों में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, अधिकतर लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर, राजस्थान के उदयपुर जिले में ऐसे 300 गैर-सरकारी संगठन मौजूद हैं जिन्हें अच्छा-खासा फण्ड मिलता है। लेकिन वास्तव में ***(शेष पृष्ठ 8 पर ....)***

पीजीए में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाओ!

8 मार्च - अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित सभाओं में गूंज उठा नारा

8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दण्डकारण्य में साल दर साल ज्यादा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। हर साल इसमें भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और साथ ही महिलाओं की संघर्ष चेतना भी बढ़ रही है। गांवों में केएएमएस में शामिल महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पीजीए और पार्टी में भी महिलाओं का प्रतिशत पिछले कुछ सालों से काफी बढ़ चुका है। महिलाएं केएएमएस के नेतृत्व में कई समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहीं हैं। कबीलाई रीति-रिवाज के तहत महिलाओं के साथ किए जाने वाले भेदभाव और अन्याय के खिलाफ महिलाएं संघर्ष कर रहीं हैं। एक शब्द में कहा जाए, तो दण्डकारण्य की महिलाएं भारत के क्रांतिकारी महिला आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रही हैं। पार्टी ने इस बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं का आह्वान किया कि *"पीजीए में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाओ "*।

दक्षिण बस्तर डिवीजन

इस पृष्टभूमि में दण्डकारण्य के दक्षिण बस्तर डिविजन में सभी इलाकों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। गोलापल्ली और किष्टाराम रेजों में केएएमएस की 70 महिलाओं ने एक महीना पहले से ही प्रचार कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने गांव-गांव घूमते हुए जनता से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित सभाओं में भाग लेकर सफल बनाने की अपील की। स्त्री-पुरुषों को समान अधिकार देने तथा पुलिसिया अत्याचारों को बंद करने की मांग करते हुए गांव-गांव में पोस्टर भी लगाए। किष्टाराम इलाके में एत्तराज, तोंडामरका और करिगुण्डेम गांवों में सभाएं आयोजित की गईं।

8 मार्च को एत्तराज गांव को लाल बंदनवारों से सजाया गया जिससे पूरा गांव ही लाल-लाल हो गया। गांव के बीचों-बीच मंच बनाया गया। सुबह 8 बजे तक आसपास की गांवो की सैकड़ों आदिवासी महिलाएं गोद में अपने नन्हें बच्चों को लेकर एत्तराज पहुंचीं। पालेसेल्ला-दब्बम सड़क जो इस गांव से गुजरती है, पर महिलाओं ने जुलूस निकाला। शहीद कॉमरेड अशोक,जोगन्ना और कमलाक्का के नाम पर गगनभेदी नारे लगाए। इस तरह नारों और गीतों से चलता हुआ जुलूस बीच गांव पहुंचा। पीजीए के आधार बल (मिलिशिया) के सदस्यों ने दुश्मन के संभावित हमले का मुकाबला करने के लिए गांव में आने वाली सभी सड़कों पर पहरा बिठा दिया। उन्होंने एक गश्ती दल भी गठित किया। जिसने गांव की चारों तरफ गश्त लगाई ताकि दुश्मन को इस सभा पर हमला करने का मौका न मिल सके।

इस सभा को केएएमएस की रेंज कमेटी सदस्याओं ने और कुछ डीएकेएमएस नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व पर रोशनी डाली। इसके अलावा फिल्मों में महिलाओं का अश्लील चित्रण, आदिवासी रीति-रिवाजों में महिलाओं का दोयम दर्जा, जबर्दस्ती विवाह, बहु-पत्नीत्व प्रथा आदि मुद्दों पर महिलाओं की चेतना बढ़ाने का प्रयास किया। बाद में केएएमएस कार्यकर्ताओ ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जिसमें महिलाओं की समस्याओं पर और महिला शहीदों पर लिखे गए गीत शामिल थे।

आखिर में पार्टी की ओर से एक कॉमरेड ने भाषण देते हुए कहा कि महिलाओं को पीजीए में बड़ी संख्या में शामिल होना चाहिए। तभी सामंतवाद, दलाल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का सफाया किया जा सकता है और पितृसत्ता का अंत किया जा

कोंटा क्षेत्र में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का एक दृश्य

भैरमगढ़ इलाके में आयोजित 8 मार्च का एक दृश्य

सकता है। उन्होंने कहा कि महिला मुक्ति की समस्या नवजन क्रांति से जुड़ी हुई है। और महिलाओं की भागीदारी के बिना इस क्रांति की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

सभा के अंत में महिलाओं ने गगन भेदी नारे लगाए–**"घर में महिलाओं की मेहनत की मान्यता हो"; जमीन पर महिला को बराबर का अधिकार दो"; महिला को पुरुष के बराबर अधिकार दो"; जन छापामार सेना को मजबूत करो"; केएएमएस जिंदाबाद"; हरेक महिला एक छापामार बने"** आदि।

इस सभा में कुल 1,400 आदिवासी महिलाओं ने भाग लिया। तोंडामरका में आयोजित एक दूसरी सभा में 550 महिलाओं ने तथा करिगुण्डेम में आयोजित सभा में करीब 400 महिलाओं ने भाग लिया।

गोल्लापल्ली रेंज में भी तीन जगहों पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सफलतापूर्वक मनाया गया। तुंगवंग में आयोजित सभा में 15 गांवों की 500 महिलाओं ने भाग लिया, जबकि गंगलेरु में 12 गांवों की 300 महिलाओं ने तथा रंजलबार में 400 महिलाओं और 20 पुरुषों ने भाग लिया।

कोंटा और भेज्जी रेजों मे चार स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस क्रांतिकारी स्फूर्ति के साथ मनाया गया। इन दोनों रेंजों में कुल 3,000 महिलाओं ने अलग-अलग सभाओं में भाग लिया। इन दोनों रेंजों के सभी गांवों से केएएमएस की अध्यक्षों एवं सचिवों को एक दिन राजनीतिक कक्षा चलाई गई। इस कक्षा में उन्हें महिला के सवाल पर पार्टी दृष्टिकोण के बारे में तथा पितृसत्ता के इतिहास के बारे में समझा दिया गया। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में भी उनकी समझ बढ़ा दी गई। उसके बाद उन्होनें सभी गांवों में 3-4 दिन का प्रचार कार्यक्रम चलाया। इस प्रचार के तहत महिलाओं से अंतराष्ट्रीय महिला दिवस को सफल बनाने की अपील की गई।

सभा के पहले कुछ स्थानों पर महिलाओं का खेल-कूद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आदिवासी महिलाओं का उत्साह बढ़ाने, उनकी झिझक को तोड़ने और उनकी रचनात्मक को उभारने के लिए इस तरह का अनोखा *(शेष पृष्ठ 27 पर....)*

माड़ इलाके में महिलओं की भारी उपस्थिति में 8 मार्च का दृश्य

उदारतावाद का विरोध करो!

- कॉमरेड माओ त्से-तुङ

(7 सितम्बर 1937)

हम सक्रिय विचारधारात्मक संघर्ष का समर्थन करते हैं क्योंकि यह एक ऐसा हथियार है जो हमारे संघर्ष के हित में पार्टी की एकता और क्रांतिकारी संगठनों की एकता की गारन्टी कर देता है। हर कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी को चाहिए कि वह इस हथियार का उपयोग करे।

लेकिन उदारतावाद विचार-धारात्मक संघर्ष से इनकार करता है और सिद्धान्तहीन शान्ति का समर्थन करता है; इस तरह यह एक सडे-गले, अधकचरे रुख जन्म देता है और पार्टी व क्रांतिकारी संगठनों की कुछ इकाइयों और व्यक्तियों को राजनीतिक पतन की ओर ले जाता है।

उदारतावाद विभिन्न रूपों में सामने आता है।

यह मालूम होते हुए भी कि सम्बन्धित व्यक्ति स्पष्टतः गलत है, लेकिन चूकि वह पुरानी जान-पहचान का है, एक ही इलाके का है, स्कूली दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है, प्रियजन है, पुराना सहकर्मी है या पहले मातहत रह चुका है, इसलिए उससे सिद्धांत के आधार पर तर्क न करना, बल्कि शांति और मित्रता बनाए रखने के लिए मामले को घिसटने देना। या फिर मामले को महज उपरी तौर पर छू देना, उसका पूरी तरह समाधान न करना जिससे कि अच्छे संबंध बने रहें। नतीजे के तौर पर संगठन तथा संबंधित व्यक्ति दोनों को नुकसान पहुंचना। यह पहली किस्म का उदारतावाद है।

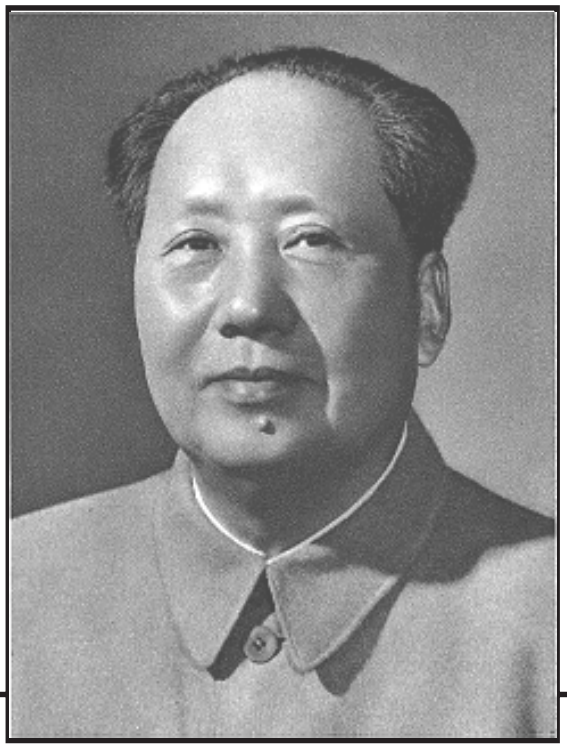

*31 वर्षों के बाद हमारी पार्टी की 9वीं कांग्रेस कामयाबी के साथ संपन्न हुई। आन्दोलन के विकासक्रम में सामने आई विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए इस कांग्रेस ने काफी सफल प्रयास किया। साथ ही, व्यवहार में हुई गलतियों से सबक भी लिया गया। इस कांग्रेस ने साहसपूर्वक नए कार्यभार उठाए हैं, जो आन्दोलन के विकास के लिए जरूरी हैं। लेकिन भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन में ही एक नया मोड़ साबित होने वाले इन नए कार्यभारों और फैसलों पर अमल तभी संभव होगा जब पार्टी अपनी शक्ति को पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा ले। जब तक पार्टी अपनी कमजोरियों और गलतियों को दूर नहीं कर लेती तब तक पार्टी की शक्ति में इज़ाफा नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस ने पार्टी में भूल-सुधार अभियान चलाने का फैसला लिया ताकि पार्टी में उत्पन्न भटकावों को दूर करके आन्दोलन को आगे बढ़ाया जा सके। इसी पृष्ठभूमि में, कॉमरेड माओ त्सेतुङ की 25वीं बरसी के मौके पर हम प्रस्तुत अंक में **उदारतावाद का विरोध करो** नामक उनके प्रसिद्ध लेख के अलावा, **मनोगतवाद पर उनके द्वारा अलग-अलग मौकों पर दी गई सीखें** प्रकाशित कर रहे हैं ताकि पाठकगण उनका अध्ययन कर सकें।* - सम्पादकमण्डल

संगठन के सामने सक्रिय रूप से अपने सुझाव पेश न करके एकांत में गैर-जिम्मेदारी के साथ आलोचना करना। लोगों के मुह पर तो कुछ न कुछ कहना लेकिन पीठ पीछे बुराई करना, या सभा में तो चुप्पी साधे रहना लेकिन बाद में अनाप-शनाप बकना। सामूहिक जीवन के सिद्धांतों को कतई नजरअंदाज करते हुए खुद अपनी मर्जी के मुताबिक चलना। यह दूसरी किस्म का उदारतावाद है।

किसी बात से अगर अपना सीधा ताल्लूक न हो, तो फिर उसकी तरफ से बिलकुल उदासीन हो जाना; यह अच्छी तरह से जानते हुए कि क्या गलत है, उस बारे में कम से कम बोलना; दुनियादारी से काम लेना और अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश करना तथा सिर्फ यह कोशिश करते रहना कि कहीं इलजाम अपने सर पर न आ जाए। यह तीसरी किस्म का उदारतावाद है।

आदेशों का पालन न करना बल्कि खुद अपनी राय को सर्वोपरि रखना। संगठन से अपने प्रति विशेष व्यवहार की मांग करना, पर उसके अनुशासन को मानने से इनकार करना। यह चौथी किस्म का उदारतावाद है।

एकता बढ़ाने, प्रगति करने या काम सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से गलत विचारों के विरुद्ध संघर्ष या वाद- विवाद करने के बजाय व्यक्तिगत आक्षेप करना, झगड़ा मोल लेना, व्यक्तिगत शिकवे- शिकायतों को सामने

लाना या बदला लेना। यह पांचवीं किस्म का उदारतावाद है।

गलत विचारों को सुनकर भी उनका विरोध न करना और यहां तक आगे बढ जाना कि क्रांति- विरोध बातों को सुनकर भी उनके बारे में नेतृत्व को खबर तक न देना, बल्कि चुपचाप बरदाश्त कर लेना, मानो कुछ हुआ ही न हो। यह छठी किस्म का उदारतावाद है।

जनता के बीच रहकर भी प्रचार और आन्दोलन न करना, अथवा भाषण न देना या जांच-पड़ताल और पूछताछ न करना, बल्कि जनता से कोई वास्ता ही न रखना, उसकी सुख- सुविधाओं की तरफ कतई ध्यान न देना; यह भूल जाना कि वह एक कम्युनिस्ट है और इस तरह व्यवहार करना मानो वह कोई मामूली सा गैर- कम्युनिस्ट हो। यह सातवीं किस्म का उदारतावाद है।

यह देखकर भी कि कोई जनता के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्रोध अनुभव न करना, ऐसे आदमी को मना न करना या न रोकना, अथवा उसे न समझाना- बुझाना, बल्कि उसे यह सब करने देना। यह आठवीं किस्म का उदारतावाद है।

बिना किसी निश्चित योजना या निर्देशन के बेमन से काम करना; लापरवाही से किसी न किसी तरह अपनी डयूटी पूरी करते जाना और जैसे-तैसे दिन बिता देना–"जब तक मैं बौद्ध भिक्षु हूं, घंटी बजाता रहूंगा।" यह नवीं किस्म का उदारतावाद है।

अपने बारे में ऐसा समझना कि मैंने क्रांति के लिए भारी योगदान किया है, बहुत तजरबेकार होने की शेखी बघराना, बड़े काम करने के आयोग्य होना मगर फिर भी छोटे कामों को हिकारत की नजर से देखना, काम के प्रति लापरवाह होना और अध्ययन में ढील आने देना। यह दसवीं किस्म का उदारतावाद है।

अपनी गलतियों को जानते हुए भी उन्हें सुधारने का प्रयास न करना और खुद अपने प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना। यह ग्यारहवीं किस्म का उदारतावाद है।

हम उदारतावाद के और भी अनेक रूप गिन सकते हैं। लेकिन ये ग्यारह मुख्य हैं।

ये सब उदारतावाद के रूप हैं।

क्रांतिकारी संगठनों के लिए उदारतावाद अत्यंत हानिकारक होता है। उदारतावाद एक ऐसा घुन है जो एकता को खा जाता है, भाईचारे को कमजोर बना देता है, काम में निष्क्रियता ला देता है और मतभेद पैदा कर देता है। यह क्रांतिकारी पांतों को ठोस संगठन व कठोर अनुशासन से वंचित कर देता है, नीतियों को पूर्णतया लागू होने से रोक देता है और पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली जनता को पार्टी- संगठनों से अलग कर देता है। यह एक हद दर्जे की बुरी प्रवृत्ति है।

उदारतावाद का जन्म निम्न- पूंजीपति वर्ग की स्वार्थपरता से होता है। यह व्यक्तिगत हितों से सर्वोपरि रखता है और क्रांति के हितों को दूसरा स्थान देता है, और यह स्थिति विचारधारात्मक, राजनीतिक व संगठनात्मक उदारतावाद को उत्पन्न कर देती है।

उदारतावादी लोग मार्क्सवाद के सिद्धांत को महज खोखले जड़सूत्रों के रूप में देखते हैं। वे मार्क्सवाद को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल करने या पूर्णतया अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। वे अपने उदारतावाद को हटाकर मार्क्सवाद को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों के पास मार्क्सवाद होता तो है, किन्तु साथ ही साथ उदारतावाद भी होता है- वे बातें तो मार्क्सवाद की करते हैं पर अमल उदारतावाद पर करते हैं; वे दूसरों पर मार्क्सवाद को लागू करते हैं, खुद अपने लिए उदारतावाद बरतते हैं। उनके झोले में दोनों तरह का माल रहता है, जहां जैसा मौका देखा वहां उस तरह का माल भिड़ा दिया। कुछ लागों का दिमाग इसी तरह काम करता है।

उदारतावाद अवसरवाद का ही एक रूप है और मार्क्सवाद का उससे बुनियादी विरोध है। उसका स्वरूप नाकारात्मक है और वस्तुगत रूप में वह शत्रु के लिए सहायक बन जाता है; यही कारण है कि शत्रु हमारे बीच उदारतावाद के बने रहने का स्वागत करता है। जब उसका स्वरूप इस तरह का है, तो फिर क्रांतिकारी पांतों में उसे कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए।

उदारतावाद पर, जो नाकारात्मक भावना है, विजय पाने के लिए हमें मार्क्सवाद का, जो एक सकारात्मक भावना है, इस्तेमाल करना चाहिए। एक कम्युनिस्ट का हृदय विशाल होना चाहिए और उसे निष्ठावान व सक्रिय होना चाहिए, क्रांति के हितों को उसे अपने प्राणों से भी मूल्यवान समझना चाहिए और अपने व्यक्तिगत हितों को क्रांति के हितों से मातहत रखना चाहिए; उसे हर जगह और हमेशा सही सिद्धांत पर डटे रहना चाहिए और सभी गलत विचारों और कामों के विरुद्ध अथक संघर्ष चलाना चाहिए ताकि पार्टी की सामूहिक जिन्दगी और अधिक ठोस बने तथा पार्टी और जन समुदाय के बीच की कड़ियां और अधिक मजबूत हों; उसे किसी व्यक्ति-विशेष से अधिक पार्टी और जन-समुदाय की चिन्ता होनी चाहिए और अपने से अधिक दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ तभी उसे एक कम्युनिस्ट माना जायेगा।

तमाम वफादार, ईमानदार, सक्रिय व सच्चे कम्युनिस्टों को चाहिए कि वे एकताबद्ध होकर हमारे बीच लोगों के अन्दर पैदा हुई उदारतावादी प्रवृतियों का विरोध करें और उन्हें सही रास्ते पर ले आएं। यह विचारधारात्मक मोर्चे पर हमारे कार्यों में से एक है। ❑

मनोगतवाद पर विभिन्न मौकों पर कॉमरेड माओ द्वारा दी गई सीखें

.....किन्तु अन्तरविरोध की विशिष्टता के बारे में बहुत से साथियों के विचार, विशेषकर कठमुल्लावादियों के विचार अब भी साफ नहीं हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि अन्तरविरोध की विशिष्टता में ही अन्तरविरोध की सार्वभौमिकता निहित है। वे यह भी नहीं समझ पाते कि हमारे सामने उपस्थित ठोस वस्तुओं में निहित अन्तरविरोध की विशिष्टता का अध्ययन क्रान्तिकारी व्यवहार को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन करने के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है।

.....

गति के किसी भी रूप के भीतर उसका अपना विशिष्ट अन्तरविरोध निहित होता है। यह विशिष्ट अन्तरविरोध ही किसी वस्तु की विशिष्ट मूलवस्तु को निर्धारित करता है जिससे वह वस्तु सभी वस्तुओं से भिन्न होती है।

.....

हमारे कठमुल्लावादी लोग जहां गलती करते हैं वह यह है कि एक तरफ तो वे यह नहीं समझ पाते कि अन्तरविरोध की सार्वभौमिकता और विभिन्न वस्तुओं की सामान्य मूलवस्तु को पर्याप्त रूप से जानने के पहले हमें अन्तरविरोध की विशिष्टता का अध्ययन करना होगा और अलग-अलग वस्तुओं की विशिष्ट मूलवस्तु को जानना होगा; दूसरी तरफ वे यह नहीं समझ पाते कि वस्तुओं की सामान्य मूलवस्तु को जानने के बाद हमें उन ठोस वस्तुओं के अध्ययन की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए जिनका अभी तक गहन अध्ययन नहीं हुआ है, या जो अभी नई-नई पैदा हुई हैं। हमारे कठमुल्लावादी लोग कामचोर हैं। वे ठोस वस्तुओं का मेहनत के साथ अध्ययन करने से इनकार करते हैं, और सामान्य सत्यों को इस तरह देखते हैं मानो वे शून्य से टपक पड़े हों, और उनको ऐसे विशुद्ध अमूर्त फार्मूलों में बदल देते हैं जो लोगों की समझ में नहीं आते, और इस प्रकार वे उस सामान्य क्रम को, जिसके जरिए मानव सत्य तक पहुंचता है, न केवल पूर्णतया ठुकरा देते हैं, बल्कि एकदम उलट भी देते हैं।

.....

भिन्न-भिन्न अंतरविरोधों को हल करने के लिए भिन्न-भिन्न तरीकों को इस्तेमाल करने का उसूल एक ऐसा उसूल है जिसका पालन मार्क्सवादी-लेनिनवादियों को सख्ती से करना चाहिए। कठमुल्लावादी इस उसूल का पालन नहीं करते; वे यह नहीं समझते कि विभिन्न क्रान्तियों की परिस्थितियां भी भिन्न होती हैं, परिणामस्वरूप वे यह नहीं समझ पाते कि भिन्न-भिन्न तरीकों को इस्तेमाल में लाना चाहिए; इसके विपरीत वे हमेशा एक ऐसे नुस्खे को अपनाते हैं जिसे वे अपरिवर्तनीय समझते हैं और उसे बिना सोचे-समझे हर जगह लागू करते हैं, जिससे क्रांति को नुकसान पहुंचता है या जिस काम को पहले अच्छी तरह किया जा सकता था वह गड़बड़घोटाले में पड़ जाता है।

.....

..... लेनिन ने जब यह कहा था कि ठोस परिस्थितियों का ठोस रूप में विश्लेषण करना ही मार्क्सवाद की सबसे मूलभूत वस्तु है, मार्क्सवाद की जीती-जागती आत्मा है, तो वे ठीक इसी विचार को व्यक्त कर रहे थे। हमारे कठमुल्लावादी लोग लेनिन की शिक्षाओं के विरुद्ध चलते हैं; वे किसी भी वस्तु का ठोस विश्लेषण करने में अपने दिमाग से काम नहीं लेते, अपने लेखों तथा भाषणों में वे हमेशा घिसीपिटी शैली का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें विषय-वस्तु का बिलकुल अभाव होता है, और इस तरह वे हमारी पार्टी में एक अत्यंत बुरी कार्यशैली को जन्म देते हैं।

किसी समस्या का अध्ययन करते समय हमें मनोगतवाद, एकांगीपन और उथलेपन से बचना चाहिए। मनोगतवाद का मतलब है समस्याओं को वस्तुगत ढंग से न देखना, अर्थात उन्हें देखते समय भौतिकवादी दृष्टिकोण का इस्तेमाल न करना

..... एक शब्द में, इसका मतलब है किसी अन्तरविरोध के दोनों पहलुओं की विशिष्टताओं को न समझना। इसी को कहते हैं समस्याओं को एकांगी ढंग से देखना। या यों कहिए कि सम्पूर्ण वस्तु को न देखकर केवल उसके किसी एक अंग को ही देखना, जंगल को न देखकर केवल पेड़ों को ही देखना।

.....

"दुश्मन को पहचानो और खुद अपने को पहचानो, तभी तुम हार का खतरा उठाए बिना सैकड़ों लड़ाइयां लड़ सकते हो।"

.....

..... उथलेपन का मतलब है न तो अन्तरविरोधों की समग्रता की विशिष्टताओं पर विचार करना और न प्रत्येक अन्तरविरोध के दोनों पहलुओं की विशिष्टताओं पर विचार करना; इसका मतलब है किसी वस्तु की बड़ी गहराई से छानबीन करने और उसके अन्तरविरोधों की विशिष्टताओं का बड़ी बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता से इनकार करना तथा उन पर दूर से महज एक सरसरी नजर डालकर और महज उनकी रूपरेखा पर नजर मारते ही उन्हें हल करने (किसी प्रश्न का उत्तर देने, किसी विवाद को निपटाने, किसी काम को पूरा करने, अथवा किसी पौजी कार्यवाही का निर्देशन करने) की कोशिश करने लग जाना। काम करने का यह तरीका हमें अनिवार्य रूप से झंझट में डाल देगा। चीनी कठमुल्लावादी और अनुभववादी साथियों ने ये गलतियां ठीक इसीलिए की हैं कि वे वस्तुओं को मनोगत, एकांगी और उथले ढंग से देखते हैं। एकांगीपन और उथलापन ये दोनों मनोगतवाद ही हैं। हालांकि सभी वस्तुगत पदार्थ वास्तव में एक दूसरे से सम्बन्धित और आन्तरिक नियमों से नियंत्रित करने के बदले उन्हें केवल एकांगी या उथले ढंग से ही देखते हैं तथा न तो उनके अन्तर-सम्बन्धों को समझते हैं और न उनके आन्तरिक नियमों को, और इस प्रकार उनका तरीका मनोगतवादी हो जाता है।

*('**अन्तरविरोध के बारे में**' में, अगस्त 1937)*

.....

यदि मनुष्य अपने काम में सफल होना चाहता है, अर्थात प्रत्याशित परिणाम प्राप्त करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह अपने विचारों को वस्तुगत बाह्य जगत के नियमों के अनुरूप बनाए; अगर उसके विचार इन नियमों के अनुरूप नहीं बनेंगे, तो वह अपने व्यवहार में असफल हो जाएगा।

.....

इसके बाद हम जरा युद्ध पर विचार करें। यदि युद्ध का संचालन करने वालों के पास युद्ध के अनुभव का अभाव है, तो वे आरम्भिक मंजिल में एक विशेष युद्ध का (उदाहरण के लिए पिछले दस वर्षों का हमारा भूमि-क्रांति युद्ध) संचालन करने वाले गम्भीर नियमों को नहीं समझ पाएंगे। आरम्भिक मंजिल में उन्हें केवल लड़ाई के बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं और वे अनेक बार हारते हैं। लेकिन इस तरह के अनुभव से (जीती हुई लड़ाइयों और खासकर हारी हुई लड़ाइयों के अनुभव से) वे समूचे युद्ध के आन्तरिक सूत्र को समझ जाते हैं, अर्थात उस विशेष युद्ध के नियमों को समझ जाते हैं, रणनीति और कार्यनीति को समझ जाते हैं और फलतः बड़े विश्वास के साथ युद्ध का संचालन करने लगते हैं। ऐसे समय में यदि किसी अनुभवहीन व्यक्ति को नायक बना दिया गया, तो वह भी तब तक युद्ध के सच्चे नियमों को नहीं समझ सकता जब तक कि कई बार हार न जाए (अनुभव न प्राप्त कर ले)।

.....

केवल ऐसे ही लोग, जो समस्याओं के प्रति मनोगत, एकांगी और सतही रुख अपनाते हैं, कहीं जाने के बाद वहां की परिस्थिति पर विचार किए बिना, वस्तुओं को समग्र रूप से (उनके समूचे इतिहास और उनकी समूची वर्तमान स्थिति की दृष्टि से) परखे बिना, तथा वस्तुओं के सारतत्व (उनके स्वरूप तथा एक वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच के आन्तरिक सम्बन्धों) तक पहुंचे बिना ही बड़े आत्मसंतोष के साथ आज्ञाएं और निर्देश जारी करते हैं। ऐसे लोगों का ठोकर खाना और गिरना अनिवार्य है।

.....

जब इन्द्रिय-संवेदन की सामग्री बहुत समृद्ध होती है (आंशिक या सम्पूर्ण नहीं होती) और वास्तविकता के अनुकूल होती है (भ्रामक नहीं होती), सिर्फ तभी हम ऐसी सामग्री के आधार पर सही धारणाएं बना सकते हैं और सही तर्क पेश कर सकते हैं।

.....

लेकिन साधारणतः, चाहे प्रकृति को बदलने के व्यवहार में हो चाहे समाज को, ऐसा बहुत कम होता है कि लोगों के मूल विचार, सिद्धान्त, योजनाएं अथवा कार्यक्रम किसी न किसी परिवर्तन के बिना कार्यान्वित हो जाएं। यह इसलिए कि जो लोग वास्तविकता को बदलने में लगे हुए हैं, उनकी बहुत सी सीमाएं होती हैं। उनकी सीमाएं वैज्ञानिक और तकनालाजीकल परिस्थितियों से ही निश्चित नहीं होतीं, बल्कि इस बात से भी निश्चित होती हैं कि वस्तुगत प्रक्रिया का खुद किस हद तक विकास हुआ है और उसने किस हद तक अपने को प्रकट किया है (वस्तुगत प्रक्रिया के विभिन्न पहलू और उसका सारतत्व अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए)। ऐसी स्थिति में, व्यवहार के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियों की जानकारी होने पर विचार, सिद्धान्त, योजनाएं अथवा कार्यक्रम अक्सर आंशिक रूप में और कभी-कभी पूरी तरह से भी बदल दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, होता यह है कि मूल विचार, सिद्धान्त, योजनाएं अथवा कार्यक्रम अंशतः या पूर्णतः वास्तविकता से मेल नहीं खाते, अथवा अंशतः या पूर्णतः गलत होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि गलत ज्ञान को ठीक करने से पहले गलत ज्ञान को बदलकर उसे वस्तुगत प्रक्रिया के नियमों के अनुकूल बनाने के पहले, और फलतः मनोगत चीजों को वस्तुगत चीजों में बदलने के पहले यानी व्यवहार में प्रत्याशित फल पाने के पहले, बार-बार असफलताओं का सामना करना ही पड़ता है। फिर भी इस मुद्दे पर पहुंचने के बाद, चाहे यह कैसे ही हुआ हो, यह समझा जाता है कि किसी वस्तुगत प्रक्रिया के बारे में, जो विकास की किसी एक मंजिल पर हो, मनुष्य की ज्ञानप्राप्ति की क्रिया पूरी हो गई है।

*(**'व्यवहार के बारे में'** में, जुलाई1937)*

..... जब हम यह कहते हैं कि हम किसी समस्या के प्रति मनोगतवादी रवैये के खिलाफ हैं, तो हमारा मतलब यह होता है कि हमें ऐसे विचारों का अवश्य विरोध करना चाहिए जो वस्तुगत तथ्यों पर आधारित नहीं होते या उनके अनुरूप नहीं होते, क्योंकि ऐसे विचार काल्पनिक और झूठे होते हैं, और उन्हें आधार बनाकर कार्यवाही करने से हमें असफलता का मुंह देखना पड़ेगा ..... इस कार्यवाही को कारगर ढंग से चलाने के लिए ऐसे लोग होने चाहिए जो वस्तुगत तथ्यों के आधार पर अपने विचार, सिद्धान्त व मत कायम करते हैं और तब योजनाएं, निर्देशक उसूल, नीतियां रणनीतियां व कार्यनीतियां बनाते हैं। विचार आदि मनोगत चीजें हैं, जबकि प्रयत्न या कार्यवाहियां मनोगत बातों के ही वस्तुगत जाहिरा रूप हैं, लेकिन दोनों ही मानव जाति की विशिष्ट गत्यात्मक भूमिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी गत्यात्मक भूमिका को हम "मनुष्य की जागरूक गत्यात्मक भूमिका" कहते हैं, और यह एक ऐसी विशेषता है जो मनुष्य को अन्य सभी वस्तुओं से भिन्न बना देती है। ऐसे सभी विचार जो वस्तुगत तथ्यों पर आधारित हैं और उनके अनुरूप हैं, सही विचार हैं, और ऐसे सभी प्रयत्न या ऐसी सभी कार्यवाहियां जो सही विचारों पर आधारित हैं, सही कार्यवाहियां हैं।

.....

विजय प्राप्त करने की कोशिश में, जो लोग युद्ध का निर्देशन करते हैं, वे वस्तुगत परिस्थितियों द्वारा निर्देशित सीमाओं को लांघ नहीं सकते; लेकिन इन सीमाओं के भीतर रहते हुए वे विजय प्राप्त करने के प्रयत्न में गत्यात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। किसी युद्ध के कमाण्डरों को अपनी कार्यवाही का मंच वस्तुगत सम्भावनाओं के आधार पर बनाना चाहिए ..... इसी कार्य में युद्ध का निर्देशन करने की हमारी मनोगत योग्यता का इस्तेमाल हो सकता है और होना भी चाहिए। हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि हमारा कोई भी कमाण्डर अपने को वस्तुगत

परिस्थितियों से अलग करके अन्धाधुन्ध कार्यवाही करने वाला एक अति-उतावला व्यक्ति बन जाए, लेकिन हम इस बात का जरूर समर्थन करते हैं कि हमारा प्रत्येक कमाण्डर एक ऐसा सेनानी बन जाए जो साहसी और विवेकशील दोनों हो। हमारे कमाण्डरों में केवल दुश्मन को तबाह कर देने का साहस ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उनमें सम्पूर्ण युद्ध में होने वाले परिवर्तनों और फेर-बदल के दौरान स्थिति पर पूरा नियंत्रण रखने की योग्यता भी होनी चाहिए।

('दीर्घकालीन युद्ध के बारे में' में, मई 1938)

.....

यह गंभीर उसूली गलती, जो चीन के क्रान्तिकारी युद्ध की विशिष्टताओं की गैरजानकारी के कारण हुई और "घेरा डालने और विनाश करने" की पांचवीं मुहिम के खिलाफ संघर्ष में व्यक्त हुई, मनोगत तथा वस्तुगत स्थितियों की उपेक्षा करने वाले "वामपंथी" उतावलेपन के रुझान की गलती थी। यह रुझान क्रान्तिकारी युद्ध को हद दरजे का नुकसान पहुंचाता है तथा हर किसी क्रान्तिकारी आन्दोलन को भी नुकसान पहुंचाता है।

अध्ययन

क्रांतिकारी सिद्धान्त को आत्मसात किए बिना, इतिहास का ज्ञान प्राप्त किए बिना और वास्तविक आन्दोलन की गहरी समझ हासिल किए बिना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक महान क्रांतिकारी आन्दोलन को विजय तक ले जाना असम्भव है।

मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्तालिन के सिद्धान्त सभी जगह लागू होते हैं। हमें इन सिद्धान्तों को जड़सूत्र नहीं समझना चाहिए बल्कि अपने समस्त कार्यों का पथ-प्रदर्शक मानना चाहिए....

.....चीनी कम्युनिस्टों के लिए, जो महान चीनी राष्ट्र के अंग हैं, और उसके साथ हाड़-मांस की तरह जुड़े हुए हैं, चीन की विशिष्टताओं से अलग मार्क्सवाद की कोई भी चर्चा करना केवल हवाई मार्क्सवाद, खोखला मार्क्सवाद है। इसलिए मार्क्सवाद को चीन में ठोस रूप से लागू करना ताकि उसकी हर अभिव्यक्ति में निस्सन्देह चीन की विशिष्टताओं के प्रकाश में लागू करना, पूरी पार्टी के लिए शीघ्र ही समझ लेने और हल करने का एक मसला बन गया है। विदेशी घिसेपिटे लेखन को मिटा देना चाहिए, खोखले और हवाई राग कम आलापने चाहिए और कठमुल्लावाद को ताक पर रख देना चाहिए; इनके स्थान पर नवीन और जीवन्त चीनी ढंग व भावना अपनानी चाहिए, जिन्हें चीन की आम जनता पसन्द करती है। अन्तरराष्ट्रवाद की अंतर्वस्तु को राष्ट्रीय रूप से अलग करना उन लोगों का व्यवहार है जो अंतरराष्ट्रवाद की प्रारंभिक बात भी कतई नहीं समझते। इसके विपरीत हमें इन दोनों को घनिष्ठ रूप से जोड़ना चाहिए। इस मामले में हमारी पांतों में गम्भीर खामियां हैं, जिन्हें संजीदगी के साथ दूर करना चाहिए।

('राष्ट्रीय युद्ध में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका' में, अक्टूबर 1938)

जांच-पड़ताल नहीं तो बोलने का अधिकार नहीं।

.....आप एक समस्या की जांच-पड़ताल नहीं करेंगे, तो उस समस्या पर बोलने के अधिकार से वंचित होंगे। क्या यह बहुत कठिन लग रहा है? बिलकुल नहीं। यदि आप एक समस्या की तह में जाकर, उसकी वर्तमान वास्तविकताओं और उसके पुराने इतिहास में जाकर उनकी छानबीन नहीं करते और उसके मुख्य पहलुओं के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो उस पर जो भी बोलेंगे वह सब बेशक बेमतलब ही होगा। बेमतलब की बातें करने से किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। यह सभी जानते हैं....

यदि वास्तविक हालत के बारे में जांच-पड़ताल नहीं की जाती है, तो तब वर्गीय बलों के बारे में आदर्शवादितापूर्ण आकलन, कार्य में आदर्शवादितापूर्ण मार्गदर्शन जरूर होंगे। इससे या तो अवसरवाद या फिर दुस्साहसिकवाद को जगह मिलेगी।

क्या इस निष्कर्ष पर आपको कोई शक है? सचाइयां आपको यह स्वीकार करने पर गरदन झुकवाकर मजबूर कर देती हैं। बिना किसी जांच-पड़ताल के हालत के बारे में अनुमान लगाने की थोड़ी सी कोशिश करके देखिए भला या संघर्ष का कुछ मार्गदर्शन करके देखिए भला। तब आप खुद ही पाते हैं कि उस तरह का आकलन या उस तरह का मार्गदर्शन कैसा बेबुनियाद और आदर्शवादितापूर्ण होता है। आप खुद ही परखकर देखिए कि क्या उससे अवसरवादी गलतियां या दुस्साहसिकवादी गलतियां होंगी कि नहीं। निश्चित रूप से उससे वही गलतियां होंगी। इसका कारण यह नहीं है कि कार्यवाही करने से पहले सही योजनाएं नहीं बनाई गई हों। सामाजिक हालात का ठोस रूप में अध्ययन करने में हुई विफलता ही इसका कारण है।

सामाजिक-आर्थिक जांच-पड़ताल का लक्ष्य यह है कि वर्गीय ताकतों के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंचना, और उसके बाद सही कार्यनीतियां तय कर लेना। समाज में मौजूद विभिन्न वर्गों के राजनीतिक-आर्थिक हालात के बारे में जान लेना ही हमारा प्रमुख मकसद है। हमारी जांच-पड़ताल का यह नतीजा होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग की ताजी हालत और उसके विकास में उतार-चढ़ावों की तसवीर सामने आए .... समाज में मौजूद अलग-अलग वर्गों के बीच आन्तरिक सम्बन्धों के बारे में समझ लेना; वर्गीय ताकतों के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंचना; और बाद में कौन-कौन से वर्ग क्रांतिकारी संघर्ष में बतौर प्रधान बल होंगे, किन-किन वर्गों को दोस्त बना लेना चाहिए और किन-किन वर्गों का सफाया करना होगा, यह बताते हुए संघर्ष की सही कार्यनीतियां तय कर लेना - इस अन्तिम लक्ष्य के साथ समाज के विभिन्न वर्गों की छानबीन करना ही हमारी जांच-पड़ताल का मुख्य तरीका होना चाहिए। हमारा एक मात्र लक्ष्य यही है।

('ग्रन्थ-पूजा का विरोध करो' में, मई 1930)

.....

मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्तालिन ने हमें यह सिखाया है

कि वस्तुगत यथार्थ को आधार बनाकर हमें ऐसे नियम निर्धारित करने चाहिए जो हमारी कार्यवाही का मार्गदर्शन कर सकें। इस उद्देश्य के लिए, जैसा कि मार्क्स ने कहा है, हमें सामग्री को विस्तार के साथ अपने हाथ में लेना चाहिए तथा उसका वैज्ञानिक विश्लेषण और संश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहिए। हमारे अनेक लोग इस ढंग से कार्य नहीं करते, बल्कि इसका उलटा करते हैं। उनमें से काफी लोग अनुसंधान-कार्य में तो लगे हुए हैं लेकिन आज के चीन या अतीत के चीन का अध्ययन करने के प्रति उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उनकी दिलचस्पी केवल उन खोखले 'सिद्धान्तों' के अध्ययन करने तक ही सीमित है जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। बहुत से अन्य लोग व्यावहारिक कार्य में लगे हुए हैं, किन्तु वे भी वस्तुगत परिस्थितियों का अध्ययन करने की ओर ध्यान नहीं देते, बल्कि केवल भावावेश में आकर कार्य करते हैं और नीति की जगह व्यक्तिगत भावनाओं को प्रतिष्ठित कर देते हैं। ये दोनों ही प्रकार के लोग मनोगततत्व पर निर्भर रहते हैं और वस्तुगत यथार्थ के अस्तित्व को नजरअन्दाज कर देते हैं।

*('**अपने अध्ययन में सुधार करो**' में, मई1941)*

.....

सोवियत संघ के उन्नत अनुभव का अध्ययन करने में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उसे हमारे खुद की स्वतंत्र व रचनात्मक उपलब्धियों के साथ जोड़ना चाहिए। मार्क्सवाद के सार्वभौमिक सचाई को चीनी व्यवहार के साथ जरूर जोड़ा जाना चाहिए। हमें पहले से बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो हमें पराजय का मुंह देखना पड़ता है।

*('**सैनिक मामलों की कमेटी की विस्तृत बैठक में दिया गया भाषण**' में, 28 जून 1958)*

.....

चीनी कठमुल्लावाद की उसकी अपनी चीनी विशिष्टताएं हैं। इनकी अभिव्यक्ति युद्ध में भी और धनी किसानों के सवाल पर भी देखी गई। चूंकि धनी किसानों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हमने सिद्धान्ततः यह तय किया कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए और उनके लिए कुछ रियायतें दी जाएं। लेकिन 'वामपंथियों' ने नहीं माना। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'धनी किसानों को खराब जमीन दी जाए और जमींदारों को कोई जमीन नहीं दी जाए।' इसके परिणामस्वरूप जमींदारों को खाने को कुछ नहीं रहा, तो उनमें से कुछ लोगों ने पहाड़ों में भागकर छापामार डाकू गिरोहों का गठन किया। पूंजीपति वर्ग के सवाल पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सत्ता को पलटकर, राजनीतिक और आर्थिक रूप में भी उनका नाश किया जाए। इस तरह उन्होंने जनवादी क्रांति और समाजवादी क्रांति को अस्त-व्यस्त कर दिया। उन्होंने साम्राज्यवाद को क्वोमिंताङ का समर्थन कर रहा एक समान अविभाजित पक्ष मानते हुए उसका कोई विश्लेषण नहीं किया।

*('**चेङतु अधिवेशन के भाषण**' में, मार्च 1958)*

★ ★

(.... पृष्ठ 21 का शेष)

कार्यक्रम आयोजित किया गया। खो-खो, कबड्डी, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ आदि स्पर्धाओं में विजेताओं को छुरी जैसे पुरुस्कार भी रखा गया। इस कार्यक्रम के बाद महिलाओं ने जुलूस निकाला। लाल झण्डों और बैनरों से लैस महिलाओं ने जुलूस के दौरान गगनभेदी नारे लगाए। बाद में आमसभाएं हुई।

गांव इरपट्टी में आयोजित सभा में 760 महिलाओं ने भाग लिया। इस सभा को केएएमएस रेंज कमेटी अध्यक्षा कॉ. कन्नील और रेंज कमेटी सदस्या कॉ. बुधरी ने संबोधित किया। केवल महिलाएं ही इस सभा में उपस्थित हुईं।

गांव गामागोडा में आयोजित सभा में कुल 1315 महिलाओं ने भाग लिया। इस सभा को कॉ. ध्रुवे, बंडी, देवे और अड़मे ने संबोधित किया। महिलाओं की भारी उपस्थिति ने सभी को उत्साहित किया।

कोंटा रेंज के ग्राम कामराजू मे आयोजित सभा में 440 महिलाओं की उपस्थिति रही। उन सभाओं को केएएमएस की नेता कॉ. कन्नील और कॉ. मुल्ली ने संबोधित किया।

गुम्पाड़ गांव में आयोजित सभा में 420 महिलाओं ने भाग लिया। इस सभा को भी केएएमएस के नेताओं ने संबोधित किया। इन सभी सभाओं में वक्ताओं ने अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व के बारे में दण्डकारण्य में जारी महिला आंदोलन के बारे में तथा पीजीए में भर्ती होकर देश की मुक्ति के साथ-साथ महिला मुक्ति के लिए लड़ने की जरूरत के बारे मे महिलाओं को अवगत कराया गया। इन सभाओं से इस क्षेत्र की महिलाएं बेहद प्रभावित हुईं और उनका संघर्ष संकल्प दुगुना हो गया।

पश्चिम बस्तर डिवीजन

पश्चिम बस्तर डिवीजन के भैरमगढ़ इलाके में कई रेन्जों में हजारों महिलाओं ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। 8 मार्च के पहले ही पूरे इलाके में केएएमएस की कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर प्रचार अभियान चलाया। इस प्रचार में उन्होंने लोगों को पर्चे बांटे और जगह-जगह पर पोस्टर और बैनर लगाए। गंगलूर रेंज के परालनार गांव में 7 गांवों से आई 1,050 महिलाएं इकट्ठी होकर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। बीजापुर रेंज के मानकेल गांव में आयोजित सभा में 15 गांवों से आई 800 महिलाओं ने भाग लिया। इसी रेंज के कमका गांव में 8 गांवों की 1,200 महिलाओं ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। साथ ही, भैरमगढ़ रेंज के अलुवुरू गांव में 3,000 महिलाओं ने एक विशाल सभा में भाग लिया। इसी रेंज के पिण्डुम गांव में आयोजित एक और विशाल सभा में 3,500 महिलाओं और 1,500 पुरुषों ने भाग लिया। ❑

टर्की में कम्युनिस्ट आन्दोलन का इतिहास

दुनिया में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर बसे देशों में टर्की एक है। उसकी आबादी 6.2 करोड़ की और क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर का है। वह यूरोप और मध्य पूर्व से जुड़ा हुआ है। वह बाल्कन देशों और पूर्वी यूरोप से भी सटा हुआ है और उत्तरी अफ्रीका के लिए वह पुल भी कहलाता है। टर्की के साथ 7 देशों-ग्रीस, बुल्गारिया, जार्जिया, अरमेनिया, इरान, इराक, और सिरिया की सीमाएं लगी हुई हैं। इसके अलावा उत्तर में कालासागर और पश्चिम में भूमध्यसागर स्थित हैं। टर्की में क्रांति से उस पूरे क्षेत्र में–यूरोप, बाल्कन क्षेत्र, मध्य एशिया, मध्यपूर्व और कुछ हद तक उत्तरी अफ्रीका में–जबरदस्त असर पडेगा।

हालांकि अधिकांश आबादी मुसलमानों की है, फिर भी 30 लाख ईसाइयों की भी उल्लेखनीय आबादी है। अपने सामरिक महत्व के चलते इज्राएल के बाद टर्की ही इस क्षेत्र में अमरीकी साम्राज्यवाद का गढ है। इसलिए टर्की का माओवादी आन्दोलन विश्व क्रांति में भौगोलिक व राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्व रखता है।

कॉमरेड इब्राहिम कैपक्काया

इतिहास

टर्की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में अजेरबाइजान में आयोजित एक मीटिंग में हुई थी। जब वे वापस लौट रहे थे सभी 13 कॉमरेड कालासागर क्षेत्र में मारे गए थे। उनमें उनके नेता मुस्तफा सफी भी शामिल थे। 1960 के दशक तक टर्की में एक संशोधनवादी पार्टी रहा करती थी। चीन के महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति ने टर्की के क्रांतिकारियों को बेहद प्रभावित किया था। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के दौरान वहां एक जुझारू साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन खडा हुआ था, जिसने सुधारवादी आन्दोलन के नेतृत्व को चुनौती दी। 1970 के दशक में, इस उभार में से तीन जुझारू संगठन खड़े हो गए। विश्वविद्यालय के छात्रों की पहलकदमी ही इसमें प्रमुख थी। वे थे:

1) टीएचकेओ (टर्की जनता की मुक्ति सेना)–जो एनवर हॉक्सा (अलबानिया) का समर्थन करने लगा।

2) टीएचकेपी-सी; अब डीएचकेपी-सी (क्रांतिकारी जन मुक्ति सेना-मोर्चा)–क्यूबा समर्थित।

3) टीकेपी/एमएल–टर्की की कम्युनिस्ट पार्टी/मार्क्सवादी-लेनिनवादी

1960 के दशक मे तत्कालीन टीएचकेपी (टर्की की मजदूर-किसान पार्टी) के भीतर केमालवाद, राष्ट्रीयता सवाल (खासतौर पर कुर्द), टर्की का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण क्रांति का पथ आदि सवालों पर तीखी बहसें होती रहीं। नौजवान कॉमरेड इब्राहिम कैपक्काया ने सुधारवादियों के खिलाफ क्रांतिकारियों के विचारधारात्मक संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ओट्टोमन साम्राज्य के दौरान टर्की एक सामंती और उपनिवेशी देश था जो केमाल पाशा के शासन में एक अर्ध-सामंती और अर्ध-उपनिवेशी देश बन गया। जबकि सभी दूसरे लोगों ने केमालवाद को प्रगतिशील बताया, कैपक्काया ने उसे फासीवादी करार दिया। वह कैपक्काया ही थे जिन्होंने पहली बार टर्की में राष्ट्रीयता के सवाल पर वैज्ञानिक समझ पेश की। कुर्द और तुर्क–दो राष्ट्रीयताओं को पहचान लिया गया। दूसरी सभी क्रांतिकारी ताकतें सामाजिक अंध-राष्ट्रवादी थीं क्योंकि किसी ने भी कुर्द राष्ट्र को मान्यता नहीं दी। महज उसे अल्पसंख्यक समुदाय माना। उन्होंने विचारधारात्मक और संगठनात्मक सवालों पर मार्क्सवाद और संशोधनवाद के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींचते हुए क्रांति की बुनियादी माओवादी रणनीति पेश की। हालांकि कई निम्न-पूंजीपति क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष को स्वीकार किया, लेकिन सभी ने चे गुवेरा के 'फोकोवादी' सिद्धांतों का इस्तेमाल किया, जबकि वह कैपक्काया ही थे जिन्होंने दीर्घकालीन जनयुद्ध का रास्ता पेश किया। इनमें से अधिकतर गुट माओ से प्रभावित तो थे, लेकिन किसी ने भी मार्क्सवाद में उनके योगदान को स्वीकार नहीं किया। वह कैपक्काया ही थे जिन्होंने यह बताया कि माओ त्सेतुङ की विचारधारा मार्क्सवाद के विकासक्रम का उच्चतर चरण था।

1. मेहमट डेमिरडैग
2. उमित सान कग्लायान
3. उमित दिनलेर
4. दिलेक कोनुक
5. तुरन सलमान
6. ओज़गार के. काराबुलुत

कॉमरेड कैपक्काया के नेतृत्व में सुधारवादी टीएचकेपी(फिलहाल मजदूर पार्टी-इशि पार्टिसि कहलाती है) को तोडकर 24 अप्रैल 1972 को टीकेपी/एमएल की स्थापना की गई। पार्टी प्रधान है, सेना प्रधान है, देहाती क्षेत्र प्रधान है आदि 11 नियम कामरेड कैपक्काया ने बताए ताकि आन्दोलन का मार्गदर्शन किया जा सके। बदकिस्मती से 1973 के प्रारंभ में दुश्मन के साथ हुई एक मुठभेड़ में घायल हुए थे। हालांकि वह भागने में सफल हुए थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। और महीनों तक क्रूरतम यातनाएं दी गईं। उनसे संगठन के संबंध में एक भी रहस्य उगलवाने में विफल होने वाले फासीवादी टर्की राज्य ने 18 मई 1973 को दियरबकिर (देरसिम इलाका) की कालकोठरी में उनकी हत्या कर दी। उस समय वह मात्रा 24 साल के थे।

कैपक्काया की शहादत से पार्टी केन्द्रीय नेतृत्व से वंचित हो गई, फिर भी केन्द्र की स्थापना करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्थानीय संगठनों का विकास होता रहा। लेकिन 1976 में पार्टी को पहली गम्भीर फूट का सामना करना पड़ा। जनता की एकता (हल्किन बिरिलिगि) के नाम से गठित धड़े ने पार्टी की बुनियादी राजनीतिक व संगठनात्मक लाइन का विरोध किया। यह अलबानिया-समर्थित संशोधनवादी गुट 1994 तक टीकेपी/एमएल आन्दोलन (हरेकेटि) के नाम से काम करता रहा, जब उसने एक और गुट के साथ मिलकर अपना नाम एमएलकेपी बदला। 1978 में पार्टी का पहला आधिवेशन संपन्न हुआ जिसने एक मजबूत दक्षिणपंथी भटकाव (शांतिपूर्ण मार्ग का) के खिलाफ लड़ते हुए नेतृत्व को गोलबंद किया। लेकिन केन्द्रीय कमेटी की चौथी मीटिंग में वह मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी लाइन से दूर हो गई और दक्षिणपंथ की गिरफ्त में चली गई। जनयुद्ध के स्वीकृति के बावजूद, वह महज सिद्धांत ही बनकर रह गया, अतः इसके बावजूद कि देश 12 सितंबर 1980 की फौजी तख्तापलट की ओर अग्रसर था, केन्द्रीय कमेटी में हावी रही दक्षिणपंथी रुझान के चलते पार्टी ने कोई तैयारी नहीं की।

12 सितंबर की तख्तापलट के तुरंत बाद सभी क्रांतिकारी संगठनों पर व्यापक हमला छेड़ दिया गया। वह हमला कत्लेआमों, यातनाओं, खुलेआम दी जाने वाली फांसी की सजाओं तक ही सीमित न था, इसके साथ-साथ एक आर्थिक, राजनीतिक,

पीकेके के बारे में .....

दो साल पूर्व तक टीकेपी/एमएल ने पीकेके को पृथक कुर्द राष्ट्र के लिए लड़ रही राष्ट्रीय क्रांतिकारी पार्टी माना। लेकिन तबसे वह राष्ट्रीय सुधारवादी पार्टी में तब्दील हो गई।

पीकेके के नेता ओचलिन की गिरफ्तारी के बाद बड़ी तेजी से उसका पतन हो गया। हालांकि पीकेके के दोहरे चरित्र के चलते आत्मसमर्पण की संभावना पहले से दिख रही थी, लेकिन यह अनुमान कभी नहीं लगाया गया था कि सिर्फ एक माह में वह सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करगी। दूसरों के लिए, जैसे कि फिलिस्तीन के आत्मसमर्पण की प्रक्रिया मे कई साल लगे थे, यानी विचारधारात्मक आत्मसमर्पण से फौजी आत्मसमर्पण तक।

ओचलिन के बाद पीकेके के नेतृत्व ने आत्मसमर्पण किया। उनके 10,000 छापामार बलों में एक तिहाई को भंग किया गया और बाकी बचे बलों में अधिकांश को दूसरे देशों में भेजा गया। सिर्फ 150 छापामारों को टर्की में रखा गया ताकि सच्चे योद्धाओं का सफाया किया जा सके। जो कुर्दिस्तान की आजादी के लिए हथियारबंद लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, उन्हें पीकेके के नेतृत्व ने चिन्हित करके मार डाला। इस तरह आत्मसमर्पण के बाद पीकेके के 300 छापामारों को मार डाला गया। देरसिम क्षेत्र में दो केन्द्रीय कमेटी सदयों की भी हत्या की गई क्योंकि वे हथियारबंद लड़ाई जारी रखना चाहते थे।

लेकिन कई छापामारों ने 'पीकेके के क्रांतिकारी लाइन के योद्धाओं' के नाम से खुद को संगठित करके प्रतिरोध को जारी रखा हुआ है।

इसके पहले पीकेके के खिलाफ 10 लाख तुर्क सेना में से 3½ लाख बल तैनात थे। अब रातों-रात इनके बड़े हिस्से को मुक्त किया गया है। और अब इन्हें मुख्य रूप से टीकेपी/एमएल के खिलाफ केन्द्रित किया जाएगा। ❑

विचारधारात्मक और सांस्कृतिक हमला भी छेड़ा गया था। कई नेताओं ने देश छोड़ दिया और कई अन्य निष्क्रिय हो गए।

इसके बावजूद जनवरी 1984 में पार्टी का दूसरा अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन ने एनवर हॉक्सा समर्थित गुट के हमलों के खिलाफ माओवादी लाइन को दृढ़तापूर्वक ऊंचा उठाया। हालांकि इसने हथियारबंद लड़ाई पर जोर दिया, लेकिन अधिवेशन में किया गया देश का ठोस विश्लेषण टर्की के वास्तविक हालात से काफी दूर था।

दूसरे अधिवेशन के तुरंत बाद इसकी केन्द्रीय कमेटी सदस्य भी या तो गिरफ्तार कर लिए गए या झड़पों में मारे गए। पार्टी के महासचिव कॉमरेड सुलेमान सिहान 1981 में ही गिरफ्तार किए गए और उन्हें क्रूर यातनाएं देकर मार डाला गया। पार्टी ने केन्द्रीय कमेटी के अधिकांश सदस्यों को खो दिया। नए सदस्यों को सहयोजित किया गया। फिर एक बार पार्टी की लाइन दक्षिणपंथ की तरफ मुड़ी और छापामार लड़ाई की गति धीमी हो गई। फासीवादी दमन के चलते संगठन को झटका लगा। और राजनीतिक व विचारधारात्मक भटकाव ने हालत और भी बिगाड़ दी।

राजनीतिक उलझन के बीचोंबीच, जबकि दोनों वामपंथी और दक्षिणपंथी भटकाव पार्टी को गंभीरता से प्रभावित कर रहे थे, 1987 में पार्टी का तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। देरसिम को, जहां अधिवेशन होने वाला था, जा रहे सात अधिवेशन-प्रतिनिधि शहीद होने के बाद दक्षिणपंथी अवसरवाद के खिलाफ आलोचना और भी तीखी हो गई। इस अधिवेशन ने तय किया कि छापामार लड़ाई प्रमुख कार्य है। लेकिन इस अधिवेशन में दो धाराएं मौजूद थीं। अपने को डीएबीके कहने वाले लोगों का सैनिकी रुझान वह दूसरी धारा थी। अधिवेशन में एकजुट रहने के बावजूद बाद में वह गुट अलग हो गया।

1991 में चौथा अधिवेशन आयोजित किया गया जबकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद पर व्यापक हमला किया जा रहा था। इस अधिवेशन ने क्रांतिकारी मार्क्सवाद को दृढ़ता से थाम लिया और हालिया पराजय को अस्थायी करार दिया। इसने देश में फैलाए जा रहे राष्ट्रीयतावादी रुझानों का विश्लेषण किया और प्रमुख काम के तौर पर यह स्वीकार किया गया कि छापामार लड़ाई को जारी रखा जाए ताकि लाल राजनीतिक सत्ता को छीन लिया जा सके। अधिवेशन ने फैसला किया कि डीएबीके के साथ एकजुटता कायम की जाए जो 1987 में पार्टी से अलग हुई थी। इसके लिए एक एकता आयोग का चुनाव किया गया ताकि तैयारियों को अंजाम दिया जा सके।

अप्रैल 1993 में पार्टी ने डीएबीके के साथ दोबारा एकता बना ली। मई-जून 1993 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया ताकि समस्याओं को दूर किया जा सके और एकता को मजबूत किया जा सके। इस अधिवेशन द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला यह था कि माओ त्सेतुङ विचारधारा को माओवाद में बदल दिया जाए। अधिवेशन ने यह विश्लेषण किया कि हालांकि माओ त्सेतुङ विचारधारा के सारतत्व को सही तरीके से समझ

लिया गया था, लेकिन उसका सूत्रीकरण अधूरा था। लेकिन डीएबीके के साथ समस्याएं बनी रहीं और 1994 में वह फिर एक बार अलग हो गई। अपने नाम में 'एमएल' शब्द को कोष्ठक में रखकर वह अभी भी वजूद रख रही है।

इस दौरान पार्टी ने अपने दूसरे विशेष अधिवेशन की तैयारी कर ली ताकि पिछले 10 सालों के इतिहास का विश्लेषण करते हुए गहन भूल-सुधार आन्दोलन को चलाया जा सके। अगस्त 1995 में यह अधिवेशन आयोजित किया गया और चोटी से लेकर एड़ी तक भूल-सुधार अभियान चलाने का फैसला लिया गया, यानी खुद केन्द्रीय कमेटी ने इसकी शुरूआत की। इसमें गलतियों का विचारधारात्मक, राजनीतिक और संगठनात्मक आधार को पहचान लिया गया। पार्टी के भीतर दक्षिणपंथी अवसरवाद का खण्डन किया गया और सभी किस्म के परिसमापनवाद को खत्म किया गया। अन्तरराष्ट्रीय रंगभूमि में पार्टी की खामियां और गलत धारणाओं के लिए आत्माआलोचना की गई तथा आवश्यक सावधानियां बरतने का फैसला लिया गया। इस अधिवेशन और भूल-सुधार आन्दोलन ने पार्टी में नई जान फूंक दी।

मौजूदा हालत

पार्टी की एक केन्द्रीय कमेटी है जिसके नेतृत्व में एक पांच क्षेत्रीय (रीजिनल) कमेटियां मौजूद हैं। उसके सभी सदस्य पेशेवर क्रांतिकारी हैं और हमदर्दों का एक व्यापक ढांचा पार्टी को है। एक मुसलमान देश होने के बावजूद पार्टी और सेना में महिलाओं की बड़ी संख्या है। पार्टी के ऊंचे पदों पर भी महिलाएं हैं। महिला काडरों को खासतौर पर प्रोत्साहन दिया जाता है।

पार्टी का एक हथियारबंद विभाग है–टिक्को (टर्की के मजदूर-किसानों की मुक्ति-सेना)। टिक्को का अपना सैन्य संविधान है। टर्की के दो क्षेत्रों–तुर्क कुर्दिस्तान और कालासागर क्षेत्र–में सशस्त्र संघर्ष चालाया जा रहा है। सैन्य कमिशन के अलावा एक जनरल कमाण्ड भी है जिसके मातहत सेना काम करती है। 1998 अधिवेशन के बाद कालासागर क्षेत्र में काम शुरू किया गया। और यहां कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की गईं। पूर्वी टर्की के तुर्क कुर्दिस्तान इलाके में पार्टी लंबे अरसे से काम कर रही है, लेकिन इस क्षेत्र में कई नुकासानों का सामना करना पड़ा। दोनों क्षेत्रों का अधिकांश भाग पहाड़ी है जहां की धरती पर साल में तीन महीनों से ज्यादा समय तक घना बर्फ रहता है। दोनों क्षेत्रों में दुश्मन के तेज दमन का सामना करना पड़ता है। कुर्द राष्ट्रीयता आन्दोलन के अस्थायी विघटन और पीकेके नेतृत्व की गद्दारी के चलते (देखें बॉक्स) अब सरकार अपने बलों को माओवादियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सक रही है।

हथियारबंद संघर्ष के इलाकों के अलावा टीकेपी/एमएल का सर्वहारा वर्ग और नौजवानों में, खासतौर पर अंकारा और इस्तांबुल शहरों में, गतिविधियों का एक विशाल ढांचा है। सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों में पार्टी ने अपनी पैठ बना ली और मजदूरों के बीच कुछ मजबूत मजदूर संघों का भी निर्माण किया। छात्रों और नौजवानों पर पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पार्टी के समर्थन में विश्वविद्यालय के छात्रों का स्थान सबसे ऊपर है।

टर्की में पत्रिकाओं का एक व्यापक ढांचा भी है जो पार्टी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा है। एक पत्रिका 'कम्युनिस्ट' जो सिर्फ पार्टी सदस्यों और नजदीकी हमदर्दों में वितरित की जाती है। जन-समुदायों में बांटने के लिए 'इक्कालाइ' नामक गैर-कानूनी पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाले कानूनी जन अखबार की 20,000 प्रतियां टर्की में और 4000 प्रतियां यूरोप में बिकती हैं। पार्टी 'कम्युनिस्ट यूथ' के नाम से एक गैर-कानूनी मासिक भी प्रकाशित करती है। 'न्यूडेमोक्राटिक यूथ' नामक कानूनी पत्रिका भी प्रकाशित करती है जो दो माह में एक बार निकलती है। इसके अलावा, मजदूरों और कामगारों के लिए एक मासिक और दो माह में छपने वाली सांस्कृतिक पत्रिका भी हैं। 'न्यू वुमन' एक महिला पत्रिका है जो टर्की और यूरोप में प्रकाशित की जाती है। इनके अलावा क्षेत्रीय और जिला स्तर की बहुत सी पत्रिकाएं हैं। टर्की में एक बढ़ता जनवादी आन्दोलन भी मौजूद है जो टर्की में लगातार चल रहे जनयुद्ध का समर्थन करता है। वकीलों के कई संगठन हैं जो संघर्षरत जनता की सहायता करते हैं। वे मानवाधिकारों का बचाव करते हैं और राजकीय बर्बरताओं के खिलाफ अनेक जांच-रिपोर्टें पेश करते हैं। देर से सही, इसे जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई है, क्योंकि आखिर बुजुर्ग लोग भी समर्थक ही नहीं, बल्कि सक्रिय कार्यकर्ता बनकर आगे आ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी को यूरोप में, खासकर जर्मनी में रह रहे निर्वासित विशाल तुर्क/कुर्द आबादी का भी व्यापक समर्थन प्राप्त है।

फिर भी, शहरी इलाकों में निर्माणरत संगठन के ढांचे के बावजूद पार्टी द्वारा तय मुख्य काम हथियारबंद संघर्ष है। दूसरे विशेष अधिवेशन ने स्पष्ट तौर पर बताया कि देहाती इलाकों में काम को केन्द्रित करना है और सभी पार्टी सदस्यों को इसे पहली प्राथमिकता देकर जिम्मेदारी लेनी है। टर्की में माओवादी जनयुद्ध लगातार बढ़ रहा है, भले ही उसे अमरीका और इज्राएल का समर्थन प्राप्त दुनिया के सबसे ज्यादा बर्बर राज्यों में से एक का सामना क्यों न करना पड़ रहा हो। इन बीते चार दशकों के दौरान उसने चार महासचिव, अन्य कई उच्च नेता और 400 से ज्यादा काडर खो दिए। दुनिया के इस सबसे ज्यादा रणनीतिक इलाके में माओवादी आन्दोलन के विकास पर विश्व भर की सच्ची क्रांतिकारी ताकतों की आशाएं टिकी हैं। ❑

मई दिवस के समारोहों में नई विश्वव्यापी लहर

लंदन, बेर्लिन और अन्य जगहों में पिछले साल मई दिवस के अवसर पर किए गए जुझारू विरोध-प्रदर्शनों के बाद, इस वर्ष विरोध-प्रदर्शनों का दायरा और भी ज्यादा व्यापक हो गया। एक दशक पहले पूंजीपतियों ने घोषित किया था कि "कम्युनिज़म मर चुका है" और "इतिहास का अंत हो चुका है।" लेकिन आज मई दिवस के समारोहों में ही नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद-विरोधी प्रदर्शनों में भी हम एक विश्वव्यापी पुनरुत्थान को देख सकते हैं। भूमण्डलीकरण-विरोधी प्रदर्शदनकारियों के खिलाफ पुलिस के भारी बंदोबस्त के बिना साम्राज्यवादी एक भी बैठक आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। नाइस, सिनसिनट्टी और क्यूबेक में की गई शानदार जन-कार्यवाहियों के सिलसिले में अब हारवर्ड में धरना चल रहा है। यहां अमरीका के सबसे संभ्रांत छात्र अपने कैंपस के कर्मचारियों को 'निर्वाह-मजदूरी' की मांग करते हुए दो सप्ताहों से संघर्ष जारी रखे हुए हैं।

इस वर्ष मई दिवस के अवसर पर लाखों लोग सड़कों पर आए। सर्वहारा वर्ग के इस पर्व के मौके पर लंदन, बेर्लिन, जूरिच और ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में दंगा पुलिस के साथ जमकर लड़ाईयां हुईं। जनता ने ठोस मांगों को लेकर प्रदर्शन किए, जैसे कि बेरोजगारी और भूमण्डलीकरण के अन्य प्रभाव के खिलाफ। पारराष्ट्रीय कंपनियों, मैकडोनाल्ड जैसे साम्राज्यवाद के चिन्हों को निशाना बनाया गया-शेयर बाजारों, पारराष्ट्रीय कंपनियों, मैकडोनाल्ड आदि को। "मुनाफे के पहले जनता" जैसे नारों के साथ उन्होंने पर्यावरण, निःशस्त्रीकरण, तीसरी दुनिया की गरीबी, भूमण्डलीकरण का विरोध, पूंजीवाद का विरोध आदि मुद्दों को उठाया।

लंदन

पिछले साल के हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनों के बाद, करीब 10,000 पुलिस वालों को आधुनिक दंगा-विरोधी उपकरणों से लैस करके हजारों प्रदर्शनकारियों के खिलाफ खड़ा किया गया। मध्य लंदन एक सैन्य छावनी जैसा नजर आ रहा था। शुरू में ही हरेक प्रदर्शनकारी की गहन तलाशी ली गई।

लंदन में 10,000 मजदूर कार्यकर्ताओं का जुलूस और एक विशाल साइकिल रैली शांतिपूर्ण तरीके से शुरू किए गए थे, लेकिन बाद में हिंसात्मक रूप लिया। साइकिल चालकों ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया और शहर के यातायात को ठप्प कर दिया। दोपहर के बाद जुलूस ने हिंसात्मक रूप तब लिया जब पुलिस की भारी उपस्थिति ने भीड़ की जुड़ने की कोशिशों को विफल कर दिया। बोतलों, पत्थरों और डंडों का खुलकर प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों नें दुकानों के दरवाजों को तोड़ डाला और कारों को उलट दिया। उन्होंने कूड़े की टोकरियां लेकर बारक्लेस बैंक की खिड़कियों की तरफ बार-बार फेंकीं। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट्स के पास (जहां पर मुख्य पार-राष्ट्रीय कंपनियों की उपभोक्ता उत्पादों की दुकानें और दफ्तर मौजूद हैं) प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के घेरे की तोड़ने की कोशिश की तो मची हाथापाई में 42 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए और 10 घायल हो गए। और ज्यों-ज्यों अंधेरा घिरा प्रदर्शनकारियों के समूहों ने दंगा पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शॉपिंग सड़क में दौड़ते हुए संपत्ति की तोड़फोड़ की।

शेष यूरोप

समूचे यूरोप में मई दिवस के मौके पर लाखों मजदूरों और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने भूमण्डलीय मुक्त-व्यापार के दुष्परिणामों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किए।

सबसे जुझारू कार्रवाई फिर एक बार बेर्लिन में हुई। मई दिवस के समारोहों के दौरान पिछले एक दशक से बेर्लिन की सड़कों पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए देश भर में कोई 9,000 पुलिस बलों को तैनात किया गया। लेकिन शासकों के रवैये से जनता का क्रोध चरम पर जा पहुंचा। सरकार ने फासीवादियों के द्वारा प्रस्तावित रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की आड़ में मजदूरों की रैली पर भी प्रतिबंध लगाया। बाद में अदालतों ने फासीवादियों पर लगे प्रतिबंध को वापस लिया, जबकि मजदूरों पर जारी रखा।

भूतपूर्व पूर्वी बेर्लिन में मुंह अंधेरे ही दो अलग-अलग जगहों पर संघर्ष भड़का–एक जगह बेर्लिन दीवार थी। अंधेरे का फायदा उठाकर सड़कों की नाकेबंदी कर दी गई और अवरोध खड़े किए गए; कुछ में आग लगाई गई। पुलिस के ऊपर पत्थर और बोतले फेंकी गई। मीलों दूर तक रात के अंधेरे में आसमान आग की लपटों से प्रज्ज्वलित हो रहा था। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई लुका-छुपी की लड़ाई में पुलिस ने पानी के तोपों, रबड़ की गोलियों और बख्तरबंद गाड़ियों का प्रयोग किया। 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिररफ्तार किया गया और कई पुलिस वाले घायल हुए।

जर्मनी के कुछ अन्य भागों में भी संघर्ष भड़का। देश भर में मई दिवस की रैलियां निकाली गईं। फ्रांकफर्ट में 100 लोगों को तब गिरफ्तार किया गया जब हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियो ने पुलिस के साथ संघर्ष छेड़ा। हैमबर्ग में भी अवरोध खड़े कर दिए गए जिससे पुलिस के साथ झड़पें हुईं और कुछ गिरफ्तारियां हुईं।

फ्रांस मे देश भर के कई शहरों में ट्रेड यूनियनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकालीं। हाल ही में पार-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नौकरियों में की गई छंटनी को प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मुद्दा बनाया।

जूरिच (स्विट्ज़रलैंड) में आयोजित शहर के परंपरागत मई दिवस जुलूसों के समापन के मौके पर उग्र वाम ग्रुपों और पुलिस के बीच झड़प हुई जिसके बाद कई दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। काले कपड़े और सिर पर नकाब पहने सैकड़ों लोगों

ने पुलिस पर पत्थर और पेन्ट की झिल्लियां फेंकना शुरू किया तो पुलिस ने पानी के तोपों, रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का प्रयोग किया। ऑस्ट्रिया में फासीवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद वाम पंथी पार्टियां सक्रिय हुईं। इसके परिणामस्वरूप मई दिवस पर नौकरी की ज्यादा सुरक्षा की मांग करते हुए एक लाख लोगों ने एक विशाल रैली निकाली। इटली और ग्रीस के कई शहरों में भी विशाल रैलियां निकाली गईं। ग्रीस में मई दिवस के कुछ ही दिन पहले, 26 अप्रैल को मजदूरों ने आम हड़ताल की जिसमें दो लाख मजदूरों द्वारा एथेन्स की सड़कों पर निकाली गई रैली भी शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया

देश भर के कई शहरों में कार्यकर्ताओं ने शेयर बाजारों के दफ्तरों को घेर लिया जिससे पुलिस के साथ झड़पें हुईं। सिडनी,पेर्थ और ब्रिसबेन में पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला करके बीसियों लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से हमले किए। ज्यों-ज्यों दिन चढ़ा प्रदर्शनकारियों ने संसद, बड़े निगमों और सिडनी स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय को अपना निशाना बनाया। मेलबोर्न, केनबेर्रा और एडीलाइड में किये गए प्रदर्शन आम तौर पर शांतिपूर्ण रहे। सिडनी में भूमण्डलीकरण-विरोधी प्रदर्शनकारियों ने घुड़सवार पुलिस वालों के खिलाफ चलते-फिरते लड़ाईयां लड़ीं। दो पुलिस वालों को अस्पताल में दाखिला लेना पड़ा जबकि अन्य 28 को मामूली चोटें आईं। ब्रिसबेन में प्रदर्शनकारियों ने शेयर बाजारों में घुसने का प्रयास किया। मेलबोर्न में 2,000 प्रदर्शनकारियों ने मैक डोनाल्ड रेस्तरां पर नारे फुहारे और प्रधानमंत्री का पुतला जलाया।

विश्व भर में मई दिवस

समूचे रूस में नौकरियों, बेहतर वेतनों और कीमतों के नियंत्रण की मांग करते हुए व्यापक प्रदर्शन किए गए। मॉस्को में ही कई सारी रैलियां निकाली गईं, एक-एक रैली में 15,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। उक्रेइन के कई शहरों में विशाल रैलियां निकाली गईं। वहां के ये विरोध-प्रदर्शन जनता के हाल ही के विरोध संघर्षों के सिलसिले की कड़ी ही थे जो पद से हटाए गए राष्ट्रपति के शासन के खिलाफ भड़के थे। हंगरी, बुलगारिया, रुमानिया, सेर्बिया और पोलैण्ड में भी इसी तरह की मजदूरों की रैलियां निकाली गईं। मध्य और दक्षिण अमरीका में करों में बढ़ोत्तरी, मजदूर संघों पर सरकार की नीतियों का और बेरोजगारी का विरोध करते हुए मई दिवस के प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए। मेक्सिको नगर में करों की बढ़ोत्तरी के खिलाफ दसियों हजार प्रदर्शनकारियों ने आवाज उठाई। अर्जेंटिना में नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आर्थिक उपायों की मांग की।

एशियाई देशों में और अफ्रीकी देश जिंबाब्वे में भी जुझारू विरोध-प्रदर्शन किए गए।

जापान में देश भर में मजदूर संघों द्वारा आयोजित रैलियों में कोई 13 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। ज्यादातर रैलियां बेरोजगारी को बढ़ाने वाली सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में निकाली गईं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सिओल में करीब 20,000 मजदूरों ने 15,000 दंगा पुलिस बलों का मुकाबला करते हुए सरकार की पहल पर शुरू किए गए आर्थिक पुनर्निमाण के खिलाफ तथा देवू मोटार के मजदूरों और यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने ताइप शहर में जुलूस निकाला। ➲

कार्यकर्ताओं द्वारा अमरीकाओं की शिखर बैठक की घेराबंदी

दसियों हजारों प्रदर्शनकारियो ने क्यूबेक नगर में आयोजित अमरीकाओं की शिखर-बैठक को घेरकर उसमें बाधा डालने की कोशिश की। इस बैठक में उत्तर और दक्षिण अमेरीकी देशों के 34 नेताओं ने भाग लिया ताकि एफटीएए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाए, जिसके तहत 2005 के आखिर तक एक मुक्त व्यापार क्षेत्र पैदा होगा।

20 अप्रैल को जब शिखर-बैठक का उद्घाटन किया जा रहा था, प्रदर्शनकारियों ने तीन मीटर ऊंचे कांक्रीट से बने बाड़े को लांघकर अंदर प्रवेश किया जिससे उद्घाटन समारोहों को कई घण्टों तक रोकना पड़ा। अमरीकाओं के अलग-अलग देशों से आए भूमण्डलीकरण-विरोधी प्रदर्शनकारियो ने दंगा विरोधी पुलिस की परवाह नहीं की जो बख्तरबंद गाड़ियों से प्रयोग किए जा रहे पानी के तोपों के अतिरिक्त रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के गोले बार-बार दाग रही थी। अमरीकी साम्राज्यवाद के सरगना बुश के अलावा कई देशों के शासकों के बचाव में निर्मित बाड़े की परिधि के कई स्थानों पर इकट्ठे हुए प्रदर्शनकारियों ने घेराबंदी जैसा माहौल तैयार किया। आंखों में दर्द पैदा करने वाला आंसू गैस शिखर- बैठक वाली इमारत में भी पहुंचा, मानो वहां इकट्ठे राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को यह याद दिला रहा हो कि जनता के खिलाफ रची उनकी साजिश का बाहर मौजूद दसियों हजारों योद्धा विरोध कर रहे हैं।

1999 में सिएटल में हुए विरोध-प्रदर्शन के मुकाबले में क्यूबेक का विरोध-प्रदर्शन काफी बड़ा था। काले कपड़े और मुखौटा पहने लड़ाकुओं ने हेल्मेट पहने और ढाल पकड़े पुलिस वालों का मुकाबला किया। उन्होंने कागजों से आग के गोले बनाकर बाड़े के भीतर फेंके। शिखर बैठक के दौरान आखिर तक लड़ाइयां चलती रहीं। नेताओं के ठहरने के स्थानों से महज 800 मीटर की दूर पर ये लड़ाइयां चलीं। ❑

साम्राज्यवाद-विरोधिता से साम्यवाद तक

उत्पीड़ित जन समुदायों को यह समझने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि सिर्फ साम्यवाद ही पूंजीवाद का विकल्प है। संशोधनवादियों ने जनता में साम्यवाद के प्रति अविश्वास और भय पैदा किया है। रूस, चीन, वियत्नाम, पूर्वी यूरोप आदि में संशोधनवादियों का कब्जा और कम्युनिज़म के नाम पर उनका पतित आस्तित्व; संशोधनवादियों के नेतृत्व वाले ट्रेड युनियनों के भ्रष्ट आचरण और नौकरशाही; संशोधनवादियों के तानाशाहीपूर्ण और एकाधिपत्यवादी तरीके जहां वे सत्तारुढ़ हैं- इन सभी ने साम्यवाद की बदनामी की। जनता अभी यह नहीं समझ पाई कि संशोधनवादी कम्युनिस्ट नहीं हैं, बल्कि मजदूर आन्दोलन के भीतर मौजूद पूंजीपति ही हैं, जैसा कि लेनिन ने बताया है। जब पूंजीपति यह पाते हैं कि वे बाहर से अपने बर्बर हमलों से कम्युनिज़म का नाश नहीं कर सकते, तब वे मजदूर आन्दोलन में अपने दलालों को छोड़ देते हैं ताकि कम्युनिज़म का पहनावा ओढ़कर संशोधनवाद पर अमल किया जा सके। आज तक, मई दिवस की अधिकांश रैलियों का आयोजन इन गद्दारों ने ही किया जो मजदूर वर्ग को लगातार धोखा देते आ रहे हैं।

लेकिन संशोधनवादियों की जंजीरों को तोड़ने के बाद ही यह बढ़ता जुझारूपन उभरकर सामने आएगा। पर्यावरणवादी, अराजकतावादी और अन्य निम्न-पूंजीपति क्रांतिकारी जो हजारो की संख्या में भाग लेते हैं, साम्राज्यवादी व्यवस्था से नफरत भर करते हैं। लेकिन चूंकि उनके पास कोई ठोस विकल्प नहीं है, इसलिए उनमें से सच्चे लोगों को कम्युनिज़म की ओर मुड़ने पर बाध्य होना पड़ेगा। यह तभी आसान हो जाएगा जब सच्चे कम्युनिस्टों (यानी माओवादियों) और विभिन्न किस्म के संशोधनवादियों के बीच स्पष्ट विभाजन-रेखा खींची जाएगी। जनता खुद ही सच्चे कम्युनिस्टों और नकली कम्युनिस्टों के बीच के फर्क को पहचान लेगी। ❑

(आन्ध्र के फासीवादी चन्द्रबाबू .... पृष्ठ 5 का शेष)

उसके इशारों पर चलते हुए आन्ध्रप्रदेश को साम्राज्यवादी लूट के लिए खुला छोड़ दिया। आन्ध्र की जनता, कई जन संगठन और हमारी पार्टी चन्द्रबाबू की नीतियों का कदम-कदम पर विरोध कर रहे हैं। इसलिए साम्राज्यवादियों की शह पर चन्द्रबाबू क्रांतिकारी आन्दोलन पर पाशविक पुलिस बलों का प्रयोग करते हुए आतंक मचा रहा है। साथ ही, उसने क्रांतिकारी आन्दोलन का समर्थन करने वाले नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य बुद्धिजीवियों की हत्याओं का सिलसिला भी शुरू किया। इन घिनौनी कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए उसने कुछ काले गिरोहों का गठन किया जिनमें मुख्य रूप से समर्पित नक्सली शामिल हैं। उन्हें बाकायदा ट्रेइनिंग देकर आधुनिक हथियारों से लैस करके हमले करवा रहा है। ये गुण्डे 'ग्रीन टाइगर्स', 'क्रांति सेना' जैसे नामों से आन्ध्रप्रदेश में आतंक मचा रहे हैं। पार्टी में, दस्तों में शामिल साथियों के रिश्तेदारों पर हमला करना, पार्टी से हमदर्दी रखने वाले बुद्धिजीवियों पर हमला करना इनका मुख्य काम है। तीन साल पहले इन्होंने कॉमरेड बेल्लि ललिता नामक क्रांतिकारी सांस्कृतिक कर्मी की भी बेरहमी से हत्या करके उनकी लाश को टुकड़े-टुकड़े करके अलग-अलग कुओं में फेंका था। 1997 में क्रांतिकारी गायक कॉमरेड गद्दर पर भी चन्द्रबाबू ने कातिलाना हमला करवाया। लेकिन वे बाल-बाल बच गए। अब थोड़े ही अन्तराल से दो-दो नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या करके वह अपने फासीवादी शासन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हमेशा के लिए चुप कराना चाह रहा है। लेकिन आन्ध्र की क्रांतिकारी जनता और जनयुद्ध इसका बदला जरूर लेगा - इन हत्याओं के लिए चन्द्रबाबू को जनता की अदालत में कीमत चुकानी पड़ेगी। इतिहास में अब तक सभी तानाशाहों के साथ यही हुआ। चन्द्रबाबू भी इसका अपवाद नहीं होगा। ❑

(पीजीए के हमले तेज .... पृष्ठ 21 का शेष)

आंध्रप्रदेश के गुन्टूर जिले में

पीजीए ने 10 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा

20 अगस्त 2001 को आंध्र के गुन्टूर जिले के रामिडिचेरला के नजदीक में पीजीए ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ हमला किया। पंचायत चुनावों के मौके पर गश्त पर निकली पुलिस वालों की एक जीप पर पीजीए ने सटीक निशान लगाया। ये लोग हमारी पार्टी द्वारा दिए गए चुनाव बहिष्कार के आह्वान को विफल बनाने के लिए, लोगों को डरा-धमकाकर वोट डलवाने के लिए अंधाधुंध घूम रहे थे। ऊपर से मीडिया तो यह प्रचार हमेशा की तरह करते ही रहे कि 'इस बार जनता में नक्सलवादियों के चुनाव बहिष्कार का कोई खास असर नहीं है।' एक पुलिया के नीचे पहले से बिछाई गई बारुदी सुरंग में विस्फोट करके छापामारों ने जीप की धज्जियां उड़ा दीं। सभी दस पुलिस वाले जिनमें एक थानेदार भी शामिल था, मौके पर ही मारे गए और दो अन्य बुरी तरह घायल हो गए। गुन्टूर जिला तटवर्ती आंध्रप्रदेश के जिलों में से एक है जहां जनयुद्ध मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों इस जिले की उत्पीड़ित जनता को जबर्दस्त सदमा तब पहुंचा, जब इस जिले के जन नायक कॉ. दिवाकर (जो नलगोण्डा जिले के पार्टी सचिव थे) की एक मुठभेड़ मे शहादत हुई थी। स्थानीय जनता ने इस हमले को कॉमरेड दिवाकर की हत्या के खिलाफ पुलिस बलों से लिया गया बदला माना। जनता ने इस हमले को कोई 10 साल पहले इसी जिले के चंद्रवंका में पुलिस वालों द्वारा मारे गए 10 से ज्यादा क्रांतिकारियों को दी गई एक श्रद्धांजली के रूप में भी देखा। इस हमले के बाद जहां आंध्र की तमाम उत्पीड़ित जनता, खासकर गुन्टूर जिले की क्रांतिकारी जनता ने पीजीए को बधाई दी, वहीं चंद्रबाबू सहित शासक वर्गों के तमाम कसाई नेताओं और अफसरों ने मातम मनाया। ❑

सिएटल से लेकर नाइस तक....
साम्राज्यवादियों को घेरता जनाक्रोश

सिएटल सम्मेलन के बाद से, सड़कों पर जन समुदायों के साथ तीखे संघर्षों के बिना साम्राज्यवादी डाकुओं की एक भी बैठक नहीं हो सकी। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक या चाहे किसी और साम्राज्यवादी गिरोह की बैठकें भी हों, उन्हें जनाक्रोश का सामना करना ही पड़ा। सशस्त्र पुलिस द्वारा की गई किलेबंदी के बीच ही उनकी बैठकें चल सकीं। सिएटल के बाद वाशिंगटन, दाओस, केनबेर्रा, थाईलैण्ड, प्रेग में इसकी पुनरावृत्ति हुई।

फ्रान्स के नाइस शहर में 7 से 11 दिसंबर तक यूरोपियन यूनियन के इतिहास में सबसे लंबी शिखर-बैठक आयोजित की गई। यूरोपियन यूनियन के विस्तार पर चर्चा करने के लिए आयोजित इस बैठक के भीतर प्रतिनिधियों के बीच तीखे झगड़े हुए तो बाहर सड़कों पर आमने-सामने की लड़ाइयां हुईं।

हालांकि 4 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन किसी एक पर भी कोई सहमति नहीं बन सकी। एक-एक सदस्य के मताधिकार समेत अन्य अधिकारों को लेकर तथा विस्तारित यूरोपियन यूनियन में संभाले जा सकने वाले प्रभाव को लेकर ही वे झगड़ते रहे। तुर्की, साइप्रस, माल्टा समेत पूर्वी यूरोप और बाल्कन देशों से प्रस्तावित 13 अतिरिक्त सदस्यों के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापार गुट बनने जा रहा है। जबकि दो सबसे शक्तिशाली सदस्य जर्मनी और फ्रान्स अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए लड़े, तो ब्रिटेन ने अमरीका के साथ अपने "विशेष सम्बन्ध" को जारी रखना चाहा। अन्तिम समझौते में अपने विशाल आकार की बदौलत जर्मनी यूपोरियन यूनियन पर प्रभुत्व जमाने के लिए बड़ी रियायतें हथियाने में सफल हो गया। इस बैठक ने 'बड़े चार' (जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटेन, इटली) देशों के अधिकारों में और वृद्धि की तथा उसी समय छोटे देशों को किनारे पर धकेल दिया। इससे बेल्जियम, पुर्तुगाल, लक्सेम्बर्ग, ऑस्ट्रिया और ऐसे अन्य देश नाराज हो गए। प्रत्येक देश को आवंटित मतों को 'बड़े चार' देशों के लाभ में दोबारा भारित किया गया।

बैठक के चारों दिनों के दौरान नाइस की पूरी तरह नाकेबंदी की गई। सड़कों पर 6,000 पुलिस वालों ने गश्त लगाई और हेलिकॉप्टरों ने आसमान में उड़ते हुए पहरा दिया। इमारतों की छतों पर निशानेबाजों ने मोर्चे सम्भाले।

फ्रान्स, स्पेइन, जर्मनी, डच, इटली, पुर्तुगाल - समूचे यूरोप से 1 लाख प्रदर्शनकारी नाइस पहुंचे थे। हथियारबंद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसात्मक झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम फेंके, दुकानों की खिड़कियां तोड़ दीं, कारों को उलट दिया और एक बैंक में आग लगा दी। 20 पुलिस वाले घायल हुए जिनमें से एक गंभीर था। 100 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया।

इस बैठक के भीतर नेताओं को दिए गए भव्य प्रीतिभोज को लेकर भी साम्राज्यवादी सरगना लड़ते-झगड़ते रहे, और बाहर लड़ाई चलती रही।

प्रदर्शनकारियों में कई किस्म के असंतुष्टों तथा भूमण्डलीकरण के दौर में जनता पर हो रहे भारी हमलों से नाखुश लोगों का समावेश था। उनमें शांतिवादियों, पर्यावरणवादियों से लेकर अराजकतावादी और समाजवादी भी शामिल थे। उनमें से अधिकतर लोगों के पास मौजूदा व्यवस्था का कोई विकल्प न था, सिवाए हवाई कल्पनाओं के। ठोस विकल्पों के अभाव में तथा रोजमर्रा के संघर्षों को स्पष्ट दिशा न देने से ऐसे संघर्ष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। समाजवादी व्यवस्था ही इसका सही विकल्प हो सकती है जिसे क्रांति के जरिए मौजूदा व्यवस्था को ध्वस्त करके ही हासिल किया जा सकता है।

नाइस में यूरोपियन यूनियन के खिलाफ प्रदर्शन

विश्व भर में समाजवादी ताकतों का अस्थाई पीछे कदम तथा संशोधनवाद के कारण कम्युनिस्टों पर अविश्वास का फायदा उठाकर गैर सरकारी संगठन इस असंतोष को स्वीकार योग्य रास्तों में मोड़ देना चाहते हैं। वे साम्राज्यवादियों के लिए अनुकूल सुरक्षा वाल्वों की तरह काम करते हैं ताकि व्यवस्था के प्रति जनता के क्रोध और आक्रोश को ठण्डा किया जा सके। उनमें से कई तो साम्राज्यवाद की बुराइयों से ज्यादा जोर का हमला समाजवाद/साम्यवाद के खिलाफ करते हैं। बहरहाल, ऐसे प्रदर्शन अपनी 'शांतिपूर्ण' सीमाओं से गुजर चुके हैं। ज्यों-ज्यों दुनिया भर में क्रांतिकारी और माओवादी ताकतों का प्रभाव बढ़ेगा, साम्राज्यवाद की गंदगी के खिलाफ लड़ने वाले सच्चे योद्धा क्रांतिकारी विकल्प को चुन लेंगे। इसी बात से ये साम्राज्यवादी सरगना ज्यादा आतंकित हैं। ❑

नेपाल के माओवादियों का फौजी अभियान कामयाब!

नेपाल में हाल ही में संपन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन द्वारा स्वीकृत महान छलांग की पहली योजना के तहत जन छापामारों ने अप्रैल 2001 के पहले सप्ताह में कुछ साहसिक हमले किए जिससे सारा नेपाल हिल उठा। सप्ताह भर चले इस अभियान के तहत देश भर में हालांकि हजारों छोटी-बड़ी तोड़-फोड़ की कार्रवाइयां हुई, लेकिन तीन क्षेत्रीय कमानों के नेतृत्व में पुलिस थानों और चौकियों पर किए पांच हमले इनमें प्रमुख थे। 6 अप्रैल को जन-आंदोलन दिवस के मौके पर बुलाए गए नेपाल बंद के साथ ही इस अभियान का सफलतापूर्वक समापन हुआ।

जनयुद्ध का गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी क्षेत्र में दो जबरदस्त हमले किए गए जिन्हें अब तक के सबसे बड़े हमले कहा जा सकता है। पहला हमला 1 अप्रैल को रुकमकोट में हुआ जो फौजी दृष्टिकोण से अब तक का बड़ा हमला था। पहाड़ की चोटी पर स्थित कंपनी स्तर के, सामरिक दृष्टिकोण से इस मजबूत अड्डे को चारों तरफ से घेरता हुआ एक बाहरी फेन्सिंग था। और उसके भीतर पत्थरों से बनी एक मोटी दीवार थी जिसके अन्दर 8 अब्जर्वेशन पोस्टें थीं। और एक ट्रेंच (खंदक) भी खोदी हुई थी। इस कैंप में 76 पुलिस वाले रहते थे। इसके बावजूद छापामारों ने कंपनी स्तर के फॉर्मेशन में जाकर बिजली सी तेजी से हमला किया। 45 मिनटों के अंदर दुश्मन के कैंप को तहस-नहस किया गया। 32 पुलिस कमाण्डो मारे गए जिनमें एक इन्सपेक्टर भी शामिल था, जबकि 14 घायल हुए और 22 को जन हिरासत में लिया गया। इस हमले से 58 रायफलें, 6 मैग्नम, 9 शॉटगन, 3 पिस्तौलें, 3 रिवाल्वर और करीब 6,000 गोलियों के अलावा कुछ संचार उपकरणों को भी छापामारों ने बरामद किया। यह जबर्दस्त कामयाबी जनता के 8 प्यारे योद्धाओं, जिनमें प्लाटून के डिप्यूटी कमांडर कॉ. राजेन्द्र भी थे, की शानदार शहादत की कीमत पर मिली।

दूसरा छापामार हमला पश्चिमी क्षेत्र के दाइलेख जिले की नौमुले इलाका पुलिस चौकी पर हुआ जिसमें 72 पुलिस वाले रह रहे थे। यह भी पहाड़ की चोटी पर स्थित थी। 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात को किए गए इस हमले में कई प्लाटूनों ने भाग लिया, जबकि स्थानीय मिलिशिया ने भी सहयोग दिया। सुरक्षा के भारी बंदोबस्त को तोड़कर छापामारों ने इस चौकी को 70 मिनटों में अपने कब्जे में लिया। यहां भी एक इंस्पेक्टर सहीत 32 पुलिस वाले मारे गए और दर्जनों घायल हुए। 58 रायफलों और 41 हजार गोलियों समेत भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र छापामारों के कब्जे में आ गए। छापामारों के छह योद्धाओं ने भी इस हमले को कामयाबी दिलाने हेतु अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर किया। इस फौजी कार्रवाई से सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में आधार इलाकों का विस्तार करने में बड़ी मदद मिली।

मध्य क्षेत्र में अप्रैल 2 तारीख को पलपा जिले में मुझुंग और धाड़िंग जिले के डारखा में एक साथ दो सफल छापामार हमले किए गए। मुझुंग पुलिस चौकी में 22 पुलिस वाले तैनात थे और छापामारों ने उसे घेरकर आधे घण्टे के भीतर ही उस पर कब्जा कर लिया। इस हमले में 2 पुलिस वाले मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए। 8 अन्य पुलिस वाले तब मारे गए जब वे इस चौकी की सहायता करने क्षेत्रीय मुख्यालय से मुझुंग की ओर आ रहे थे। पुलिस चौकी को छापामारों ने बमों से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। छापामारों को 12 रायफलें, 2 पिस्तौलें, 2 रिवाल्वर,1 शॉटगन और भारी मात्रा में गोलाबारूद मिले। जन छापामारों को इस हमले में कोई क्षति नहीं हुई। धाड़िंग जिले के डारखा में जो कि राजधानी शहर काठमांडू से लगा हुआ है, किए गए हमले में दुश्मन के भाड़े के सैनिकों ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण किया। दोनों तरफ कोई भी हताहत नहीं हुए। छापामारों ने 9 रायफलें, 1 मैग्नम, एक शॉटगन, दो पिस्तौलें, दो रिवाल्वर और भारी मात्रा में गोला बारूद छीन लिए और चौकी को ध्वस्त कर दिया। बाद में सरकार ने सभी पुलिस कर्मियों को इस आरोप में गिरफ्तार किया कि उन्होने क्रांतिकारियों से हाथ मिलाया।

पूर्वी क्षेत्र में डोलखा जिले की माइनापोखरी पुलिस चौकी पर छापामारों ने 1 अप्रैल को धावा बोला। चूंकि कुछ अंतिम रुकावटों के चलते हमला भोर के समय तक टाल दिया गया था, इसलिए इसमें आंशिक सफलता ही मिल पाई। इस चौकी में 46 पुलिस वाले रहते थे। जिनमें से 7 को मार डाला गया और 20 को घायल कर दिया गया। छापामारों ने 8 रायफले, एक मैग्नम और कुछ गोलाबारूद जब्त किया। इस हमले में तीन जन छापामार योद्धाओं की शहादत हुई और छह अन्य घायल हो गए।

काठमांडू घाटी में भूतपूर्व पुलिस प्रमुख अच्युत कृष्ण खरेल और सत्तारूढ़ पार्टी के एक पूर्व सांसद लेखनाथ न्यूपाने के आवासों पर किए गए बम हमलों ने शासक वर्गों के कसाइयों और गद्दारों के रीढ़ में कंपकंपी भर दी। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में कई छिटफुट कार्रवाइयां भी हुईं जिन में घात हमले आदि शामिल हैं।

महान छलांग की पहली योजना के तहत की गई छापामार कार्रवाइयों से शासक वर्गों का संकट और भी गहरा हो गया। पुलिस बलों का मनोबल बुरी तरह गिर गया। इनसे विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र में क्रांतिकारी आधार इलाकों का विस्तार करने और उन्हें मजबूत बनाने में सहायता मिली। इस क्षेत्र में तैनात कई सामरिक महत्व वाले पुलिस थानों को हटा लिया गया।

अपने पड़ोसी देश नेपाल में जनयुद्ध द्वारा हासिल इन उपलब्धियों से भारत के क्रान्तिकारियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। दूसरी ओर भारत के विस्तारवादी शासक इन उपलब्धियों से काफी हैरान होंगे। माओवादियों की ये कामयाबियां उनकी नींदें उड़ा रही हैं। हम इन सफलताओं के लिए नेपाल के बहादुर छापामारों और उत्पीड़ित जनता को क्रांतिकारी बधाई देते हैं और साथ ही, इन कार्यवाहियों के दौरान शहीद हुए जांबाज़ योद्धाओं को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ❑

पुलिस जवानों! लुटेरे शासक वर्गों के हित में 'बलिदान' मत करें !

अपने वर्ग की जनता के पक्ष में खड़े होकर क्रांतिकारी आंदोलन की मदद करें!!

पुलिस जवानों! आज दण्डकारण्य (छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, और उड़ीसा का वनांचल) में युद्ध का माहौल बना हुआ है। इसमें एक ओर हमारी पार्टी के कॉमरेड मारे जा रहे हैं तो दूसरी ओर आपकी जानें जा रही हैं। जब हमारा कोई कार्यकर्ता (संगठन सदस्य से ले कर पार्टी नेता तक) मारा जाता है तो जनता उसे 'अपना' समझते हुए सैकड़ों-हजारों की संख्या में इकठ्ठे होकर अंतिम यात्रा में भाग ले रही है। लेकिन आप मारे जाते हैं तो आपके बीवी-बच्चों के आंसू और सरकार व अधिकारियों के घड़ियाली आंसू को छोड़ दें तो जनता इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि मौत सभी के लिए बराबर है, लेकिन सबकी मौत बराबर नही है। आपकी मौतों से यह कहावत सच साबित हो रही है कि "जनता के लिए जान देना हिमालय से भी भारी है जबकि लुटेरों के लिए जान देना पंख से भी हल्का है।" शासक सरकारें और शासक वर्गों के प्रसार माध्यम (अखबार, रेडियो,टीवी आदि) यह बात छुपाते हुए कि आपकी इस बदहाली की क्या वजह है, पुलिस और नक्सलवादियों के बीच जारी लड़ाई के रूप में इस आंदोलन का चित्रण करते हुए आपको हमारे खिलाफ और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिए हम यह वक्तव्य दे रहे हैं ताकि आपको यह सोचने पर मजबूर किया जा सके कि वर्तमान लड़ाई का क्या मकसद है। और क्यों आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहे हैं।

यह पुलिस और नक्सलवादियों के बीच की लड़ाई नहीं!

पुलिस जवानों! आप गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से ही इस नौकरी में आए हैं। अधिकांश गरीब परिवारों से ही आए हैं। आपके माता-पिता दिन-रात मेहनत करने के बावजूद सिर्फ इसलिए गरीबी में डूबे हुए हैं क्योंकि श्रम का उचित फल नहीं मिलता है और जोतने वालों को जमीन नहीं मिल रही है। जनता का शोषण ही इसकी जड़ है। लुटेरे शासक वर्ग ही इसके जिम्मेदार हैं। श्रम का उचित फल और जोतने वालों को जमीन मिलना है तो गरीबो के राज्य के बिना कोई चारा नहीं है। इसलिए, हमारी पार्टी देश की उत्पीड़ित जनता को गोलबंद करके लुटेरे शासक वर्गों के खिलाफ लड़ रही है। हमारी पार्टी के नेतृत्व में गोलबंद हो रही जनता लड़कर कई अधिकार हासिल कर रही है। ग्रामीण अंचलों में सामंती शोषण और उत्पीड़न को दफना रही है। चूंकि सामंती वर्ग और लुटेरे शासक भिन्न नहीं हैं, इसलिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर आपको जनता के खिलाफ उकसाया जा रहा है। जनता का दमन करवाया जा रहा है। शासक वर्ग जनता के जायज अधिकारों के लिए संघर्ष को 'अपराध' मान रहे हैं। जनता को संघर्ष इसलिए अनिवार्य हो रहा है क्योंकि सरकारें जनता की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के बजाए उन्हें उलझाए रख रही हैं। भूख लगने पर शिशु का रोना जितना सहज है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनता का संघर्ष करना भी उतना ही सहज है। इसलिए उत्पीड़ित वर्ग हमारी पार्टी की अगुवाई में गोलबंद होकर शासक वर्गों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। यह लड़ाई जनता और लुटेरे शासक वर्गों के बीच हो रही है। सचाई यही है। लेकिन शासक वर्ग कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर आपको थोड़ा वेतन देकर आपको बतौर अपने 'सशस्त्र बल' इस्तेमाल करते हुए जनता के खिलाफ उकसा रहे हैं ताकि अपने धन दौलत को और लुटेरे शासन को बचाया जा सके। दूसरी ओर वे आपको और जनता को गुमराह करने के लिए यह 'गोबेल्स' प्रचार कर रहे हैं कि यह पुलिस और नक्सलवादियों के बीच की लड़ाई है। आपकी मौतों को जनता के लिए किए जा रहे 'बलिदानों' के रूप में चित्रित करते हुए आपको बलि के बकरे बना रहे हैं।

शासक वर्ग, जो क्रांतिकारियों के ही नहीं, पुलिस वालों के सिरों पर भी इनाम लगाते

हमें आपको यह याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी कि आप निचले स्तर के पुलिस जवानों के रूप में काम करते हुए अपने अधिकारियों के द्वारा अपमानित किए जाते हुए किस तरह की बदहाली मे जी रहे हैं। ऐसे उत्पीड़नों के खिलाफ आंध्र में, बिहार में, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में कई अन्य प्रदेशों में जब भी आपने संघर्ष किया तो उस संघर्ष को आपके अधिकारियों और शासकों ने कितनी क्रूरता से कुचल डाला, यह बात आप ही अच्छी तरह से जानते हैं। आज वही शासक वर्ग आपको कुछ रियायतें देकर, सुविधाएं बढ़ाकर यह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वे आपकी खूब भलाई कर रहे हैं। आप मर जाते हैं तो आपके परिवार को पैसा दे रहे हैं जो पहले नहीं दिया जाता था। सरकारें ये सब आपको उदारता से नहीं दे रही हैं। वे ऐसे तरीके अपना रहे हैं ताकि आपको कुछ हद तक संतुष्ट करके जनता के खिलाफ और भी भड़काया जा सके। जनता का नेतृत्व कर रहे क्रांतिकारियों की हत्या करके अपने वजूद को बनाए रखने के इरादे से जिस तरह क्रांतिकारियों के सिर पर इनाम घोषित कर रहे हैं, उसी तरह हमारे प्रतिरोधी हमलों में आप मारे जाएंगे तो पैसा देने की बात कहकर

आपके सिर पर भी इनाम रखा है। वे खुद तो 'जेड' या 'जेड पल्स' किस्म की सुरक्षा के घेरे में रहकर बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने वाले जैमरों का बंदोबस्त करके, बुलेटप्रूफ गाड़ियों में घूमते हुए, जमीन पर खतरा महसूस करने से हेलिकॉप्टरों में उड़कर जा रहे हैं, और अपने लुटेरे शासन को जारी रखने के लिए आपकी जानों को दांव पर लगा रहे हैं। उसे जनता के लिए किए जाने वाला 'बलिदान' का नाम दे रहे हैं।

इस मौके पर आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए। जबसे समाज में वर्गों का उदय हुआ, राजसत्ता को अपनी मुट्ठी में रखे हुए शासक वर्गों ने अपने लुटेरे शासन को बनाए रखने के लिए और जनता के विरोध को दबाने के लिए ही राज्य-यंत्र का गठन किया। इसी के अंतर्गत ब्रितानी साम्राज्यवादियों ने भारत में आपकी वर्तमान पुलिस व्यवस्था की नींव रखी ताकि हमारे देश को लूटा जा सके। और उनकी लुटखसोट का विरोध करने वाली जनता और जनान्दोलन का दमन किया जा सके। जलियांवालाबाग का नरसंहार, क्रांतिकारी अल्लूरि सीताराम राजू की 'मुठभेड़' भगतसिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा–ये सब कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की आड़ में ही हुए थे। अंग्रेजों के साथ सांठगांठ करके सत्तारूढ़ हुए देसी शासक वर्ग अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता को कुचलने के लिए तैयार की गई पुलिस व्यवस्था पर बिना कोई फेरबदल किए ही अमल करते हुए, आज उसे और क्रूरतापूर्ण बना रहे हैं। सोचने पर आपको भी यह बात समझ में आएगी कि जनता को कुचलने के लिए शोषक वर्ग आपका किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यह समझकर ही जनता आपको अंग्रेजी जमाने में ही नहीं बल्की आज भी 'अपने' नहीं मान रही है। इसके अलावा, सरकार उन लोगों को ज्यादा इनाम-इकराम और पदोन्नतियां दे रही है जो क्रांतिकारी आन्दोलन के खिलाफ क्रूरता से पेश आते हैं। विशेषकर आपमें से कुछ लंपट संस्कृति से प्रभावितों को जानबूझकर प्रोत्साहित करते हुए हत्यारे गिरोह बना रही है। इससे तमाम पुलिस वालों के खिलाफ जनाक्रोश भड़क रहा है। इसे आंध्र में साफ तौर पर देखा जा सकता है।

सभी सरकारें विश्व बैंक की उंगलियों पर नाचते हुए, साम्राज्यावादी यहां के प्राकृतिक संसाधनों और जनता के श्रम शक्ति को सस्ते में लुट सकें, इसके लिए अनुकूल सुधारों पर अमल करते हुए मजदूरों को बेघरबार कर रही हैं। दैनिक वेतनभोगियों की छंटनी, बिजली बोर्ड का निजीकरण, कारखानों का मशीनीकरण जैसे कदमों से नौकरियों की संख्या घटाकर, रिक्त पदों की भर्ती पर रोक लगाकर बेरोजगारों की सेना बढ़ा रही हैं – छात्र-नौजवानों की चैन उड़ा रही हैं। फसलों के मार खाने, उगी फसलों के न बिक जाने, बिकने पर भी वाजिब दाम न मिलने के कारण किसान कर्जों के बोझ से दबकर आत्महत्या की शरण ले रहे हैं। सरकारें उनकी मदद करने के बजाए नई कृषि नीति के नाम से गरीब किसानों के खेतों को बहुराष्ट्रीय निगमों के हवाले कर देने की साजिश रच रही हैं। दूसरी तरफ बाजार में हर चीज की कीमतों को अंधाधुंध बढ़ा रही हैं। नई आर्थिक नीतियों के तहत दूसरी पीढ़ी के सुधारों पर अमल करते हुए जनता की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। सभी सरकारें गरीबों को मिल रही सब्सिडियों को धीरे-धीरे समाप्त करके साम्राज्यवादियों और दलाल पूंजीपतियों को करों मे कई रियायतें दे रही हैं। ये हमारी मातृभूमि को साम्राज्यवादियों के पास गिरवी रखकर देशभक्ति का राग अलाप रही हैं। केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा सबसे बड़ी देशद्रोही है। जिसने 'स्वदेशी' नाकाब पहनकर भारत को साम्राज्यवादियों की लूट का मैदान बनाया। उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण की नीतियों तथा विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के कारण सभी तबकों की जनता को संघर्ष अनिवार्य हो गया। देश भर में अलग-अलग तबकों के लोगों द्वारा किए जा रहे संघर्षों से यही निष्कर्ष निकल रहा है।

जनता को लूटते हुए देश को गुलामी की ओर ले जाने वाली इस स्थिति से देश को मुक्त करने के लिए ही हमारी पार्टी के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है। हमारी पार्टी पर और हमारे जन संगठनों पर कुछ राज्यों की सरकारों ने प्रतिबंध लगाया और कुछ ने प्रतिबंध लगाने की तैयारियां शुरू कीं क्योंकि उन्हें डर है कि सभी तबकों की जनता हमारी पार्टी के नेतृत्व में गोलबंद हो जाएगी। वे यह सोचकर कि जनता का नेतृत्व कर रही पार्टी पर प्रहार करके अपने अस्तित्व को बचा लेंगे, हमारे आंदोलन पर अमानवीय दमनचक्र चला रही है। साम्राज्यवादियों की शह पर साझा कमान को गठित कर हत्याएं कर रही हैं। इसके लिए शासक वर्ग पीपुल्सवार पार्टी के बारे में समाज विरोधी देशद्रोही और आतंकवादी कहकर प्रचार करते हुए आपके नसों में यह जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने औजारों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सोचिए कौन हैं देशद्रोही और समाज विरोधी, जनता को लूटते हुए देश को कौड़ियों में बेचने वाले? या फिर हम जो उनका विरोध कर रहे हैं? मुलतई गोलीकांड, लखोली के किसानों पर हिंसा, गोवारी आदिवासियों का नरसंहार, केशोरी में आदिवासियों पर गोलीबारी–यह हिंसा किन समाज-विरोधियों को कुचलने के लिए, किन देशद्रोहियों का सफाया करने के लिए की गई, आप एक बार सोचिए। चूंकि आप जनता के दुश्मन शासक वर्गों की तरफ से उनका सशस्त्रबल बनकर जनांदोलनों को कुचलने के लिए बंदूकों से आ रहे हैं, इसलिए हमें इसका प्रतिरोध करने के लिए आप पर हमले करने पर बाध्य होना पड़ रहा है। वेतन के लिए जनता के दुश्मनों की तरफ से जनता का दमन करने की कोशिश करने पर आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है।

नेता-मंत्री-अफसरों के हित और आपके हित एक नहीं!

जनता को लुटना ही शासक वर्गों का मतलब है। दिग्गिविजय सिंह, अजित जोगी, महेन्द्रकर्मा, ***(शेष पृष्ठ 39 पर ....)***

गड़चिरोली डीवीजन में तेन्दुपत्ता संघर्ष सफल!

हर साल की तरह इस साल भी गड़चिरोली डीवीजन के आदिवासी मजदूरों ने तेन्दुपत्ता मजदूरी दरों में बढ़ोत्तरी की मांग करते हुए ठेकेदारों के खिलाफ संघर्ष करके अपनी मांगें हासिल कीं। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस वालों ने इस संघर्ष को तोड़ने के लिए व्यापक दमन अभियान चलाया। इसके बावजूद यहां की संघर्षशील जनता ने पुलिस दमन को धता बताते हुए संघर्ष को कामयाबी दिलाई। गांव-गांव में संघर्ष समिति का गठन किया गया। इन्हीं संघर्ष समितियों ने लोगों का नेतृत्व किया। इस साल जनता ने 1.45 रु. प्रति सैकड़ा मजदूरी की मुख्य मांग से संघर्ष छेड़ा। आखिर ठेकेदारों के साथ हुई चर्चाओं के बाद 1.43 रु. प्रति सैकड़ा मजदूरी पर सहमति हुई। इसके अलावा जनता द्वारा हासिल मांगें इस प्रकार हैं :

1.	तुड़ाई (प्रति सैकड़ा)	143.00
2.	उलटाई (प्रति 1000 पुड़ा)	12.00
3.	पलटाई (प्रति 1000 पुड़ा)	12.00
4.	डिगली	12.00
5.	पानी (कावड़)	9.00
6.	बोरा भराई	45.00
7.	बोरा ढुलवाई (प्रत्येक किलोमीटर)	15.00
8.	दीवानजी का वेतन (बड़ा फड़)	3,000.00
9.	दीवानजी (छोटा फड़)	2,900.00
10.	वाचर (बड़ा फड़)	2,900.00
11.	वाचर (छोटा फड़)	2,800.00
12.	मृत्यु होने पर मुआवजा	95,000.00

इन मांगों को हासिल करने के अलावा जनता ने कुछ गांवों में अपने ग्राम विकास के लिए ठेकादारों से जुर्माना वसूला जिससे गांव में तालाब आदि का निर्माण किया जा सके।

बांस कटाई मजदूरों का सफल संघर्ष

गड़िचिरोली डीवीजन में हर साल बल्लारशाह पेपरमिल के लिए बांस कटाई की जाती है। इस बार भी जनता ने मजदूरी में बढ़ोत्तरी की मांग करते हुए संघर्ष किया। इस संघर्ष के संचालन के लिए गांव स्तर पर और यूनिट स्तर पर संघर्ष समिति का गठन किया गया था। पुलिस ने इस संघर्ष को विफल करने के लिए, जनता की एकजुटता को तोड़ने के लिए सारे हथकण्डे अपनाए, लेकिन वे सब विफल हो गए। भामरागढ़ इलाके में जनता और पेपरमिल अधिकारियों के बीच मजदूरी दरों पर बातचीत हुई। इस बातचीत में संघर्ष समिति ने जनता का प्रतिनिधित्व किया। बाद में मिल मालिकों को जनता की एकता के सामने झुककर मजदूरी बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। जनता द्वारा हासिल मजदूरी की दरें इस प्रकार हैं -

1.	कटाई-ढुलवाई (प्रति बन्डल)	7.10 (7.00)
2.	रीबन्डलिंग	40.00
3.	लोडिंग-अनलोड़िंग	42.00
4.	सीनियर मेट	62.00
5.	जूनियर मेट	60.00
6.	मौत होने पर मुआवजा	1,00,000.00
7.	दिहाड़ी मजदूरी	60.00 - 58.00

(.... पृष्ठ 38 का शेष)

विलासराव देशमुख जैसे नेताओं ने सैकड़ों करोड़ रूपए इसी तरह कमाए। आपके बड़े अधिकारी माफिया गैगों से, डाकूओं से पैसा वसूल कर करोड़ों की कमाई करते हैं। यह आप भी जानते हैं। लेकिन आप तो पेट पालने के लिए पुलिस बने हैं। आप गरीबी में पल-बढ़ कर पुलिस बने हैं। लेकिन अजीत जोगी, महेन्द्रकर्मा, मदन गोपाल पाण्डे के औलाद या फिर आपके पिताओं कर्ज देने वाले सूदखोरो के औलाद, आप जैसे सामन्य पुलिस जवान नहीं बनते। सिर्फ आप जैसे लोग ही पुलिस जवान बनते हैं। तो आपके हित किसमें है? सिर्फ वेतन पाने के लिए शासक वर्गों की तरफ से जनता पर हमला करने में? या फिर आपके भाई-बंधुओं और आपके आसपास रहने वाले लोगों के हितों में? आपका किया एक-एक लाठी प्रहार, आपकी दागी एक-एक गोली आपके भाई-बंधुओं और आपके वर्ग के हितों पर ही कुठाराघात है। इसलिए आपको चोर नेताओं के खातिर, भ्रष्ट अधिकारियों के खातिर जान देने की जरूरत नहीं है। 'बलिदान' करने की जरूरत कतई नहीं है।

गरीब पुलिस वालों! आपकी वर्गीय पृष्ठभूमि को और आपको समझने में हमारा नजरिया काफी स्पष्ट है। भले ही आप जनता के दुश्मनों के बलों के तौर पर कार्यरत हों, आपके खिलाफ हमारे प्रतिरोधी हमलों की हम समय-समय पर समीक्षा कर रहे हैं। हम हमारे इस उसूल का हमेशा पालन करते हैं कि हमले के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले पुलिस वालों को नहीं मारा जाए तथा निहत्थे पुलिस वालों को नहीं मारा जाए, बशर्ते कि वे जनता के ऊपर हमलों में मुख्य भूमिका अदा करने वाले क्रूर पुलिस वाले न हों। इक्के-दुक्के मौकों पर जब इसका उल्लंघन हुआ तो हमने उसे गलत ठहराते हुए समीक्षा की। इसलिए आपके बारे में हमारा रवैया काफी स्पष्ट है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियो को पहचानें तथा इस सचाई पर भी गौर करें कि आपके अपर्याप्त वेतन से लेकर आपकी सभी मुश्किलें नवजनवादी क्रांति की सफलता से ही जुड़ी हुई हैं जो आपके वर्गीय हितों के लिए जारी है। आपसे हमारी अपील है कि आप क्रांतिकारी आन्दोलन के बारे में अपनी समझ बढ़ा लें तथा आपके लिए संभव तरीकों में आन्दोलन में अपना सहयोग दें।

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]

स्पेशल जोनल कमेटी, दण्डकारण्य

डीएकेएमएस का एटापल्ली रेन्ज अधिवेशन कामयाबी के साथ सम्पन्न!

पुलिस के भीषण दमन अभियानों के बीच ही डीएकेएमएस का एटापल्ली रेन्ज अधिवेशन शहीद भगतसिंह के शहादत दिवस 23 मार्च, 2001 को आयोजित किया गया। इसमें 26 प्रतिनिधियों और केएएमएस से 5 महिलाओं ने साथी-प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया। अधिवेशन के प्रारम्भ में शहीद राजू पुंगाटी ग्राउण्ड में कॉमरेड बाजू ने झण्डा फहराया। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि पुलिस दमन में हमारा संगठन कमजोर पड़ गया और गांवों में मुखियाओं ने फिर से जनता का दमन शुरू किया। उन्होंने इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि बूरगी गांव के सोमजी जैसे लोगों ने, जो एक समय डीएकेएमएस के नेता रहे, पुलिस मुखबिर बनकर जनता को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि आने वाले दिनों में पुलिसिया दमन बढ़ने के बावजूद दृढ़ता से काम करें।

ग्राउण्ड से नारेबाजी करते हुए सभी प्रतिनिधि कॉ. किशन अधिवेशन हाल पहुंच गए। बाद में प्रतिनिधियों ने अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए कॉ. दशरत पुंगाटी का चुनाव किया। इस अधिवेशन में डीएकेएमएस का घोषणा-पत्र, मौजूदा देशीय-अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति, जंगल और वन्यप्राणियों का बचाव आदि विषयों पर चर्चाएं हुईं। आखिर में रेन्ज कमेटी का चुनाव किया गया। कॉ. नड्डुगु को अध्यक्ष चुन लिया गया। बाद में रेन्ज कमेटी के चुने हुए सभी लोगों ने शपथ-ग्रहण के बाद अपनी बात रखी। सभी प्रतिनिधि अधिवेशन के फैसलों और प्रस्तावों पर अमल करने का संकल्प लेकर अपने-अपने गांव लौट गए।

मुखबिर का सफाया और उसके परिवार को ग्राम बहिष्कार!

दक्षिण बस्तर डिवीजन के जेगरगोंडा इलाके में गांव भीमारम के पटेल बंदा भीमाल (कोमटि वड्डे) को पुलिस मुखिबिरी के कारण जन अदालत में मौत की सजा दी गई। भीमाल के पिता बांदा मूकाल को 1991 में हमारे छापामार दस्ते ने मार डाला था, क्योंकि उसने दस्ते को मरवाने के लिए पुलिस को लाया था। पिता की मौत के बाद उसके दो बेटे भीमाल और पोदियाल ने पार्टी के खिलाफ पुलिस मुखबिर बनकर किसी भी तरह दस्ते का सफाया करने की ठान ली। भीमाल गांव में रहता था और उसका भाई पोदियाल किरन्दुल में रहता था। भीमाल दस्ते के आने-जाने की खबर किरन्दुल में अपने भाई को पहुंचाता था और पोदियाल पुलिस को। पिछले साल के अगस्त महीने में पोदियाल ने एक पुलिस जवान को अपने भाई के पास भेजा था जिसे भीमाल ने अपने घर पर 15 दिन तक रखा। गांव वालों को उसे अपना रिश्तेदार बताया। लेकिन उस बीज दस्ते का वह गांव जाना नहीं हुआ। बाद में इसका पर्दाफाश हो गया। इस पर स्थानीय पार्टी ने जन अदालत बुलाई जिसमें 10 गांवों से आए क हजार लोगों ने भाग लिया। जनता के फैसले के मुताबिक उसे मार डाला गया और उसके परिवार को गांव से खदेड़ दिया गया क्योंकि उसका पूरा परिवार ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था। इसके अलावा, गांव में भीमाल को सहयोग देने वाले चार अन्य लोगों को जन अदालत ने पिटाई करने का फैसला सुनाया।

माड़ डिवीजन में जमींदारों पर जबरा के हमले!

15 साल पहले जीविका की तलाश में मैदानी इलाके छोड़ माड़ के पहाड़ों में आ बसने वाले कुछ लोग आज जमींदार बन गए हैं। इन्होंने गांव में प्रवेश पाने हेतु,पहले स्थानीय जनता को रिझाने के लिए मुखियाओं को दारू-मुरगे दिए थे। बाद में दूसरे इलाकों से यहां जीने के लिए आए हुए गरीब लोगों को मजदूरी पर लगाकर जंगल की अंधाधुंध कटाई करवाकर काफी जमीन को काश्त में लाया। इन्होंने इसका विरोध करने वाले लोगों पर हमले करते हुए, गांजे की खेती से खूब पैसा कमाया। पुलिस के साथ इनके अच्छे सम्बन्धों के चलते जनता पर जुल्म करते थे।

ऐसे लोगों में नेलनार इलाके के ओयंगेर गांव का निवासी माडवी उंगा, डेंगलपुत्ति गांव का निवासी इडमो कोवासी, कोहकामेट्टा इलाके के रानीबेड़ा गांव का निवासी दुग्गा पटेल और कमकल गांव का निवासी घसिया शामिल हैं। स्थानीय छापामार दस्तों, डीएकेएमएस और केएएमएस के नेतृत्व में 10 से 15 गांवों की जनता ने अलग-अलग हमले करके उनकी सारी संपत्तियां जब्त करके बांट लिया। इन सभी हमलों में 40 गांवों के 950 लोगों ने भाग लिया।

ओयंगेर के माडवी उंगा के घर पर 10 गांवों से 300 स्त्री-पुरुषों ने हमला किया। 12 दिसम्बर 2000 को किए गए इस हमले में जनता ने निम्नलिखित संपत्तियां जब्त कीं -

धान - 100 खण्डी (एक खण्डी के 25-30 किलो), खोसरा - 100 खण्डी, मकई - 10 खण्डी, मुरगे - 45, बकरे - 22, सुअर - 3, गायें - 30 के अलावा सोना-चांदी के कई सारे जेवरात, एक घड़ी, दो सायकलें और दो भरमार बन्दूकें भी शामिल हैं।

डेंगलपुत्ति का निवासी इडमो कोवासी एक खुख्यात जालिम था। जनता ने फैसला किया कि इसकी सारी सम्पत्तियों को जब्त करके इसे गांव से भगा दिया जाए। इसके मुताबिक सैकड़ों लोगों ने इसके घर पर धावा बोला। इसके घर से जनता द्वारा जब्त की गई सम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

धान - 150 खण्डी, मकई - 5 खण्डी, खोसरा - 30 खण्डी, परबत - एक खण्डी, सरसों - एक खण्डी, रहड़ - 2 खण्डी, कुलथी - 1 खण्डी, बरबटी - 1 खण्डी, मिर्च - 30 किलो, बकरे - 18, सुअर - 2, मुरगे - 2 और 7,750 नगद।

रानीबेड़ा के पटेल दुग्गा पर हमला करके उसकी 30 एकड़ जमीन जब्त करके लोगों में बांट दी गई। इसके अलावा उससे एक दुनाली भरमार बन्दूक भी जनता ने जब्त की।

कमकल के निवासी घसिया पर भी जनता ने हमला किया। इसका एक बेटा छापामार दस्ता सदस्य कॉमरेड राकेश की हत्या में शामिल था जो अब पुलिस में है। जनता ने इसकी करीब 50 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया और उसके चार मकानों को जला दिया। उसके बैलों और सुअरों को जब्त करके उसके पूरे परिवार को गांव से भगा दिया।

इन घटनाओं ने जहां स्थानीय जनता को उत्साहित किया, वहीं इस इलाके के जमींदारों की सबक सिखाया। चूंकि इन सभी लोगों का सम्बन्ध पुलिस वालों के साथ था, इसलिए जनता के इन हमलों से पुलिस के मुंह पर भी कालिख पुत गई। ❑

फिलिप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 9वीं कांग्रेस को कॉमरेडाना बधाई!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्स वार] की होने वाली 9वीं कांग्रेस को फिलिप्पनीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी तहेदिल से जुझारू कॉमरेडाना बधाई देती है। हमें विश्वास है कि इस कांग्रेस के जरिए आप सही सैद्धान्तिक, राजनीतिक और संगठनात्मक लाइन के गिर्द समूची पार्टी को एकजुट करेंगे और इस तरह जनयुद्ध के जरिए नव जनवादी क्रांति के संघर्ष के स्तर को ऊपर उठाएंगे।

दिसम्बर 1999 में भारत के फासीवादियों द्वारा क्रूरता से मारे गए आपा केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. श्याम, कॉ. महेश और कॉ. मुरली को और आपकी पार्टी की स्थापना के बाद भारत की क्रांति एवं विश्व क्रांति के खातिर सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी कॉमरेडों को हम श्रद्धांजली पेश करते हैं। भारत की जनता के अलावा दुनिया भर में मौजूद क्रांतिकारी भी उनकी शहादत को याद करेंगे। हमारे शोक को क्रांतिकारी साहस में तब्दील करेंगे। भारत की क्रांतिकारी जनता आपके शहीदों की मौत का बदला जरूर लेगी। अंतिम विजय तक क्रांतिकारी संघर्ष को जारी रखेगी।

31 सालों के कठिन संघर्षो के जरिए आपने जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] न सिर्फ स्थानीय वर्ग दुश्मनों के खिलाफ, बल्कि पार्टी के भीतर वामपंथी व दक्षिणपंथी भटकावों के खिलाफ तथा देश के अंदर और बाहर भी संशोधनवादियों द्वारा फैलाए जाने वाले दिवालिया सिद्धान्तों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की आग में तपकर सुदृढ़ बन गई।

आपकी जीत की गारन्टी इस बात में है कि आपकी पार्टी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई है। भारत के ठोस हालात में इस सिद्धांत को ठोस रूप से लागू करते हुए आपने भारत का एक अर्ध उपनिवेशी व अर्ध सामंती समाज के रूप में सही विश्लेषण किया; समाजवाद के परिप्रेक्ष्य के साथ नव जनवादी क्रांति की आम दिशा तय की; और देहाती इलाकों से शहरों को घेर लेने की दीर्घकालीन जनयुद्ध की रणनीतिक कार्यदिशा तय की। इस सही क्रांतिकारी कार्यदिशा के गिर्द भारत की जनता गोलबंद हुई और अपनी बहादुर संतानों को संघर्ष के लिए अर्पित किया।

पिछले 20 सालों से आपकी लगातार हो रही प्रगति में निर्णायक आपका यह निर्णय रहा कि आपने हथियारबन्द संघर्ष को संघर्ष के मुख्य स्वरूप के तौर पर स्वीकार किया। इससे आपके दस्तों को विकसित छापामार बलों में विकसित करके जन सेना का निर्माण करने में, छापामार इलाकों और छापामार आधार-क्षेत्रों से विस्तारित और मजबूत मुक्त इलाकों के निर्माण की दिशा में लहर-दर-लहर आगे बढ़ने में आपको मदद मिली।

पार्टी ने हथियारबन्द संघर्ष और संयुक्त मोर्चा - इन दो हथियारों से अपने को लैस किया ताकि क्रांति को आगे बढ़ाया जा सके। दुश्मन पर कड़े प्रहार करते हुए, जन सेना के लिए हथियार जुटाते हुए, जनता के मनोबल और संघर्ष संकल्प को बढ़ाते हुए कार्यनीतिक हमले बढ़ाकर आपने अपने हथियारबन्द संघर्ष में उल्लेखनीय प्रगति की।

आप मजदूर-किसानों की एकता के आधार पर मध्यम वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपतियों को अपनी तरफ कर लेते हुए, प्रतिक्रियावादियों के बीच के अंतरविरोधों का फायदा उठाकर संयुक्त मोर्चे को विकसित कर रहे हैं।

आप देहाती और शहरी इलाकों के लोगों में काफी गहराई से अपनी जड़ें जमा चुके हैं और उनके फौरी और दूरगामी हितों के लिए उन्हें जागृत करने में, संगठित करने में और गोलबन्द करने में कामयाबी प्राप्त कर चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप, भूमि सुधारों, उत्पादन, कृषक व गैर-कृषक मजदूरों के वेतनों में बढ़ोत्तरी आदि में जन-समुदायों ने ठोस उपलब्धियां हासिल कीं। इस तरह पार्टी और जन सेना को विशाल जन-समुदायों का विस्तृत और उत्साहपूर्ण समर्थन मिल रहा है।

शहरी आन्दोलन लाखों लोगों को गोलबन्द करने में सक्षम रहा है ताकि भारत के शासक वर्गों की जन विरोधी एवं साम्राज्यवाद अनुकूल नीतियों का प्रतिरोध किया जा सके। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसे साम्राज्यवादी संगठनों की नव उदारतावादी नीतियों के मातहत ही ये नीतियां बनाई गईं। स्थानीय शासक व्यवस्था का सामाजिक-आर्थिक संकट बद से बदतर हो गया और विशाल जन-समुदायों पर बेहिसाब मुश्किलें लद रही हैं।

क्रांतिकारी हथियारबन्द संघर्ष की बढ़ती मांगों को और क्रांति का विस्तार करने की जबर्दस्त संभावना को देखते हुए, पार्टी की 31वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया किया गया आपका यह आह्वान काफी सही है कि पार्टी को देशव्यापी बेल्शेविक पार्टी में, जो व्यापक जनाधार प्राप्त, जनोन्मुखी और सैद्धान्तिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक तौर पर मजबूत हो, विकसित किया जाए।

भारत एक बड़ा देश है और यहां पर विशाल आबादी है। एशिया के धरातल में भारत एक सामरिक स्थान पर है। भारत में क्रान्ति की प्रगति विश्व सर्वहारा क्रान्ति में काफी महत्व रखती है और उसे प्रभावित करती है।

साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्तियों के इस युग में जनयुद्ध को जारी रखने वाले मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी पार्टियों और आन्दोलनों का महत्व बहुत ज्यादा है। वे राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त को ऊंचा उठाते हुए उसे व्यवहार में लागू करते हैं। वे सशस्त्र क्रान्ति के जरिए विश्व सर्वहारा क्रान्ति को आगे बढ़ाते हैं। आज के विश्व के हालात में, जबकि साम्राज्यवादी और स्थानीय प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग सर्वहारा और जनता के शोषण और उत्पीड़न को बढ़ा रहे हों, वे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावाद के खिलाफ जारी संघर्ष में भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] और फिलिप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी घनिष्ठ हथियारबन्द-संघर्ष के साथी हैं। हमारी जनता को साम्राज्यवादी और स्थानीय प्रतिक्रियावादियों के शोषण-उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए जारी हमारे साझे संघर्ष में हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग और परस्पर समर्थन को दृढ़तापूर्वक जारी रखना चाहिए। और इस तरह विश्व सर्वहारा क्रांति को आगे बढ़ाने में हमारी तरफ से योगदान करना चाहिए।

हम आशा करते हैं कि आप इस कांग्रेस में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल करेंगे। हम आने वाले दिनों में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा-ले) [पीपुल्स वार] की अगुवाई में क्रान्तिकारी सशस्त्र संघर्ष द्वारा महान उपलब्धियों की उम्मीद रखते हैं। हमें विश्वास है कि आप नव जनवादी क्रांति को जीत लेंगे और समाजवादी क्रांति का प्रारम्भ करेंगे।

★ **भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा-ले) [पीपुल्स वार] जिन्दाबाद!**

★ **भारत की क्रान्ति जिन्दाबाद!**

★ **सर्वहारा अन्तरराष्ट्रीयवाद जिन्दाबाद!**

10 फरवरी 2001

केन्द्रीय कमेटी,

फिलिप्पीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी

गोण्डी रिपोर्ट

सीआईडी किन सजा हितोर !

उत्तरबस्तर डिविजन केशकाल एरिया अंतागढ़ रेंज, 'ए' नाटेने जीआरडी तोर वरोर सीआईडीन पोयसी मंजाल दलम तोर किन हितोर। ओरु निब्रा नाटे नोर पटेलना मर्री आंदुर। इद परिवार तोर 5-6 साल्क नल नाटेना जनतान विरोध काम किसोरे मंदुर। इदराम कियाना अस्के नाटे संगठन तोर अनी नाटे नोर बचोको बेरा समझा कितोर, मति ओर केंजोर, उल्टा नाटे नोरकिन डरे किंदुर। अस्के नाटे नोर अनी दलमतोर कलिइसी जनता न मुन्ने पंच किसी पिटाई कितोर। अस्के उचुक दिया बेस मंजी ओसो वेने जनतान अनि दलम तोरकिन विरोध आसी पुलिस तोरा संगे गोती मंजी धोका हियला कोशिश कितोर। पुलिस तोरिन तत्ताना, खबुर हियना किसोरे रावघाट थाना ते विततोर।

अगाडंची सीआईडी काम किसोरे, नाटे-नाटे वेलियसोरे नाटेना समाचार एतना, संगठन तोरा पोरोल तालकना, 'दादा लोर वायना मत्ता वायोरा', इंजी दलम तोरकिन पता किसोरे वेलियाना किन्दुर।

अदरामे तना आड़दुन आटुम तगा केयसी आड़दा संगे वेने समाचार पिंगदुर। अदमे आटुम हत्ता मानेन (सगा जीवा तोरकुन) कलियसी ओर किन जबरदस्ती मीटू दादालोर वातेके माकिन खबुर हियाना इंजी किरिया किया वेहन्दुर। मीटु वायकोम इत्तके तोड़ीय तुन पोयसी किरिया कियाना इंजी किरिया किया वेहन्दुर।

इदराम नाटे-नाटे वेलियाना अस्के 'ए' नाटे नोर संगठन तोर पोयसी मंजाल पिटाई किसी हौक्ला हुड़तोर मति ओना आड़ मंजी ओरकिन डरे किता, मीटु हौक्तेक मिवा पोरो रिपोर्ट हिकान इंजी। संगठन तोर विड़ची तोर। ओसो वेने उचुक दिया न पेरके अदे नाटे ने वातोर अस्के संगठन तोर विचार किसी, इदाड़ वेन विड़चानायो इंजी मीटिंग कितोर। अनि पोयतोर पोयसी दलम एरे मत्ता तची दलम तोरकिन हितोर। दलम तोर ओनक हौक्तुर।

जनतान लोप्पा वेने इदराम तोर किन बस्केन विड़चानायो सजा किसीए विड़चाना इंदाना चेतना वाता। इदिना लोप्पा जीआरडी ता महत्वपूर्ण भूमिका मंता।

पड़िया नेली तुन जनता कब्जा कितोर

उत्तरबस्तर डिविजन कोण्डागांव एरिया कजुंम नाटे सुखबतीना न परोलते 8 एकड़ जमीन मत्ता। सुखबती न कोयतोर हातोर। अदु दूसरा नार हंजी दूसरोनक मर्मी आता। 20 साल्कनल नेली पड़िया मंदाना हुड़सी जनता सुखबती नु तालकतोर, अस्के सुखबती 'इंजे नन्ना वायोन मिटे वीत्ताट' इंजी वेहता। डीएकेएमएस, केएएमएस तोर नार सुलते वीत्ताकाल इंजी विचार कितोर।

मति सुखबती न सग्गा तोर गुलाब वासी सुखबती नाक वीत्ता इंजी वेहता इंजी नाटे नोरकिन डांगतोर। नाटे नोर खत दोसी वीत्ताला जोंग आतोर गुलाब वासी जबरदस्त वीततोर। वीतमा इत्तेक वेने केजोंर। कंजुम नाटेन जनता होंग आसी मंजाल गुलाब वीतले वंजीन पूरा कोयसी ततोर। विस्ता अस्के 30 कंडी वंजी आतां। हैवुर संगे उन्दी वंजी कमेटी पण्डसी 14 कंडी सहकार संगठन हिसाबते तासतोर, 6 कंडी गरीब जनतान तुसीतोर, 10 कंडी विज्जा तुक तासतोर। गुलाब जनता कुन वेरिहतोर, पुलिस तोरकिन वेहकान इंजी। जनता वेने निम्मा पुलिस तोरकिन वेहतेक माटु दादा लोरकि वेहकोम इंजी तेदतोर। जनतान हिम्मत हुड़सी गुलाब वाता हर्री मलसी विततोर।

जनता वेने नेण्ड पुत्तोर जनतान हिम्मत हियना पार्टी मंता इंजी। हरेक समस्या पोरो जनता मुन्ने मंजी लड़े मासोर मंतोर। पुहतोनोनके नेली इंजी दण्डकारण्य आदिवासी गरीब जनता नेण्डू क्रातिकारी संघर्ष लोपा मुन्ने वासोर मंतोर। दण्डकारण्य जनता गला जमीन लेवा जिन्दगी हिले इंजी पुता। दण्डकारण्य आदिवासी जनता पीड़ी-पीड़ी तल सरकार ता काला कानून अडिय दबेमासी पिस्सोर मंता। मति नेंडू दण्डकारण्य जनता मावा असली दुश्मन बोर आंदुर, बोनक मुट्टी कियाना इन्दाना पुत्तोर। उत्तरबस्तर जनता बच्चोवुरो मालगुजारकना पोरो लड़े मासी सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कितोर। अदरामे नेंडू कंजुम नाटे जनता गुलाब न पोरो लड़े मासी मावा नाटे न जमीन माके मंदाना इंजी उंडा ते कमाई किसोर मंतोर। ❑

22 अप्रैल को लेनिन का जन्मदिन और पार्टी का स्थापना दिवस मना

पश्चिम बस्तर डिवीजन के भैरमगढ़ इलाके में जनता ने इस बार 22 अप्रैल को मार्क्सवाद के महान शिक्षक लेनिन का जन्मदिन और पार्टी का 32वां स्थापना दिवस शानदार ढंग से मनाया। भैरमगढ़ रेन्ज के ऊरेपाडू, पिण्डुम, पल्लेवाया, गंगलूर रेंज के पुंबडु, तोडका और बीजापुर रेंज के कमका गांवों में इस अवसर पर आयोजित सभाओं में इन गांवों के अलावा आसपास के गांवों से भी आए हजारों लोगों ने भाग लिया। इसके पहले जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसके बारे में गांव-गांव में पोस्टरों और बैनरों से प्रचार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा आन्दोलन में लेनिन के महत्वपूर्ण योगदान का स्मरण करते हुए लोगों ने उन्हें श्रद्धांजली पेश की। इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि 22 अप्रैल को ही हमारी पार्टी की स्थापना महज इत्तेफाक से नहीं, बल्कि हमारा यह सकल्प दोहराने के लिए भी हुई कि हम लेनिन की विरासत को जारी रखते हैं। हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हुए हमारे देश में नव जनवादी क्रांति को सफल बनाना हमारा प्रमुख कर्तव्य है जो विश्व समाजवादी क्रांति का अभिन्न अंग है। इस तरह ही हम लेनिन के मकसद को पूरा कर सकेंगे और उनके सच्चे वारिस बन सकेंगे। ❑

(.... अंतिम पृष्ठ का शेष)

बावजूद इस क्षेत्र में जन-समुदाय प्रतिरोध को जारी रखे हुए हैं और उमड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

विश्व साम्राज्यवाद, विशेषकर अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित भारतीय विस्तारवादी राज दक्षिण एशियाई जनता का साझा दुश्मन है। यही दक्षिण एशियाई क्रांतिकारी ताकतों की एकता कायम करने के लिए ठोस आधार मुहैया करवाता है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अमरीकी साम्राज्यवाद और भारतीय विस्तारवाद की सांठगांठ को साफ तौर पर देखा जा रहा है।

नेपाल में हाल के घटनाक्रम में इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। भले ही साम्राज्यवादी और उनके पिछलग्गू नेपाल के शाही परिवार के जघन्य नरसंहार के पीछे की असली राजनीति को छुपाने की कोशिश करते हों, लेकिन जनता सचाई को जानती है। नेपाल में नव जनवादी क्रांति और दीर्घकालीन जनयुद्ध के विकासक्रम से यह संकट जुड़ा हुआ है जिसकी परिणति इस हत्याकाण्ड में हुई है। राजा बीरेन्द्र और शाही परिवार का सफाया इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजसत्ता को शासक वर्ग के एक ज्यादा विश्वसनीय फासीवादी और कट्टर तबके के हाथों में सौंपा जा सके जिसे सीपीएन (माओवादी), जनयुद्ध और नेपाली जन-समुदायों के खिलाफ एक सम्पूर्ण प्रति-क्रांतिकारी युद्ध छेड़ने का जिम्मा सौंपा जा सकता है। यह संकट जानबूझकर पैदा किया गया ताकि भारतीय विस्तारवाद के द्वारा बाहरी हस्तक्षेप के लिए अनुकूल हालात बनाए जा सकें, इस आशा में कि नेपाल में माओवादी दीर्घकालीन जनयुद्ध के शोलों को बुझाया जाए। इस हत्याकाण्ड को साफतौर पर अमरीकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवादी राज्य और नेपाली शासक वर्ग के सबसे कट्टर तबकों के बीच हुई साजिश के तहत सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया।

सीपीएन (माओवादी) और जनता यह मानती हैं कि इस हत्याकाण्ड ने परम्परागत राजतंत्र को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया और नेपाल में जनता के जनवादी गणराज्य की स्थापना को जनता के फौरी एजेन्डे में ला खड़ा किया। दक्षिण एशिया के माओवादी पार्टियों और संगठनों की समन्वय समिति (CCOMPOSA) की स्थापना इसलिए की गई ताकि दक्षिण एशिया में माओवादी पार्टियों और संगठनों की गतिविधियों में एकजुटता और समन्वय लाए जा सके, जिससे विश्व सर्वहारा समाजवादी क्रांति को तेजी से आगे बढ़ाने के संदर्भ में इस क्षेत्र में दीर्घकालीन जनयुद्ध को फैलाकर इस विकासशील परिस्थिति का फायदा उठाया जा सके। यह एक व्यापक महत्व वाला ऐतिहासिक कदम है।

यह पहलकदमी सीपीएन (माओवादी) और सीपीआइ (एम-एल) [पीपुल्स वार] द्वारा पेश किए गए विचारों और सुझावों का नतीजा है। इस प्रक्रिया में कोरिम (CoRIM) ने एक सक्रिय भूमिका अदा की।

समन्वय समिति यह प्रस्ताव करती है कि पेरू, फिलिप्पीन्स और तुर्की के दीर्घकालीन जनयुद्धों के साथ-साथ, समूचे क्षेत्र में और उसके आगे दीर्घकालीन जनयुद्ध के शोलों को भड़काने के लक्ष्य से साझे प्रयास करेंगे और क्रांतिकारी संघर्षों को तेज करेंगे। हम प्रस्ताव करते हैं कि संशोधनवाद - दोनों संसदीय और सशस्त्र - को हरा देंगे जो दीर्घकालीन जनयुद्ध को विकसित करने में मुख्य खतरा है। हम हिमालय की चांदी की चोटियों पर तथा समूचे क्षेत्र में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद और साम्यवाद का लाल पताका पूरी शान के साथ लहराने में हमारी सूत्रबद्ध एकता और चेतनापूर्वक दृढ संकल्प को दोहराते हैं। हम साम्राज्यवादी व्यवस्था का सफाया करने और दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ते के जरिए नव जनवादी क्रांति को सफल बनाकर समाजवाद एवं साम्यवाद के हमारे आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए यह जिम्मेदारी उठाते हैं।

हम दक्षिण एशिया की तमाम माओवादी ताकतों से कम्पोसा में शामिल होने की अपील करते हैं ताकि नेपाल और भारत में चल रहे दीर्घकालीन जनयुद्धों का समर्थन कर सके - उन्हें आगे बढ़ा सके तथा दक्षिण एशिया के देशों में नव जनवादी क्रांति की विजय हासिल की जा सके। हम तमाम साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी ताकतों से साम्राज्यवाद और भारतीय विस्तारवाद के खिलाफ उमड़ते जन संघर्षों को मजबूत करने में हमारा समर्थन करने की अपील करते हैं।

हस्ताक्षरित :

बांग्लादेश

1. पूर्ब बांग्ला सर्बहारा पार्टी (सीसी)
2. पूर्ब बांग्ला सर्बहारा पार्टी (माओबादी पुनर्गठन केन्द्र)
3. बांग्लादेश साम्यबादी पार्टी (एम-एल)

भारत

1. माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (एमसीसी)
2. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा-ले) [पीपुल्स वार]
3. रिवॅल्यूशनरी कम्युनिस्ट सेन्टर ऑफ इंडिया (एमएलएम)
4. रिवॅल्यूशनरी कम्युनिस्ट सेन्टर ऑफ इंडिया (मावोइस्ट)

नेपाल

1. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

श्रीलंका

1. सिलोन कम्युनिस्ट पार्टी (मावोइस्ट) ❑

दक्षिण एशिया के माओवादी पार्टियों और संगठनों की समन्वय समिति (CCOMPOSA)

1 जुलाई 2001

प्रेस बयान

हम, यहां नीचे दस्तखत किए दक्षिण एशिया के माओवादी पार्टियां और संगठन **"दक्षिण एशिया के माओवादी पार्टियों और संगठनों की समन्वय समिति (CCOMPOSA)"** की स्थापना की घोषणा करते हुए यह संयुक्त बयान जारी करते हैं:

भूमण्डलीकरण, ढांचागत समायोजन और खुले बाजार की अर्थव्यवस्था के नाम पर विश्व साम्राज्यवाद ने अपने भूमण्डलीय एजेन्डा घोषित किया है ताकि जनता का उत्पीड़न, शोषण और प्रभुत्व को तेज कर सके। यह एजेन्डा विश्व पूंजीवादी संकट की गहराई को प्रतिबिंबित करता है और विश्व स्तर पर और ज्यादा गरीबी, विभीषिका, विनाश और युद्ध की अनिवार्यता बढ़ाता है।

विश्व के सर्वहारा वर्ग और उत्पीड़ित जनता क्रांतिकारी संघर्षों को तेज करके इस एजेन्डा का प्रतिरोध करेंगे। वे साम्राज्यवाद और उसके कठपुतली विभिन्न देशों के प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों से जूझते हुए समूचे विश्व में, खासकर उत्पीड़ित देशों में जन संघर्षों की नई लहर पैदा करेंगे।

जैसे कि माओ ने कहा था, उत्पीड़ित देश विश्व क्रांति के तूफान के केन्द्र होंगे और आज के विश्व में क्रांति ही मुख्य रुझान है। दक्षिण एशिया क्षेत्र इस सचाई की गाढ़ी अभिव्यक्ति करता रहेगा।

दक्षिण एशिया, जहां विश्व की आबादी का पांचवा हिस्सा बसा हुआ है, एक खौलती ज्वालामुखी है, जैसा कि खुद साम्राज्यवादियों ने भी माना। इस क्षेत्र में सभी प्रमुख अंतरविरोध तीखे हो रहे हैं जिनका क्रांतिकारी समाधान करना जरूरी है।

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की प्रेरणा से चारु मजुमदार की अगुवाई में भड़के ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी विद्रोह की चिनगारियों ने दक्षिण एशिया के अलग-अलग क्षेत्रों में दीर्घकालीन जनयुद्ध को सुलगाया। नक्सलबाड़ी का शंखनाद समूचे दक्षिण एशिया और उसके बाहर भी लगातार गूंज रहा है। नेपाल, भारत (आन्ध्र, दण्डकारण्य, बिहार आदि) में आगे बढ़ रहे दीर्घकालीन जनयुद्धों और इस क्षेत्र में हो रही दीर्घकालीन जनयुद्ध की तैयारियों की नींव बुनियादी तौर पर नक्सलबाड़ी वज्रनाद से ही पड़ी।

कश्मीर, असम, नगालैण्ड, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर इलाकों, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन भी चल रहे हैं। साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के खिलाफ विभिन्न जन संघर्ष भी खड़े हो रहे हैं।

नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) - सीपीएन (माओवादी) के नेतृत्व में और भारत में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्स वार] - सीपीआइ (एम-एल) [पीडब्ल्यु] तथा माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र - एमसीसी के नेतृत्व में नव जनवादी क्रांतियों और दीर्घकालीन जनयुद्धों की अप्रधिरोध्य प्रगति दक्षिण एशिया के राजनीतिक भूगोल को और क्रांतिकारी गतिशीलता को बदल रही है। दीर्घकालीन जनयुद्ध की उमड़ती नई लहर को दक्षिण एशिया में साफ देखा जा सकता है। भाजपा के नेतृत्व में भारतीय शासक वर्ग भारत में चल रहे दीर्घकालीन जनयुद्धों और विभिन्न राष्ट्रीयता आन्दोलनों के खिलाफ अपने आक्रामक हमले को तेज कर रहे हैं। इन संघर्षों का दमन करने के लिए विभिन्न ऑपरेशनल इकाइयों का गठन किया गया, और केन्द्र सरकार इन तमाम कार्यवाहियों का सीधा समन्वय कर रही है। भाजपा, जोकि एक हिन्दू धर्मोन्मादी ताकत है, राज को तेजी से एक फासीवादी मशीनरी में तब्दील कर रही है और अपनी तमाम पूर्ववर्ती सरकारों को पीछे छोड़ते हुए भारत में सभी किस्म के जनवादी आन्दोलनों को कुचलने के लिए नित नए काले कानून बना रही है। उपमहाद्वीप के सभी जनांदोलनों का दमन करते हुए, खासतौर पर नेपाल में सशस्त्र हस्तक्षेप की धमकी देते हुए उसने अमरीकी साम्राज्यवाद की ओर से पुलिस की भूमिका अदा करना भी शुरू किया ताकि अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और भूटान के प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग जनता पर तथा जनवादी, प्रगतिशील व माओवादी ताकतों पर फासीवादी दमनचक्र को तेज कर रहे हैं।

बर्बरतापूर्ण फासीवादी दमन के *(शेष पृष्ठ 43 पर ....)*